



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 22, 2017/आषाढ़ 31, 1939

No. 180]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 22, 2017/ ASADHA 31, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटन-रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2017

अंतिम जांच परिणाम

**विषय :** चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय यूनियन, कीनिया, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा एश के आयातों पर लागू पाटन-रोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा जांच (एमटीआर)।

**फा. सं.15/28/2014-डीजीएडी:** समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियम भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

**क. मामले की पृष्ठभूमि**

1. यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय यूनियन, कीनिया, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमरीका (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा एश (जिसे आगे संबद्ध वस्तुएं अथवा विचाराधीन उत्पाद अथवा डाइसोडियम कार्बोनेट भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच के संबंध में दिनांक 17 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या 14/17/2010-डीजीएडी के द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे, जिनमें निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या 34/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी) द्वारा संबद्ध देशों/क्षेत्रों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक शुल्क लगाए गए थे।

2. यतः संबद्ध वस्तुओं के आयातकों/प्रयोक्ताओं के एक प्रतिनिधि निकाय, दि आल इंडिया ग्लास मेन्युफेक्चरर्स फेडरेशन (एआईजीएमएफ) ने सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटन-रोधी शुल्कों की समीक्षा की शुरुआत करने का अनुरोध करने वाला एक आवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह दावा किया है कि मूल जांच की जांच अवधि के दौरान विद्यमान परिस्थितियों में काफी बदलाव आ गया है जिससे ऐसी स्थिति हो गई है जिसमें मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. यतः आवेदक ने यह निवेदन किया है कि संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत में भारी वृद्धि होने के साथ-साथ घरेलू बिक्री कीमत में भी भारी वृद्धि हुई है। साथ ही यह भी निवेदन किया गया है कि प्रमुख कच्ची सामग्रियों की लागत में भी वृद्धि हुई है, लेकिन वह संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की कीमतों में वृद्धि के अनुपात में नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक ने यह भी निवेदन किया है कि आयात कीमतों में भारी वृद्धि के साथ आयातों के पंहुच मूल्य में वृद्धि हुई है, जिसके कारण क्षति मार्जिन में कमी आई है और इसके परिणामस्वरूप शुल्कों के वर्तमान स्तर की समीक्षा करने की जरूरत उत्पन्न हुई है।
4. और यतः अधिनियम 9 क के साथ पठित नियमावली के नियम 23 में ऐसी अपेक्षा है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी जहां आवश्यक हो, वहां स्वयं की पहल पर या किसी हितबद्ध पक्षकार जो ऐसी समीक्षा की जरूरत को सही साबित करने के लिए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, के अनुरोध पर और जब निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क को लगाये जाने से एक तर्क संगत अवधि बीत गई हो, किसी पाटन-रोधी शुल्क को लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षा के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी केन्द्र सरकार से तब उसे हटाने की सिफारिश करेंगे जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि उक्त पाटन-रोधी शुल्क को हटाया या उसमें अंतर किया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और इसलिए इसकी अब आवश्यकता नहीं है।
5. और यतः आवेदक द्वारा प्रदत्त ऐसी सूचना पर विचार करते हुए जिसमें लागू उपायों की समीक्षा करने की आवश्यकता को अधिप्रमाणित किया गया था और प्रथम दृष्टया आवश्यक परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना संख्या 15/28/2014-डीजीएडी द्वारा वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की थी और दिनांक 17 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या 14/17/2010-डीजीएडी द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किया गया था।
6. और यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 16 के अनुसार दिनांक 14.09.2016 को प्रकटन विवरण जारी किए थे और हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां मांगी थी।
7. और यतः प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद दिनांक 23.09.2016 को अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे।
8. और यतः निरमा लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात में वर्तमान मध्यावधि समीक्षा में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिनांक 14.09.2016 के प्रकटन विवरणों को प्रारंभ में चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी और उसके बाद में अपनी रिट याचिका में संशोधन करते हुए उन्होंने दिनांक 23.09.2016 के संबंधित अंतिम जांच परिणाम को भी चुनौती दी थी।
9. और यतः माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात ने दिनांक 23.02.2016 के अपने सामान्य निर्णय द्वारा दिनांक 14.09.2016 के प्रकटन विवरणों को, दिनांक 23.09.2016 के अंतिम जांच परिणामों के साथ-साथ नियमावली के नियम 18 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई परवर्ती अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया था तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी की कार्यवाही को बहाल करने के साथ-साथ उन्हें यह भी निर्देश दिए थे कि वे संबद्ध सांविधिक प्रावधानों के समनुरूप और निर्णय में किए गए प्रेक्षणों के आलोक में नए प्रकटन विवरण जारी करें।
10. और यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 25.04.2017 को अन्य मौखिक सुनवाई आयोजित की थी और हितबद्ध पक्षकारों को अपने मौखिक विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया था। साथ ही हितबद्ध पक्षकारों को लिखित निवेदन प्रस्तुत करने और उसके बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उन पर अपने उत्तर प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया था।

**ख. क्रियाविधि**

11. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित क्रियाविधि का अनुसरण किया गया है:-

- (1) प्राधिकारी ने दिनांक 21 जुलाई, 2015 की जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों तथा उपलब्ध सूचना के अनुसार घरेलू उत्पादकों को भेजी थी। ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत कर दें और अपने विचारों से अवगत करा दें।
- (2) निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावलियों की प्रतियां संबद्ध देशों के दूतावासों को ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ इस अनुरोध के साथ भेजी गई थीं कि वे संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को यह सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत कर दें।
- (3) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र के अगोपनीय वृत्तान्त की प्रति, ज्ञात निर्यातकों, घरेलू उत्पादकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को उपलब्ध करा दी गई थी।
- (4) प्राधिकारी ने मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) को शुरू करने संबंधी सार्वजनिक अधिसूचना की एक प्रति, संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजी थी और नियमावली के नियम 6 (2) और 6 (4) के अनुसार उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने लिखित विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया गया था:-

शानडोंग हाईहुआ ग्रुप, शानडोंग हाईहुआ ग्रुप कंपनी लिमिटेड, डेवलप जोन आफ हाईहुआ बेफेंग सिटी शानडोंग, चीन
क्विंगहाई अल्काली प्लांट (झेझियांग ग्लास चाईनाज क्विंगटल अल्काली प्लांट) झेझियांग ग्लास चाईनाज क्विंगहाई डिलिंगा इंडस्ट्रियल पार्क, जिप : 81700 चीन
जिनशान केमिकल कंपनी, हेनन प्रांत में चाईनाज झेंगझाऊ सिटी, झेंगझाऊ सिटी, फुशोऊशान स्ट्रीट 87, चीन
हेबेई टांगशान सानयु अल काली इंडस्ट्री कंपनी, नानपु डेवलेपमेंट एरिया, टांगशान, हेबेई, चीन
टिआन्जिन सोडा एश प्लांट, नंबर 87 किसनहुआ रोड टंगू, जिला - टिआन्जिन, चीन
सिमान लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स 29, कजानलक एसएल, जगोरा, बल्गारिया-6103
सोल्वाई सोडी एडी, जिप कोड : 9160, बोसनिया और हेरजेगोविना, ब्रूनर मंडे विन्निंगटन लेन, मोंड हाऊस, नोर्थविच, चेशायर, यूके, सीडब्ल्यू 8 4 डीटी
स्पिन इंटरनेशनल, 13 र्यू डे पेस्सी, पेरिस 75016
बेलवेडेरे एसआरएल रोमानिया, सेटेटीआनू लोन, गलाटी, रोमानिया 800198
आशा ट्रेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मंगालियर एनआर 71 बीएल पीआईएस डी एपीटी 36, कोन्सटाना 900116, रोमानिया
जीएचसीएल रोमानिया, जीएचसी अपसोम ओईना म्यूस अल्बा काउंटी, रोमानिया 515700
सिसक्केम सोडे लूकोवेक" दि फर्स्ट स्ट्रीट 1 75300 ल्यूकंवा, बोसानिया और हेरजेगोविना

मगडी सोडा कंपनी, पी ओ बॉक्स 1 - 00206, मगडी, केनिया
अलाईड नेटवर्क कंपनी लिमिटेड, असिली को-ओप हाऊस मोई एवन्यू, नेरोबी, केनिया-72964 00200
एफएमसी इंडस्ट्रियल केमिकल्स, 1735 मार्किट स्ट्रीट, फिलाडेलफिया, पीए 19103, संयुक्त राज्य अमरीका
ओसीआई केमिकल कार्पोरेशन, 1800 वेस्ट ओक कोमन कोर्ट सूट 100, मेरिएट्टा, जीए 30062
सोलावे सोडा एश, मुख्यालय, 5333 रिचमोंड एवन्यू, हाऊसटन, टीएक्स 77098, डाक का पता: पी.ओ. बाक्स 27328, हाऊसटन, टीएक्स 77227
जनरल केमिकल्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, 120 ईगल रोक एवन्यू, ईस्ट हेनोवर, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमरीका
एएनएसएसी, 15 रीवरसाईड एवन्यू, 2सरा तल, वेस्टपोर्ट, सीटी 06880, संयुक्त राज्य अमरीका
एफएमसी कार्पोरेशन, वेल्स फ्रेगो बैंक एन.ए., शेयरओनर सर्विसिज, पी.ओ. बाक्स 64854, सेंट पोल, एमएन 55164-0854, ओआर 161 एन. कोन्कोर्ड एक्सचेंज साअथ इट, पोल, एमएन
सोडा एश, सोडा एश बिजिनेस आईसीआई पाकिस्तान लिमिटेड 63 - मोजांग रोड, लाहौर, पाकिस्तान
ओलम्पिया केमिकल्स लिमिटेड, 23-डेविस रोड, लाहौर, पाकिस्तान
सिरिना ट्रेड कंपनी, अरुम्स 88 आफिस 25 ला, डोनेट्सक, यूक्रेन

- (5) वर्तमान जांच शुरू करने के उत्तर में तुर्की के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं और निवेदन किए हैं:-

(1) ओलम्पिया केमिकल्स लिमिटेड, पाकिस्तान
(2) आईसीआई पाकिस्तान लिमिटेड, पाकिस्तान

- (6) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:-

गुजरात गारजियन लिमिटेड, ग्राम - कोंध, वालिया रोड, प्लांट स्टेट हाईवे नंबर 13, अंकलेश्वर, भडौच - 393001
फ्लोट ग्लास इंडिया लिमिटेड, टी-7 मिडक, इंडस्ट्रियल एरिया, टालोजा, महाराष्ट्र।
हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिशरा, पश्चिम बंगाल।
प्रोक्टर एंड गेम्बल हाईजीन एंड हेल्थ केयर, मंडीदीप प्लांट एलएंडसी-एमएफजी, प्लाट नंबर 182, मंडीदीप, मध्य प्रदेश।
एडवाटेज इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, धनाली, ग्राम - धनाली, अल-कादिल जिला, मेहसाना, गुजरात।
यू.पी.ग्लास मैनुफैक्चरर्स, सिंडीकेट, 14- मोनापुरम, निकटस्थ गणेश नगर - फिरोजाबाद - 283203, उत्तर प्रदेश।

फेना (प्राईवेट) लिमिटेड, ए-237 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-20
पोल्लाची चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री , आर पी काम्पलेक्स , दूसरा तल, 14, बालागोपालापुरम स्ट्रीट, पोल्लाची-642001
पावर सोप लिमिटेड , 62-बी, नॉर्थ बोआग रोड, टी. नगर, चेन्नई-600017
अलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अलेम्बिक रोड, बडोदा (बदोदरा) गुजरात।
दीपक नाईट्राईट लिमिटेड, 4/12, केमिकल कॉम्पलेक्स, जीआईडीसी, नानफेसारी, बडौदा (बदोदरा) गुजरात।
हिन्दुस्तान यूनीलाईव लिमिटेड, पार्टी का पता, दक्षिण बिल्डिंग, 8वां तल, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई।
अल्ट्राईट मोरारजी एंड पंडित लिमिटेड, अम्बेरनाथ, जिला - थाणे, महाराष्ट्र।
सेंट-गोवार्डन ग्लास इंडिया, मुख्यालय और संयंत्र: ए-1 सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क, श्रीपेरुम्बदुर-602105, कांची पुरम जिला, तमिलनाडु।
आशी इंडिया ग्लास लिमिटेड , 5वां तल, टावर-बी, ग्लोबल बिजिनेस पार्क, महारौली-गुरुग्राम रोड, गुरुग्राम-122002 (भारत)।
श्री यूनियन आर्गेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड, वीएस-3, अपीजे, 130 बम्बई समाचार मार्ग, मुंबई-23
वसुन्धरा रसायन लिमिटेड, सी-104, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, माहेड, जिला - रायगड, महाराष्ट्र।
शान्तिनाथ डिटरजेंट प्राईवेट लिमिटेड, पी-15, कलाकार स्ट्रीट, कोलकाता-700007
एडवांस होम एंड पर्सनल केयर प्राईवेट लिमिटेड, एडवांस सर्फेक्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, 511/2/1, ग्राम - रजोकडी, नई दिल्ली-38
एस कुमार डिटरजेंट प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 34, सेक्टर-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पीथमपुर-454775, जिला - धार, मध्य प्रदेश।
हिन्द सिल्केट्स प्राईवेट लिमिटेड, 3ए, ऑकलैंड प्लेस, 5वां तल, कोलकाता-17
पी एंड जे क्रेटकेम (प्राईवेट) लिमिटेड, 318, स्वपन लोक, 92/93, एसडी रोड, सिकन्दराबाद-500003, आन्ध्र प्रदेश (भारत)।
जे.जे. पटेल इंडस्ट्रीज, गोंडल रोड, बी/एच राजकमल पेट्रोल पम्प, वावडी, राजकोट-360004
माडर्न ग्लास इंडस्ट्रीज, कोल साईडिंग रोड, एस.एन. रोड, फिरोजाबाद-283203
सन्दीप आर्गेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड, 104, नैन कूपा, 118/122, काजी सईद स्ट्रीट, मस्जिद बंदर (पश्चिम), वाडगाडी, मुंबई-400003
एलंबिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एलंबिक रोड, बडौदा (बदोदरा) गुजरात।
रोहित सर्फेक्टेन्स (प्राईवेट) लिमिटेड, 117/एच-2/202, पांडु नगर, कानपुर-05

बीडीजे ग्लास इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, 1 कईद स्ट्रीट, प्लेस कोर्ट, 1ला तल, सूट-14-ए, कोलकाता-700016
जगजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्लॉट नंबर 78, सेक्टर-18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001
हिल्डन ग्लास गुजरात लिमिटेड, 9, गायत्री कमर्सियल काम्पलेक्स, मित्तल इंडस्ट्रियल एरिया इस्टेट नंबर 5 के पीछे, अंधेरी रोड, मारोल नाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059
हिपोलीन लिमिटेड, मधुवन, 4था तल, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006
मॉडर्न ग्लास इंडस्ट्रीज, कोल सार्डिंग रोड, एस.एन. रोड, फिरोजाबाद-283203
डिटरजेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (दिल्ली क्षेत्र), 148, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स-1, नई दिल्ली-110020
मौली एक्सपोर्ट्स, प्लॉट नंबर 97-98, सेक्टर-25, पार्ट-2, इंडस्ट्रियल एरिया, हूडा, पानीपत-132104 (हरियाणा)।
मेसर्स चेम्पेक्स इंटरनेशनल, 393/III/6 बाजेर, बीकानेरियन, कटरा, आहलूवालिया, अमृतसर, पंजाब।
टाटा केमिकल्स लिमिटेड, लीला बिजनेस पार्क, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-59
मेसर्स टूटीकोरिन अल्काली केमिकल्स एंड फर्टलाइजर्स लिमिटेड, 534, अन्ना सलई, तेईनामपेट, चेन्नई-18
एजीआई ग्लासपेक, ग्लास फैक्टरी रोड, मोती नगर, पोस्ट बाक्स 1030, शांत नगर, हैदराबाद-500018
पावर सोप्स लिमिटेड, ए-8 प्रथम मेन रोड, अम्बाटुर इंडस्ट्रियल इस्टेट, चैन्नई-600 058
हिंडकोन केमिकल्स (प्राईवेट) लिमिटेड, 62/बी, ब्रोनफ्लेड रोड, 1ला तल, कोलकाता-700 027
एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एम्पायर हाऊस, 414, सेनापति बापत, लोअर पारेल, मुंबई-13

- (7) उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं और निवेदन किए हैं:-

(क)	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
(ख)	गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड
(ग)	एचएनजी फ्लोट ग्लास लिमिटेड
(घ)	एचएसआईएल लिमिटेड, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स डिवीजन
(ङ)	ला ओपेला आर जी लिमिटेड
(च)	पीरामल ग्लास लिमिटेड

- (8) आवश्यक सूचना मंगाने और उत्तर प्राप्त करने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात घरेलू उत्पादकों को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:-

मेसर्ज डीसीडब्ल्यू लिमिटेड
मेसर्ज जीएचसीएल लिमिटेड
मेसर्ज निरमा लिमिटेड
मेसर्ज सोराष्ट्र केमिकल्स लिमिटेड
टाटा केमिकल्स लिमिटेड

(9) जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना निम्नलिखित एसोसिएशनों को भेजी गई थी:-

डिटरजेंट मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (दिल्ली क्षेत्र)
इंडियन केमिकल मर्चेन्ट्स एंड मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन
बल्क ड्रग मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (इंडिया)
इंडियन ग्लास मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन
दि डायर्स एंड केमिकल मर्चेन्ट्स एसोसिएशन
आल इंडिया ग्लास मैन्युफेक्चरर्स फेडरेशन
अल्काली मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया
इंडियन सोप्स एंड टोइलेटरीज मेकर्स एसोसिएशन

(10) विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उत्पादकों और उनके प्रतिनिधियों के अतिरिक्त निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों और हितबद्ध पक्षकारों ने भी इस जांच के दौरान अपने निवेदन प्रस्तुत किए हैं:-

1.	डिटरजेंट मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया
2.	डिटरजेंट मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (दिल्ली क्षेत्र)
3.	बंगाल सोप्स एंड डिटरजेंट्स मैन्युफेक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन
4.	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
5.	संदीप आर्गेनिक्स लिमिटेड
6.	आरएसपीएल लिमिटेड
7.	अशोका इनेमल एंड ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
8.	इंडियन काउंसिल आफ स्माल इंडस्ट्रीज
9.	आल इंडिया ग्लास मैन्युफेक्चरर्स फेडरेशन
10.	सेंट गोबार्डन ग्लास इंडिया लिमिटेड

- (11) जिन विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उन्होंने इस जांच से संबद्ध कोई सूचना प्रस्तुत की है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।
- (12) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से अनुरोध किया गया था कि वे जाँच अवधि और विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विस्तृत आकड़े उपलब्ध कराएं। इसलिए प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा का परिकलन करने और आवश्यक विश्लेषण करने के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- (13) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और निर्माण और बिक्री की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत का आकलन किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यदि पाटन-रोधी शुल्क, पाटन मार्जिन से कम लगाया जाता है, तो क्या वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (14) मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि, 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक (जांच अवधि) है। तथापि, क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और जांच की अवधि (पीओआई) शामिल है। प्राधिकारी ने संभावित विश्लेषण करने के लिए जांच अवधि पश्चात की अवधि (1 अप्रैल, 2015 से 30 सितंबर, 2015) के लिए भी हितबद्ध पक्षकारों से संबद्ध सूचना/आंकड़े मंगाए थे। प्राधिकारी ने संभावित विश्लेषण को और अधिक पूरा करने के लिए डी जी सी आई एंड एस से जांच की अवधि के बाद के संबंध में और आंकड़े भी प्राप्त किए।
- (15) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को अपने मौखिक विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए 2 मार्च, 2016 को एक सार्वजनिक सुनवाई की थी। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने इस सार्वजनिक सुनवाई के समय अपने मौखिक विचार प्रस्तुत किए थे, उनसे अनुरोध किया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें और साथ ही अपने प्रत्युत्तर भी दें।
- (16) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (6) और उच्च न्यायालय, गुजरात के निर्णय के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को अपने मौखिक विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए 25 अप्रैल, 2017 को एक सार्वजनिक सुनवाई की थी। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने इस सार्वजनिक सुनवाई के समय अपने मौखिक विचार प्रस्तुत किए थे, उनसे अनुरोध किया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें और साथ ही अपने प्रत्युत्तर भी दें।
- (17) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें।
- (18) उपरोक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा 7 जून, 2017 को जारी किए गए प्रकटन विवरण द्वारा ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को जांच के अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन कर दिया गया था और उन पर टिप्पणियां प्राप्त हो गई थी, जिन पर प्राधिकारी द्वारा यथा संभव विचार किया गया है और इस जांच परिणाम में उनकी जांच की गई है तथा समाधान किया गया है। पूर्व के 14.9.2016 के प्रकटन विवरण को माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
- (19) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांच की कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अत्यधिक अडचने डाली हैं, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपना निर्णय रिकार्ड किया है।



- (20) किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा \*\*\* सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है।
- (21) प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच अवधि के दौरान प्रचलित औसत विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 61.69 रूपए है।

**ग. विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र और "समान वस्तु"**

12. मूल जांच के साथ-साथ वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद "सोडा एश" है। मूल जांच में उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"1. विचाराधीन उत्पाद डाइसोडियम कार्बोनेट है जिसे आम तौर पर सोडा एश के रूप में जाना जाता है जिसका रासायनिक सूत्र  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  है। सोडा एश एक सफेद, क्रिस्टलीय, जल में विलेय पदार्थ है। सोडा एश दो रूपों – लाइट सोडा एश और डेंस सोडा एश में उत्पादित किया जाता है। दो किस्मों में अंतर बल्क घनत्व का है। इसके अलावा, सोडा एश या तो प्राकृतिक सोडा एश या कृत्रिम सोडा एश हो सकता है। दोनों उत्पाद अनिवार्यतः समान हैं। तथापि, वर्तमान जांच में सोडा एश के सभी प्रकार और रूप शामिल हैं।

2. सोडा एश डिटरजेंट, साबुनों, क्लीनिंग कंपाउंड, सोडियम आधारित रसायनों, फ्लोट ग्लास, कंटेनर और विशेष ग्लासों, सिलिकेट और अन्य औद्योगिक रसायनों के विनिर्माण में अनिवार्य अवयव है। इसका प्रयोग वस्त्र, कागज, धातु निष्कर्षण उद्योगों और डिसेलीनेशन संयंत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है। सोडा एश को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत सीमा-शुल्क उप-शीर्ष संख्या 2836.20 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह सीमा-शुल्क का यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच पर बाध्यकारी नहीं है।

13. विचाराधीन उत्पाद/समान वस्तु के संबंध में किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई टिप्पणी अथवा निवेदन नहीं किया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र वही बना रहेगा, जो कि मूल जांच में था।

**ग. घरेलू उद्योग और उसका आधार**

**याचिकादाता और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन**

14. घरेलू उद्योग के आधार और उसके कार्य-क्षेत्र के बारे में याचिकादाता और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) संबंधित घरेलू उत्पादक स्वयं को घरेलू उद्योग होने का दावा कर रहे हैं, जबकि वे संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के बड़े आयातक हैं। कुछ घरेलू उत्पादकों के पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों ने काफी मात्रा में भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए हैं। घरेलू उत्पादकों ने विशेष रूप से यह स्वीकार किया है कि वे दक्षिणी और पूर्वी भारत के ग्राहकों को आपूर्ति करने के लिए मुख्यतया आयातों पर विश्वास करते हैं। इसलिए पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार ऐसे घरेलू उत्पादक, घरेलू उद्योग बनने के पात्र नहीं हैं।
- (2) भारत के सबसे बड़े घरेलू उत्पादक नामतः "टाटा केमिकल्स लिमिटेड" ने केनिया में स्थित अपनी सहायक कंपनी से तथा यूरोपीय यूनियन और चीन से असंबंधित उत्पादकों से सामग्री आयात की है।
- (3) निरमा की अन्य देशों में उसके पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियां हैं और वह इन कंपनियों के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का आयात कर रही है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को इसकी जांच करनी चाहिए कि क्या आयात की कम कीमत की प्रतिपूर्ति निरमा द्वारा प्राप्त कीमत से की जा सकती है।
- (4) जीएचसीएल भी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों से आयात कर रही है। जांच अवधि में जीएचसीएल ने 87% से भी अधिक क्षमता उपयोग किया है, जो कि इन उद्योगों के लिए अधिकतम है। जीएचसीएल 8,50,000 मी.टन की क्षमता वाली प्रमुख उत्पादक है

और उसकी संबद्ध देशों सहित विभिन्न देशोंसे संबद्ध वस्तुओं का आयात करने की बाध्यता है। वह संबद्ध वस्तुओं का आयात करने के समय पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान कर रही है और फिर भी वह लाभ अर्जित कर रही है।

- (5) सौराष्ट्र केमिकल्स लिमिटेड (एससीएल) को पहले से ही निरमा में समामेलित कर दिया गया है और वह अब पृथक कानूनी प्रयोज्यता/कंपनी नहीं है।
- (6) टूटीकोरिन अल्काली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड उत्पादन की दृष्टि से घरेलू उत्पादकों की बहुत छोटी और अत्यधिक अकुशल सदस्य है। इसने अपना उत्पादन फिर स्थगित कर दिया है और इसने ऐसा कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण किया है।
- (7) केवल डीसीडब्ल्यू ही ऐसी उत्पादक कंपनी है, जिसकी प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता 3,00,000 मी.टन है। यह कंपनी उच्चतर स्तर पर क्षमता का उपयोग कर रही है और लाभ अर्जित कर रही है। ऐसी कंपनी निरंतर संरक्षण प्राप्त करने की हकदार नहीं है।
- (8) न कथित घरेलू उद्योग ने और न ही प्राधिकारी ने इसका स्पष्ट किया है कि पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार कौन घरेलू उत्पादक "घरेलू उद्योग" बनता है।

#### घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

15. घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) याचिकादाता ने घरेलू उद्योग को अभिज्ञात नहीं किया है। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने का आवेदन-पत्र तब तक अपूर्ण है जब तक कि आवेदक को घरेलू उद्योग अभिज्ञात नहीं किया गया है, विशेषकर जब कि आरोप यह है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। जांच की समस्त कार्यवाई को इस कारणवश समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- (2) जीएचसीएल और टाटा केमिकल्स को छोड़ कर किसी भी कंपनी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का स्वयं आयात नहीं किया है।
- (3) जीएचसीएल ने आयात केवल बाजार में उपस्थिति बनाए रखने के लिए किया था, ताकि बृहत्त क्षमता की उपलब्धता में वह निरंतरता बनाए रख सके।
- (4) जीएचसीएल की रोमानिया में एक संबद्ध कंपनी है जो कि अब बंद पड़ी हुई है। निरमा का एक संबंधित उत्पादक संयुक्त राज्य अमरीका में है, जिसने जांच अवधि के दौरान भारत को सोडा एश का निर्यात किया था। तथापि, संयुक्त राज्य अमरीका में स्थित इस संबंधित कंपनी द्वारा सीधे निर्यात किए जा रहे हैं।
- (5) डीसीडब्ल्यू की भारत से बाहर कोई संबंधित उत्पादक - निर्यातक नहीं है।
- (6) टाटा केमिकल्स के संबंधित उत्पादक कीनियां, संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोप में स्थित हैं। टाटा केमिकल्स केनिया में एक सहायक कंपनी है, जिसने भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए हैं। ऐसे निर्यात टाटा केमिकल्स द्वारा सीधे किए गए हैं। यदि आवश्यक समझा जाता है, तो टीसीएल को एक अपात्र घरेलू उद्योग माना जा सकता है।
- (7) घरेलू उद्योग द्वारा आयात करने के अनेक कारण हैं। प्रथमतः पहुंच कीमत, वास्तव में उस कीमत से कम है, जिस पर घरेलू उद्योग इन क्षेत्रों में बिक्री कर सकता है। द्वितीय निकट भविष्य में क्षमताओं का विस्तार करने के लिए मांग का पूर्व सृजन किए जाने की आवश्यकता है, जो कि इन उपभोक्ताओं को आयातित उत्पाद की आपूर्ति करके की जा रही है। तृतीय इन आयातों पर बहुत मामलू लाभ अर्जित किया गया है। चतुर्थ भांड को शामिल किए बगैर शुल्कों की सिफारिश की गई थी, जिसे उचित प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया जाना चाहिए।
- (8) पाटन-रोधी शुल्क निष्पक्ष आधार पर हैं और यदि घरेलू उत्पादकों ने विचाराधीन उत्पाद के आयात किए हैं, तो उन्होंने उन पर पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान किया है।

- (9) मौखिक सुनवाई के निष्प्रभावी होने के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यह आवेदक आयातक एसोसिएशन का दायित्व था कि वह घरेलू उद्योग को अभिज्ञात करे और उसके बाद क्षति नहीं होने और उसकी कोई संभावना नहीं होने को सिद्ध करे।
- (10) निरमा की दर्शाई गई क्षमता, एससीएल की क्षमता के साथ है। क्षति अवधि के प्रारंभ में एससीएल एक पृथक प्रयोज्यता थी और बाद में उसे निरमा के साथ समामेलित कर दिया गया था। निरमा की सूचना में एससीएल की सूचना भी निहित है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

16. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

*“(ख) घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”*

17. पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में यह प्रावधान है कि ऐसे घरेलू उत्पादकों को, जो कि ऐसे निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हैं, जो स्वयं पाटित वस्तुओं के आयातक हैं, घरेलू उद्योग का निर्धारण करते समय बहिष्कृत किया जा सकता है। प्राधिकारी का यह विचारित मत है कि नियम 2 (ख) में “सकता” शब्द का अभिप्राय दो किस्मों के उत्पादकों से है, अर्थात् संबंधित उत्पादक और पाटित उत्पाद का आयात करने वाला उत्पादक, जिन्हें घरेलू उद्योग के एक भाग में से स्वतः बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत ऐसी सुसंगत पद्धति है कि ऐसे उत्पादकों का बहिष्करण करने का निर्णय अलग-अलग मामले के आधार पर किया जाता है, जिसके कारण सामान्य आधार पर हों और उसके लिए उसमें निहित सभी कानूनी और आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जाए।

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में भी कुछ घरेलू उत्पादक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात करने में लिप्त थे अथवा वे संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों/आयातकों से संबंधित थे। मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और उसके आधार का सपष्ट रूप से समाधान किया है। प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के साथ पठित नियम 5 (3) के अनुसार जीएचसीएल, निरमा लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड को “घरेलू उद्योग” के रूप में माना है। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने मूल जांच के समय किए गए निष्कर्ष को स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

### **घ. विविध निवेदन**

19. आवेदक और अन्य विविध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) घरेलू उद्योग ने मध्यावधि समीक्षा के उत्तर में अपनी किसी परिश्रमता का उपयोग नहीं दिया है अथवा एमटीआर का उत्तर देने के लिए प्रदत्त आंकड़ों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सावधानी नहीं बरती है और जहां तक कि उसने परिशुद्धता का आवश्यक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है।
- (2) भाडे को शामिल करने का दावा कानूनी रूप से तर्क संगत नहीं है और वास्तव में दोहराए जाने (रेस-ज्यूडिकाटो) का सिद्धांत इस मुद्दे पर लागू होता है क्योंकि घरेलू उद्योग ने एक बार फिर प्राधिकारी के समक्ष यह दबाव डाला है, जो कि उसने मूल जांच में भी किया था और प्राधिकारी ने उसे अस्वीकृत कर दिया था।
- (3) घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई में प्रतिवादियों द्वारा किए गए निवेदनों का खंडन नहीं किया था और “गैर-अनुपस्थिति के सिद्धांत” को ध्यान में रखते हुए यह माना जाता है कि घरेलू उद्योग ने ऐसे निवेदनों को स्वीकार कर लिया था।
- (4) दो मध्यावधि समीक्षाओं को एक साथ संयोजित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उत्पादकों की संरचना के साथ-साथ जांच की अवधि भी समान है।

- (5) जैसा कि विगत जांच में परिभाषित किया गया है, घरेलू उद्योग को घरेलू उद्योग माना जाएगा। केवल घरेलू उत्पादक ही हैं, जो कि इस संबंध में स्वयं सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं और न कि आवेदक। आवेदक के लिए घरेलू उद्योग को अभिज्ञात करने और आरोप लगाने के लिए पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 (1क) के अंतर्गत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।
- (6) चूंकि भाड़े को शामिल करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिकाएं और अपील उच्च न्यायालय और सेस्टेट में विचाराधीन हैं, इसलिए प्राधिकारी को क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के संबंध में अपनी सुस्थापित पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए और क्षति रहित कीमत का निर्धारण करते समय अंतरदेशीय भाड़े को निरंतर शामिल नहीं करना चाहिए। भाड़े को शामिल करने/शामिल नहीं करने के मुद्दे पर निर्णय तभी लिया जाए, जब उच्च न्यायालय अथवा सेस्टेट द्वारा इसका समाधान अंतिम रूप से कर दिया जाए।
- (7) चूंकि घरेलू उद्योग क्षमताएं होने के बावजूद भी आपूर्ति करने में असमर्थ है, घरेलू बाजार में मांग-आपूर्ति में अंतर व्याप्त है।
- (8) भारत में हजारों की संख्या में छोटे, लघु और मध्यम वर्ग के डिटरजेंट उत्पादक हैं, जो कि जनता को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। डिटरजेंटों की प्रमुख कच्ची सामग्री, सोडा एश पर लागू पाटन-रोधी शुल्क के कारण उनको कठिनाई हो सकती है। मांग और पूर्ति के बीच व्याप्त अंतर के कारण घरेलू उद्योग द्वारा आवश्यक मात्रा में आपूर्ति नहीं किए जाने से इन उद्योगों को पाटन-रोधी शुल्क का वहन करते हुए आयातित सामग्री पर निर्भर करने के लिए विवश होना पड़ता है, जिससे उनकी उत्पादों की लागत निष्प्रभावी हो जाती है।
- (9) कीमत निर्धारण के संबंध में सोडा एश के घरेलू उत्पादकों के बीच पारस्परिक समझौता है, जिससे निचले स्तर तक के उद्योगों की लागत पर कार्टेलाइजेशन हो जाता है।
- (10) संबद्ध वस्तुएं लागत लेखाकरण रिकार्ड नियमावली (सीएआर) के अंतर्गत शामिल हैं। इसलिए घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत पर सीएआर के आधार पर विचार किया जाए। इसलिए प्राधिकारी को सीएआर के आधार पर घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत (सीओपी) पर विचार करना चाहिए और यदि यह पहले से उपलब्ध नहीं है, तो प्राधिकारी संबद्ध सूचना मंगा सकते हैं।
- (11) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। निबल अचल परिसम्पत्तियों जैसी नियोजित पूंजी और कार्यशील पूंजी के संबंध में चुनिन्दा सूचना ही प्रदान की गई है, जबकि निर्धारित प्रपत्र में विशिष्ट अवधि के लिए लेखा बहियों के आधार पर नियोजित पूंजी की सूचना देने की आवश्यकता होती है।
- (12) नियम 23 के अनुसार मध्यावधि समीक्षा में पाटन मार्जिन अप्रासंगिक है क्योंकि जहां घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने अथवा उसकी आवृत्ति होने की संभावना नहीं है, वहां शुल्क को समाप्त किया जा सकता है। जहां तक कि शुल्क के जारी रहने की स्थिति में भी सकारात्मक पाटन मार्जिन को यथोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

#### **घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन**

20. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) याचिका अपूर्ण है क्योंकि उसमें "घरेलू उद्योग" को सिद्ध किए बिना ही क्षति नहीं होने का दावा किया गया है।
- (2) याचिका यह सिद्ध नहीं करती है कि पाटन-रोधी शुल्क को क्यों समाप्त करने की आवश्यकता है। मध्यावधि समीक्षा का उद्देश्य इसका विश्लेषण करना है कि क्या शुल्क को समय से पूर्व समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- (3) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे प्राधिकारी द्वारा सामान्यतया लागू की जाने वाली और जो कि मूल जांच के दौरान लागू की गई थी, क्षति मार्जिन का निर्धारण करने की कार्य-प्रणाली और साथ ही वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उसके औचित्य और उपयुक्तता के संबंध में घरेलू उद्योग के निवेदनों पर विचार करें। क्षति रहित कीमत के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-III के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों का पहले अनुपालन किया जा रहा था और विधि के शुरू होने से पहले भी प्राधिकारी द्वारा उनका अनुसरण किया जा रहा था।

- (4) स्थाई विवरण में कंपनी-वार ब्यौरे निहित होने के कारण स्थाई तालिका और क्षति विवरण में उत्पादन के आंकड़ों में अंतर होने के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि यह एक लिपिकीय त्रुटि थी, जिसका खेद है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि इसके कारण हितबद्ध पक्षकारों को गंभीर क्षति हो सकती है, यदि शुल्कों को समाप्त कर दिए जाएं।
- (5) प्रस्तुत की गई सूचना की परिशुद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की कोई निर्धारित आवश्यकता नहीं है। घरेलू उद्योग को उसके कानूनी संरक्षण से वंचित करके, लिपिकीय मानवीय त्रुटियों के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता है।
- (6) हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग भाडे के कारण दक्षिण में आपूर्ति करने के लिए इच्छुक नहीं है, यह निवेदन है कि पहले घरेलू उद्योग ने किसी भी उपभोक्ता को कोई भी सामग्री देने से मनाही नहीं की है और दूसरे इससे ऐसा पता चलता है कि क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए भाडे को मान्यता दी जा सकती है।
- (7) "गैर-अनुप्रस्थ के सिद्धांत" पर विश्वास इसलिए निराधार है क्योंकि जब कोई निवेदन किया जाता है, तो सुनी हुई बात का कोई अर्थ होता है तथा अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का उत्तर दिया जा सकता है।
- (8) घरेलू उद्योग को दो मध्यावधि समीक्षाओं के संचयन के प्रति कोई आपत्ति नहीं है। तथापि, इससे जांच शुरू करना अवैध हो जाएगा और फिर से नई मध्यावधि जांच शुरू करने की आवश्यकता होगी।
- (9) विश्व बाजार जिसमें बेशी विद्यमान है की तुलना में भारत में सोडा एश के उत्पादन की कमी है। एक प्रमुख डिटरजेंट विनिर्माता, आरएसपीएल लिमिटेड केप्टिव खपत और घरेलू बाजार में बिक्री करने के लिए 5 लाख मी.टन की उत्पादन क्षमता के साथ भारत में एक सोडा एश संयंत्र की स्थापना कर रही है। इस क्षेत्र में उसके प्रवेश करने से भारत सोडा एश में आत्म निर्भर बन जाएगा। यदि वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है और कीमतों में गिरावट हो जाती है, तो आरएसपीएल को क्षति होगी। इसलिए वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर जारी रखा जाना चाहिए।
- (10) प्राधिकारी को केवल उन्हीं मामलों में क्षति मार्जिन निर्धारित करने की आवश्यकता है, जिनमें निर्दिष्ट प्राधिकारी यह पाते हैं कि आयातों के कारण क्षति हो रही है - चाहे वह नया मामला है अथवा मध्यावधि समीक्षा अथवा निर्णायक समीक्षा जांच है। यदि परिणाम संभावना के आधार पर है, तो क्षति मार्जिन का निर्धारण नहीं किया जाए और जैसा कि प्राधिकारी की पद्धति रही है, पाटन-रोधी शुल्क की विद्यमान मात्रा की ही संपुष्टि की जाए।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

21. पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:-

*'(1) अधिनियम की धारा 9 क के उपबंध के अंतर्गत लगाया गया कोई पाटन-रोधी शुल्क क्षति पहुंचाने वाले पाटन की प्रतिपूर्ति करने की समयावधि तक और उसकी आवश्यक सीमा तक लागू रहेगा।*

*(1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी जहां आवश्यक हो, वहां स्वयं की पहल पर या किसी हितबद्ध पक्षकार जो ऐसी समीक्षा की जरूरत को सही साबित करने के लिए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है के अनुरोध पर और जब निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क को लगाये जाने से एक तर्कसंगत अवधि बीत गई हो, किसी पाटन-रोधी शुल्क को लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षा के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी केन्द्र सरकार से तब उसे हटाने की सिफारिश करेंगे जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि उक्त पाटन-रोधी शुल्क को हटाया या उसमें अंतर किया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और इसलिए इसकी अब आवश्यकता नहीं है।*

*(1ख) उपरोक्त उप-नियम (1) और (1क) में निहित किसी भी व्यवस्था के बावजूद अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई भी सुनिश्चित पाटन-रोधी शुल्क, उसको लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि तक तब तक लागू रहेगा, जब तक कि उस अवधि से पहले निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वयं अपनी पहल पर अथवा घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत् अधिप्रमाणित अनुरोध पर उक्त अवधि के समाप्त होने से पर्याप्त समय पूर्व शुरू की गई समीक्षा जांच में यह निष्कर्ष नहीं देते हैं कि उक्त पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।*

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत शुरू की गई कोई समीक्षा ऐसी समीक्षा की शुरुआत की तारीख से 12 माह से अधिक अवधि के भीतर संपन्न की जाएगी।

(3) नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, तथा 20 के उपबंध समीक्षा के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

22. पाटन करार के अनुच्छेद 11.2 में यह प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वयं अपनी पहल पर अथवा किसी हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर जो कि समीक्षा की आवश्यकता की संपुष्टि करने की सकारात्मक सूचना के साथ ऐसा निवेदन करता है, शुल्क को जहां उसकी आवश्यकता है, निरंतर लागू रखे जाने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे अथवा बशर्ते कि निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क को लागू करने के बाद ऐसी समीक्षा करने का उचित समय हो गया है। हितबद्ध पक्षकारों का प्राधिकारियों से यह अनुरोध करने का अधिकार होगा कि वे इसकी जांच करें कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है अथवा यदि पाटन रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है अथवा उसमें परिवर्तन किया जाता है अथवा दोनों किए जाते हैं, तो क्या क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। यदि इस पैराग्राफ के अंतर्गत समीक्षा के परिणामस्वरूप प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क की अब कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसे तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।

23. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि मध्यावधि समीक्षाओं का कार्य-क्षेत्र, निर्णायक समीक्षा जांच से भिन्न होता है। आवेदक ने यह भी तर्क दिया है कि मध्यावधि समीक्षा में डीजीएडी को इस पर विचार करने और इसका निर्धारण करने की आवश्यकता होती है कि क्या पांच वर्ष के समाप्त होने से पहले पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने का पर्याप्त औचित्य है, जबकि निर्णायक समीक्षा जांच में डीजीएडी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि पांच वर्ष की समाप्ति पर क्या पाटन-रोधी शुल्क को आगे बढ़ाए जाने का आवश्यकता है अथवा नहीं। घरेलू उद्योग ने भी यह तर्क दिया है कि मध्यावधि समीक्षा में वर्तमान निष्पादन ही यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त होता है कि क्या ऐसी स्थिति में पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त किया जा सकता है और यह कि प्राधिकारी को ऐसी संभावित स्थिति पर विचार करने की आवश्यकता होती है, जो कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर उत्पन्न हो सकती है।

24. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की है और वे नोट करते हैं कि पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वे निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क को लागू करने के बाद उचित समय बीत जाने पर किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता के लिए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करने के साथ उसकी संपुष्टि करने का अनुरोध किए जाने पर अन्य बातों के साथ-साथ पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर जारी रखे जाने की समीक्षा करें। ऐसी समीक्षा करने पर जहां प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने अथवा उसमें परिवर्तन किए जाने से घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है और इसलिए अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो वे केन्द्रीय सरकार को उसको समाप्त करने की सिफारिश कर सकते हैं।

25. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने अपनी किसी परिश्रमता का उपयोग नहीं दिया है अथवा एमटीआर का उत्तर देने के लिए प्रदत्त आंकड़ों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सावधानी नहीं बरती है और जहां तक कि उसने परिशुद्धता का आवश्यक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की संबद्ध सूचना/आंकड़ों की जांच कर ली गई है।

26. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि क्षति रहित कीमत में भाड़े को शामिल करने के लिए घरेलू उद्योग का दावा की कानून की दृष्टि से तर्क संगत नहीं है और प्राधिकारी को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि वर्तमान मामले में क्षति रहित कीमत निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है जब कि घरेलू उद्योग को कोई आर्थिक क्षति नहीं हो रही है।

27. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि दो मध्यावधि समीक्षाएं अर्थात् वर्तमान समीक्षा तथा प्राधिकारी द्वारा तुर्की और रूस के खिलाफ शुरू की गई अन्य समीक्षा को संयोजित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उत्पादकों की संरचना के साथ-साथ जांच की अवधि समान है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों मध्यावधि समीक्षाएं दो विभिन्न

अंतिम जांच परिणामों से संबंधित हैं और इनमें शुल्क की अधिसूचनाओं में देशों के भिन्न सेट शामिल हैं और इसलिए इन दोनों मध्यावधि समीक्षाओं को संयोजित करना उपयुक्त नहीं होगा।

28. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर व्याप्त है क्योंकि घरेलू उद्योग क्षमताएं होने के बावजूद आपूर्ति करने में असमर्थ है और जिसके कारण निचले स्तर के उद्योग विशेषकर छोटे, लघु और मध्यम स्तर के डिटरजेंट उत्पादकों को नुकसान हो रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी विधि में घरेलू उद्योग, घरेलू बाजार की समस्त मांग को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। चूंकि पाटन-रोधी शुल्क लागू करने से आयात की रोकथाम नहीं होती है और इसका उद्देश्य केवल पाटन के कारण अनुचित स्थिति में सुधार लाना है, प्रयोक्ता क्षेत्र सदैव आयात कर सकता है और अपनी अतिरिक्त मांग को पूरा कर सकता है। साथ ही प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जीएचसीएल और निरमा वर्तमान जांच अवधि में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहे थे और अब वे वाणिज्यिक हो गई हैं।

29. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि कीमत निर्धारण के संबंध में सोडा एश के घरेलू उत्पादकों के बीच पारस्परिक समझौता है, जिससे निचले स्तर तक के उद्योगों की लागत पर कार्टेलाइजेशन हो जाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा आरोप अधिप्रमाणित नहीं है।

#### **ड. पाटन मार्जिन का निर्धारण**

##### **बाजार अर्थव्यवस्था के दावे, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन**

##### **आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन**

30. बाजार अर्थव्यवस्था, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) जब सोडा एश प्राकृतिक स्रोतों से उत्पादित किया जाता है, तो उत्पादन की लागत अत्यधिक कम होती है। यदि ऐसा प्रकटन सही है तो उन देशों में सामान्य मूल्य अत्यधिक कम होगा।
- (2) घरेलू उत्पादकों की निजी सहायक कंपनियां संबद्ध देशों में हैं, अर्थात् निरमा की निजी सहायक कंपनी संयुक्त राज्य अमरीका में है और टाटा की निजी सहायक कंपनियां केनिया और संयुक्त राज्य अमरीका में हैं। इसलिए घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों में निर्यातक का सामान्य मूल्य प्रदान करने में समर्थ होना चाहिए।
- (3) प्राधिकारी को चीन और यूक्रेन के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन, बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में घरेलू उत्पादकों की सहायक कंपनियों से प्राप्त कीमत के आधार पर अथवा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के संरचित मूल्य के आधार पर करना चाहिए।
- (4) घरेलू उद्योग ने इस तथ्य के बावजूद कि अधिकतर संबद्ध देशों में उसके संबंधित उत्पादक हैं, चीन और यूक्रेन को छोड़ कर संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अपनी मानक कीमतों को प्रयुक्त किया है। प्राधिकारी को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की ऐसी कार्य-प्रणाली को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
- (5) चूंकि घरेलू उत्पादकों द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उन्होंने समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए मूल्यों का आकलन कैसे प्राप्त किया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इनके साक्ष्य मंगाए और घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर अंध विश्वास करने के बजाय ऐसी सूचना प्राप्त करें।
- (6) असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का परिकलन, सहयोगी निर्यातकों के निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए।
- (7) मूल जांच के समय यूक्रेन में केवल 3 उत्पादक प्रचालन कर रहे थे। तथापि, विगत कुछ वर्षों के दौरान यूक्रेन परिस्थितियों में विकट रूप से परिवर्तन हुआ है, जिनके परिणामस्वरूप तीन संयंत्र बंद हो गए हैं और प्रचालन कर रहा एक संयंत्र क्रिमिया में

अवस्थित है, जिसे रूस ने हथिया लिया है। इसके फलस्वरूप यूक्रेन में अब कोई उत्पादक नहीं है, इसलिए यूक्रेन के खिलाफ लागू किए गए पाटन-रोधी शुल्कों को अब हटा लेने की आवश्यकता है।

- (8) यूक्रेन को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए जैसा कि उसे विगत जांच में माना गया था।
- (9) यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राज्य अमरीका के मामले में जांच अवधि में आईएचएस केमिकल्स में प्रकाशित औसत कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है, लेकिन प्रयुक्त किए गए आंकड़ों का प्रकटन नहीं किया गया है।
- (10) सोडा सानाई जैसे निर्यातकों को विशिष्ट पृथक मार्जिन दिया जाना चाहिए क्योंकि उसने समस्त जांच में सहयोग दिया है और प्रश्नावली के पूरे उत्तर प्रस्तुत किए हैं। जहां तक कि जांच पश्चात अवधि के आंकड़े भी विधिवत् प्रस्तुत किए हैं और प्राधिकारी द्वारा उनका सत्यापन किया गया है।

#### घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

31. बाजार अर्थव्यवस्था, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) चीन और यूक्रेन गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। विगत तीन वर्षों में भारत, यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा चीन और यूक्रेन गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश माना गया है।
- (2) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा ऐसी स्थिति में नहीं दिया जा सकता है, जिसमें एक प्रमुख शेयरधारक राज्य का निजी/नियंत्रित प्रयोज्यता है।
- (3) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक यह प्रमाणित नहीं करते हैं कि प्रमुख इनपुट की कीमतें बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं।
- (4) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक यह प्रमाणित नहीं करते हैं कि उनकी लेखा बहियों की लेखा-परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेकाकरण मानकों के अनुसार की जाती है।
- (5) किसी एक प्राचल को पूरा नहीं किए जाने पर भी बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।
- (6) प्रतिवादी निर्यातकों का यह दायित्व है कि वे इसे प्रमाणित करें कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचालन कर रहे हैं।
- (7) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि प्रतिवादी कंपनी और उसका समूह एक साथ मिल कर उसका दावा नहीं करते हैं।
- (8) ऐसी स्थिति में जिसमें वर्तमान शेयरधारकों ने स्वयं अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं, लेकिन उन्हें कुछ अन्य पक्षकारों से प्राप्त किया है, बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि दस्तावेजी साक्ष्यों परिवर्तन की प्रक्रिया को पूर्णतया प्रमाणित नहीं कर दिया जाता है।
- (9) घरेलू उद्योग ने भारत में अदा की गई कीमत के आधार पर चीन और यूक्रेन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने प्रमुख कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत को ध्यान में रखते हुए भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है और उसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय का विधिवत् समायोजन किया है तथा घरेलू उद्योगके खपत के मानदंडों पर विचार किया है। कच्ची सामग्री परिकलन,
- (10) घरेलू उद्योग ने आईएचएस केमिकल ग्लोबल सोडा एश में सूचित कीमतों के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय यूनियन के लिए कीमतों पर विचार किया है।
- (11) चूंकि ट्रेड लॉ जर्नल ईरान के लिए विचाराधीन उत्पाद की कीमतों को प्रकाशित नहीं करता है, घरेलू उद्योग ने ईरान में सामान्य मूल्य का निर्धारण, घरेलू उद्योग की खपत के मानकों और ईरान में विद्युत की कीमतों को ध्यान में रखते हुए ईरान में उत्पादन की लागत के श्रेष्ठ प्राक्कलनों के आधार पर किया है।



- (12) पाकिस्तान के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, आईसीआई पाकिस्तान की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, जिसमें कंपनी के लिए उत्पादन और बिक्रियों के मूल्य का प्रकटन भी किया गया है।
- (13) केनिया के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, जो कि भारत में एक सूचीबद्ध कंपनी है और जिसका एक संयंत्र मगाडी, केनिया में स्थापित है, की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
- (14) निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस के कारोबार-वार आंकड़ों के आधार पर किया गया है। निर्यात कीमत में समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन व्यय, बैंक प्रभारों और वॉट के अंतर के लिए समायोजन किया गया है।
- (15) सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों का निर्धारण कारखाना-गत स्तर पर किया गया है। घरेलू उद्योग ने उत्पाद के सभी भौतिक लक्षणों को ध्यान में रखा है जिनके लिए सूचना उपलब्ध है। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा की गई तुलना, उचित तुलना बनती है।
- (16) पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम है, बल्कि यह पर्याप्त भी है।
- (17) ऐसे देशों में जिनमें उत्पादन प्राकृतिक स्रोतों से किया जाता है, उत्पादन की लागत कम होने के संबंध में निवेदन है कि आईएचएस केमिकल जर्नल में ऐसे देशों में प्रचलित कीमत दी जाती है, जिससे इन देशों में अर्जित किए जाने वाले अधिक लाभ की अवधारणा बनती है।
- (18) घरेलू उद्योग ने देश में प्रचलित कीमत प्रदान की है जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।
- (19) निर्दिष्ट प्राधिकारी जैसा भी उचित समझते हैं, चीन और यूक्रेन के सामान्य मूल्य की संरचना के आधार का निर्णय ले सकते हैं।
- (20) घरेलू उद्योग ने विभिन्न समायोजनों के लिए साक्ष्य के संबंध में रूढ़िवादी रवैया अपनाया है।
- (21) प्राधिकारी को असहयोगी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए अत्यधिक सामान्य मूल्य और कमतर निर्यात कीमत के सौदों पर विचार करना चाहिए।

#### **प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था के दावे की जांच**

##### **चीन जनवादी गणराज्य और यूक्रेन**

32. प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (3) में निर्धारित मानदंड के अनुसार एमईटी की प्रश्नावलियां, सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन करने के लिए भेजी थीं। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया था कि वे अपने देश में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दें कि वे अपेक्षित सूचना प्राधिकारी को प्रदान करें। यथासंशोधित पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (3) के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि निर्यातक पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है और इसके प्रतिकूल सिद्ध करता है। तथापि, वर्तमान जांच में चीन जनवादी गणराज्य और यूक्रेन में किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई सहयोग नहीं दिया है और निर्यातक की प्रश्नावली और एमईटी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन नहीं किए जाने की स्थिति में प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य और यूक्रेन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार आगे की कार्रवाई करना उपयुक्त समझते हैं।

##### **च. सामान्य मूल्य का निर्धारण**

33. पाकिस्तान से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्यातक की प्रश्नावलियों के उत्तरों को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन पर विचार किया गया है:-

(क) ओलम्पिया केमिकल्स लिमिटेड, पाकिस्तान

(ख) आईसीआई पाकिस्तान लिमिटेड, पाकिस्तान

34. संबंधित संबद्ध देशों से अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में प्राधिकारी ने नियमावली के अनुसार उपलब्ध श्रेष्ठ सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

#### **चीन जनवादी गणराज्य और यूक्रेन**

35. चीन और यूक्रेन के उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह उचित समझते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई कार्रवाई की जाए। पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार हैं:

*“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।”*

36. तदनुसार किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में संबद्ध वस्तुओं के लिए कोई विश्वसनीय कीमत और लागत के ब्यौरे उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्राधिकारी ने समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से अदा की गई अथवा देय कीमत के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य और यूक्रेन के लिए सामान्य मूल्य संरचित किया है, जिसमें उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत् समायोजन किया गया है। तदनुसार चीन जनवादी गणराज्य और यूक्रेन से सभी निर्यातकों के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य संरचित किया गया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

#### **यूरोपीय यूनियन (ईयू)**

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय यूनियन से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली को उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने यूरोपीय यूनियन के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध श्रेष्ठ सूचना पर विश्वास किया है। तदनुसार प्राधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, एचआईएस केमिकल सप्लीमेंट, जो कि आवधिक रूप से यूरोपीय यूनियन सहित विभिन्न देशों में प्रचलित सोडा एश की कीमतें प्रकाशित करता है, में प्रकाशित कीमतों को ध्यान में रखते हुए जांच अवधि के दौरान औसत कीमतों के आधार पर कारखाना-गत स्तर पर यूरोपीय यूनियन के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार यूरोपीय यूनियन के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

#### **संयुक्त राज्य अमरीका**

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली को उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने संयुक्त राज्य अमरीका के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध श्रेष्ठ सूचना पर विश्वास किया है। तदनुसार प्राधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, एचआईएस केमिकल सप्लीमेंट, जो कि संयुक्त राज्य अमरीका सहित विभिन्न देशों में प्रचलित सोडा एश की कीमतें प्रकाशित करता है, में आवधिक रूप से प्रकाशित कीमतों के आधार पर कारखाना-गत स्तर पर संयुक्त राज्य अमरीका के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

**ईरान**

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईरान से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली को उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने ईरान के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध श्रेष्ठ सूचना पर विश्वास किया है। तदनुसार प्राधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, एचआईएस केमिकल सप्लिमेंट, जो कि ईरान सहित विभिन्न देशों में प्रचलित सोडा एश की कीमतें प्रकाशित करता है, में आवधिक रूप से प्रकाशित कीमतों के आधार पर कारखाना-गत स्तर पर ईरान के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार ईरान के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

**पाकिस्तान**

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाकिस्तान के दो निर्यातकों नामतः आईसीआई पाकिस्तान लिमिटेड और ओलम्पिया केमिकल्स लिमिटेड, ने निर्यातक की प्रश्नावली को उत्तर प्रस्तुत किए हैं, जिनमें उन्होंने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्रियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं।

**आईसीआई पाकिस्तान लिमिटेड**

41. निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में आईसीआई पाकिस्तान लिमिटेड ने सूचित किया है कि वर्तमान मध्यावधि जांच की जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की उनकी कुल घरेलू बिक्रियां \*\*\* मी. टन थीं, जिनका सकल बीजक मूल्य \*\*\*टीएल था। बिक्री कर, कमीशन, छूट, कार्गो हैंडलिंग प्रभारों, भंडारण प्रभारों, बीमा, बिक्री और वितरण लागत अर्थात् वेतन, अन्य और कोर्पोरेट सामान्य प्रशासनिक व्यय, घरेलू लाभ पर कर, तैयार वस्तुओं को रखने की लागत और क्रेडिट की लागत आदि उन उन्होंने समायोजन करने का दावा किया है। तथापि, प्रतिवादी कंपनी समायोजन करने के दावों को प्रमाणित करने के लिए पूरे समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी है। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी आईसीआई पाकिस्तान लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं कर सके हैं।

**ओलम्पिया केमिकल्स लिमिटेड**

42. ओलम्पिया केमिकल्स लिमिटेड, पाकिस्तान ने सूचित किया है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की उनकी कुल घरेलू बिक्रियां \*\*\* मी. टन थीं, जिनका सकल बीजक मूल्य \*\*\*टीएल था। उसने वॉट, छूट, कमीशन, अंतरदेशीय भाड़े, क्रेडिट लागत और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन करने का दावा किया है। प्राधिकारी ने समायोजन करने के दावे को स्वीकार कर लिया है और ओलम्पिया केमिकल्स लिमिटेड, पाकिस्तान के संबंध में संबंध में कारखाना-गत स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। ओलम्पिया केमिकल्स लिमिटेड, पाकिस्तान के लिए इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य नीचे पाटन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

**पाकिस्तान के असहयोगी निर्यातक**

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाकिस्तान के अन्य किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए। इसलिए प्राधिकारी ने पाकिस्तान से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए पाकिस्तान से सहयोगी निर्यातक के अधिकतम सामान्य मूल्य को अपनाया है। तथापि, पाकिस्तान से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार से निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य के ब्यौरे, नीचे पाटन तालिका में उल्लिखित किए गए हैं।

**केनिया**

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि केनिया के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने केनिया के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध श्रेष्ठ सूचना पर विश्वास किया है और तदनुसार केनिया के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया। केनिया से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार से निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य के ब्यौरे, नीचे पाटन तालिका में उल्लिखित किए गए हैं।

**छ. निर्यात कीमत****चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राज्य अमरीका, ईरान, केनिया और यूक्रेन**

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय यूनिया, संयुक्त राज्य अमरीका, ईरान, केनिया और यूक्रेन से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। उपरोक्त देशों से उत्पादकों/निर्यातकों से निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध श्रेष्ठ सूचना के आधार पर इन देशों के संबंध में निर्यात कीमत निर्धारित की है। प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान उपरोक्त देशों से आयातों के भारित औसत सीआईएफ मूल्य पर निर्यात कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ डीजीसीआईएंड एस के आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। उपरोक्त देशों के संबंध में निबल निर्यात कीमत प्राप्त करने के लिए याचिकदाता द्वारा जैसा दावा किया गया है, समुद्री भाड़े, बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़े और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन पर विचार किया गया है। तदनुसार चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राज्य अमरीका, ईरान, केनिया और यूक्रेन के सभी निर्यातकों के लिए कारखाना-गत स्तर पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है, जिसे नीचे पाटन तालिका में दिया गया है।

**पाकिस्तान****आईसीआई पाकिस्तान लिमिटेड**

46. आईसीआई पाकिस्तान लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तरों के अनुसार उसने जांच अवधि दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं के \*\*\* मी.टन निर्यात किए हैं, जिनका सकल बीजक मूल्य \*\*\*पीकेआर था। कंपनी ने कमीशन, छूट, लदाई और उतराई के व्यय, पत्तन प्रभारों, बीमा, सेवा प्रभारों, घरेलू लाभ पर कर, प्राप्त हुई अग्रिम राशि पर ब्याज आय के लिए समायोजन करने का दावा किया है। तथापि, प्रतिवादी कंपनी समायोजन करने के दावों को प्रमाणित करने के लिए पूरे समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी है। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी आईसीआई पाकिस्तान लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण नहीं कर सके हैं।

**ओलम्पिया केमिकल्स लिमिटेड**

47. ओलम्पिया केमिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तरों के अनुसार उसने जांच अवधि दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं के \*\*\* मी.टन निर्यात किए हैं, जिनका सकल बीजक मूल्य \*\*\* अमरीकी डालर था। जैसा कि कंपनी ने दावा किया है, कमीशन, अंतरदेशीय भाड़े, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभारों, बीमा और हैंडलिंग प्रभारों के लिए समायोजन करने के बाद कारखाना-गत स्तर पर निबल निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। ओलम्पिया केमिकल्स लिमिटेड, पाकिस्तान के लिए इस प्रकार से निर्धारित की गई निबल निर्यात कीमत के ब्यौरे नीचे पाटन तालिका में दिए गए हैं।

**पाकिस्तान के सभी अन्य निर्यातक**

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाकिस्तान से किसी भी अन्य निर्यात ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने सभी अन्य निर्यातकों के लिए सहयोगी निर्यातकों की भारत को कमतर प्रतिनिधिक निबल निर्यात कीमत को अपनाया है और उसमें विधिवत् समायोजन करने के बाद निबल निर्यात कीमत तय की है। पाकिस्तान से असहयोगी निर्यातकों के लिए इस प्रकार से निर्धारित की गई निर्यात कीमत, नीचे पाटन तालिका में उल्लिखित की गई है।

**ज. पाटन मार्जिन**

49. यथा निर्धारित उपरोक्त सामान्य मूल्य और निर्यातक कीमतों की तुलना करते हुए जांच अवधि और जांच पश्चात अवधि के दौरान संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है, जिससे यह पता चलता है कि जांच अवधि के बाद भी अर्थात् जांच अवधि के बाद परवर्ती अवधि में भी पाटन होता रहा है। तथापि, जांच की अवधि के बाद की अवधि में पाटन मार्जिन संयुक्त राज्य अमरीका, जहां वह बढ़ा है, को छोड़कर सभी देशों के संबंध में कम हुआ है।

**जांच अवधि (2014-15)**

देश	निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य अमरीकी डालर/मी.टन	निबल निर्यात कीमत मरीकी डालर/मी.टन	पाटन मार्जिन अमरीकी डालर/मी.टन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % सीमा
चीन जनवादी गणराज्य	सभी	****	****	****	****	15-25
यूक्रेन	सभी	****	****	****	****	15-25
यूरोपीय यूनियन	सभी	****	****	****	****	5-15
ईरान	सभी	****	****	****	****	5-15
संयुक्त राज्य अमरीका	सभी	****	****	****	****	5-15
केनिया	सभी	****	****	****	****	10-20
पाकिस्तान	ओलम्पिया केमिकल्स लिमिटेड, पाकिस्तान	****	****	****	****	20-30
	पाकिस्तान में असहयोगी उत्पादक/निर्यातक	****	****	****	****	30-40

जांच पश्चात अवधि (अप्रैल, 2015-सितंबर, 2015)

देश	निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य अमरीकी डालर/मी.टन	निबल निर्यात कीमत मरीकी डालर/मी.टन	पाटन मार्जिन अमरीकी डालर/मी.टन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % सीमा
चीन जनवादी गणराज्य	सभी	****	****	****	****	5-15
यूक्रेन	सभी	****	****	****	****	15-25
यूरोपीय यूनियन	सभी	****	****	****	****	0-10
ईरान	सभी	****	****	****	****	0-10
संयुक्त राज्य अमरीका	सभी	****	****	****	****	15-25
केनिया	सभी	****	****	****	****	0-10
पाकिस्तान	ओलम्पिया केमिकल्स	****	****	****	****	15-25

	लिमिटेड, पाकिस्तान					
	पाकिस्तान में असहयोगी उत्पादक/निर्यातक	****	****	****	****	20-30

## झ. क्षति निर्धारण की कार्य-प्रणाली तथा क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

### आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

50. इस संबंध में आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) आयात इसलिए हो रहा है क्योंकि घरेलू उत्पादक प्रयोक्ताओं को विवश कर रहे हैं। जहां तक कि ऐसे घरेलू उत्पादक भी जो कि निचले स्तर के उत्पादन के लिए संबद्ध वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, केवल आयातित उत्पादों का प्रयोग करते हैं। इसलिए मध्यावधि समीक्षा शुरू करने की तारीख से पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की सिफारिश की जा सकती है।
- (2) घरेलू उत्पादकों ने इस तथ्य का कभी भी प्रतिवाद नहीं किया है कि क्षमता उपयोग, प्राप्त क्षमता उपयोग से अधिक किया जा सकता है। यह प्रतिवाद नहीं किया गया है कि एससीएल के साथ निरमा ने वीआईएफआर के समक्ष यह दावा किया है कि एससीएल का संयंत्र स्क्रैप की स्थिति में है।
- (3) घरेलू उत्पादकों द्वारा अर्जित नियोजित पूंजी पर 20% - 25% प्रतिलाभ, अनुबंध-III के सिद्धांतों को लागू किए बिना वित्तीय रिकार्ड से प्राप्त किया गया है, जिसमें कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण संयंत्र के बंद होने की अवधि के दौरान हुए व्यय जैसे असमान्य व्यय को शामिल नहीं किए जाने की आवश्यकता है।
- (4) कीमत में कटौती के लिए घरेलू उत्पादकों की निबल बिक्री वसूली (एनएसआर) को भाड़े को जोड़ कर प्राप्त किया गया है। हालांकि ऐसा निर्दिष्ट प्राधिकारी की पद्धति के अनुसार किया गया है, घरेलू उत्पादकों के लिए कारखाना-गत आधार पर निबल बिक्री वसूली प्राप्त की गई है।
- (5) गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड ("जीएचसीएल") एक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है और वह ऐसे उत्पादकों और निर्यातकों से संबंधित है, जो कि वर्तमान जांच में भाग नहीं ले रहे हैं क्योंकि कोई पाटन नहीं हो रहा है। घरेलू उत्पादकों ने इस तथ्य की मनाही नहीं की है कि टाटा केमिकल्स लिमिटेड ("टीसीएल") भी एक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है और यह आयातित संबद्ध वस्तुओं की पुनः बिक्री पर अत्यधिक लाभ अर्जित कर रही है।
- (6) घरेलू उत्पादकों के निष्क्रिय संयंत्रों को शामिल करने के बाद भी कीमत में कोई ह्रास और न्यूनीकरण नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है।
- (7) घरेलू उद्योग को कोई मात्रात्मक क्षति और कीमत क्षति नहीं हो रही है तथा संयंत्र अपनी श्रेष्ठ क्षमता का उपयोग करते हुए चल रहे हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- (8) एनआईपी, एनएसआर और पहुंच कीमत से पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान नकारात्मक क्षति हुई है। जांच पश्चात अवधि से नकारात्मक मार्जिन का पता चलता है। घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है। इसलिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही घरेलू उद्योग को क्षति के निरंतर जारी रहने की भी कोई संभावना नहीं है।
- (9) यह अविवादित तथ्य है कि अमरीकी डालर में निर्यात कीमत में वृद्धि होने के कारण पहुंच मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है। घरेलू उत्पादक आयातित सामग्री पर निर्भर नहीं हैं और इसलिए वे अमरीकी डालर के आधार पर आईएनआर में मूल्य ह्रास द्वारा निष्प्रभावित हैं। ऐसा परिवर्तित स्थाई प्रकृति का होता है और अब यह 3 वर्षों से भी अधिक समय से निरंतर चल रहा है। इसलिए घरेलू उत्पादकों को क्षति होने की कतई संभावना नहीं है।
- (10) आधार वर्ष में उत्पादन 2,391,519 मी.टन था, जो कि जांच अवधि में बढ़ कर 2,405,410 मी.टन हो गया है। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान घरेलू उत्पादकों ने यह स्वीकार किया है कि उनको कोई क्षति नहीं हुई है।
- (11) घरेलू उद्योग के कुल निर्यात वर्ष 2011-12 में 2,00,354 मी.टन थे, जो वर्ष 2014-15 में घट कर 26,642 मी.टन रह गए, जिससे घरेलू उत्पादकों द्वारा दिए गए ऐसे वक्तव्य को झुठलाता है कि घरेलू उत्पादक मालसूचियों का निपटान करने के लिए निरंतर निर्यात कर रहे हैं।

- (12) उत्पाद की घरेलू बिक्रियां, वर्ष 2011-12 में 20,06,729 मी.टन से बढ़ कर वर्ष 2014-15 में 22,18,766 मी.टन हो गई हैं। तथापि, केप्टिव खपत और निर्यात में तेजी से गिरावट आने के कारण कुल बिक्रियां, वर्ष 2011-12 में 24,19,438 मी.टन से मामूली घट कर वर्ष 2014-15 में 24,03,783 मी.टन रह गई हैं।
- (13) सबसे बड़ी भारतीय घरेलू उत्पादक, "टाटा केमिकल्स लिमिटेड" ने केनिया में स्थित अपनी सहायक कंपनी और यूरोपीय यूनियन और चीन में गैर-संबंधित उत्पादकों से सामग्री के आयात किए हैं। घरेलू उत्पादक ने दावा किया है कि केनिया से आयातित उत्पाद निम्नतम ग्रेड का था और यह भारत में घरेलू उत्पादकों से कम कीमत कीमत प्राप्त करता है। आयात के बाद घरेलू उत्पादक जिस कीमत पर संबद्ध वस्तुओं को प्रयोक्ताओं को बेचते हैं, उसकी तुलना निबल बिक्री वसूली और क्षति रहित कीमत के साथ की जानी चाहिए।
- (14) जांच अवधि और क्षति अवधि के दौरान घरेलू उत्पादकों ने अनुकूलतम क्षमता उपयोग प्राप्त किया है। उनके द्वारा निर्दिष्ट क्षमता केवल नाम पट्टिका क्षमता मात्र है, संयंत्र निष्क्रिय हो गए हैं और वे उस क्षमता से अधिक का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं, जिस पर वे चल रहे हैं।
- (15) शुल्क के अनेक वर्षों के बाद भी सोडा एश उद्योग ने उस स्तर पर अपनी क्षमता को नहीं बढ़ाया है, जिससे वह समग्र भारतीय मांग को पूरा कर सके। पाटन-रोधी शुल्क लागू करने का उद्देश्य क्षति पहुंचाने वाले पाटन के व्यापार को विकृत करने वाले प्रभावों को समाप्त करना है और न कि घरेलू उद्योगों के लिए एकाधिकारिता की स्थिति उत्पन्न करना है।
- (16) मूल जांच अवधि जो कि समीक्षाधीन है, से घरेलू उत्पादकों की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त क्षमता में वृद्धि करने के लिए संयंत्रों में किए गए निवेशों के बारे में घरेलू उद्योग के दावे किसी साक्ष्य के बिना अधिप्रमाणित नहीं होते हैं।
- (17) विस्तार योजनाओं के संबंध में घरेलू उत्पादक संदिग्ध रूप से प्रयोक्ताओं के खर्च पर अत्यधिक लाभ अर्जित करने के लिए संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यहां घरेलू उत्पादकों ने दुबारा झूठा दावा किया है। आईएनआर 1250 पीएमटी का प्रतिलाभ उद्योग के लिए औसत है। घरेलू उत्पादक क्षमताओं का विस्तार करने अथवा नए सदस्यों पर कभी व्यय नहीं करेंगे।
- (18) पाटन-रोधी शुल्क के बिना अथवा सहित जांच करने पर विगत दो वर्षों से आयातों से घरेलू उत्पादकों को कोई क्षति नहीं हुई है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है जो कि प्रयोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ है।
- (19) जीएचसीएल जांच अवधि के दौरान 87% से भी अधिक क्षमता का प्रयोग कर रही थी, जो कि इन उद्योगों में अधिकतम संभावित क्षमता उपयोग है। जीएचसीएल 8,50,000 मी.टन क्षमता के साथ सबसे बड़े उत्पादकों में से एक उत्पादक है। यह कारोबार से लाभ की अच्छी राशि अर्जित कर रही है। जहां तक कि इसे संबद्ध देशों सहित विभिन्न देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह नोट किया जा सकता है कि वह पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान करने के बाद आयात कर रही है और तब उसकी पुनःबिक्री से पर्याप्त लाभ अर्जित कर रही है।
- (20) घरेलू उद्योग उन्हीं आंकड़ों को चुन रहा है जो उसके अनुकूल हैं। ऐसे रवैये को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि आयात हो रहे हैं, फिर भी वह अपनी कीमतें बढ़ा रहा है। जैसा कि घरेलू उद्योग के दिनांक 02.03.2016 के निवेदन में सूचित किए गए सही आंकड़ों को देखने से पता चलता है, वर्ष 2014-15 में बिक्रियों की लागत बढ़ कर केवल 111 हो गई है, लेकिन बिक्रियों की लागत बढ़ कर 117 हो गई है। वर्ष 2014-15 में जब बिक्रियों की लागत में 110 से 1 प्रतिशत बिन्दु तक की गिरावट देखी गई थी, तब बिक्री कीमतें विगत वर्ष की तुलना में उछल कर 10 प्रतिशत तक हो गई थी।
- (21) स्थाई प्रकृति की जांच करने के लिए निर्यातक देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के साथ-साथ घरेलू उद्योग की बिक्रियों की वसूली पर भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन विश्व बाजार में प्रतिबिंबित होता है और भारत में निर्यात कीमत में वृद्धि एकमात्र घटना नहीं है।
- (22) पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-III में ऐसा स्पष्ट उल्लेख है कि क्षति रहित कीमत के प्रयोजनार्थ बाह्य भाड़े पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि यह विनिर्माण पश्चात व्यय है। घरेलू उद्योग अब ऐसा प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहा है कि उसका तर्क क्षति रहित कीमत का निर्धारण करना नहीं, बल्कि क्षति का निर्धारण करना है। वास्तव में दोनों ही एक समान हैं क्योंकि क्षति के मार्जिन को आयातों की पहुंच कीमत और कारखाना-गत स्तरों पर क्षति रहित कीमत के बीच का अंतर माना जाता है।
- (23) यह दावा तर्क संगत नहीं है कि प्रत्याशित भावी निवेश, जो कि कोई ठोस प्रकृति का नहीं है, के संरक्षण के लिए शुल्कों को निरंतर जारी रखा जाए।

- (24) ऐसे मामलों में जिनमें क्षति मार्जिन स्वतः नकारात्मक है अर्थात् पहुंच मूल्य, क्षति रहित कीमत से अधिक है, प्राधिकारी द्वारा किसी पाटन-रोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की जा सकती है। चूंकि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, इसलिए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- (25) घरेलू उद्योग द्वारा सृजित सर्वोच्च लाभ प्रत्यक्षतः इस तथ्य से संबंधित है कि आयात क्षति रहित कीमत के समान हैं और घरेलू उद्योग द्वारा इस अंतर का लाभ उठाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को उनके उद्योगों के लिए जरूरी सोडा एश की कृत्रिम रूप से अत्यधिक बढ़ाई गई कीमतों के कारण नुकसान हो रहा है, जिनका आगे प्रभाव विभिन्न औद्योगिक और उपभोक्ता मदों पर प्रभाव पड़ सकता है।
- (26) विनिमय दर के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में वृद्धि होने के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है। घरेलू उत्पादक बड़े हुए पहुंच मूल्य के रूप में रूपए के अवमूल्यन का लाभ उठा रहे हैं क्योंकि इस तथ्य के कारण उनकी लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि घरेलू उत्पादक ऐसे कच्चे माल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि भारत में स्वतः अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है।
- (27) गुजरात में आयात की कीमत सर्वाधिक है। ऐसे क्षेत्र में जहां संबद्ध वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, अधिक कीमत होने तथा जिस क्षेत्र में इनकी आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, वहां कम कीमत होने से भी यह सिद्ध होता है कि खरीदारी, कीमत की प्राथमिकता पर निर्भर नहीं करती है।
- (28) आयात की मात्रा और कीमतों के बीच कोई संबंध नहीं है। घरेलू उत्पादक आयातों की मात्रा और कीमतों के निरपेक्ष अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। घरेलू उत्पादकों के संरक्षण की किसी आवश्यकता के बिना भी प्रयोक्ता पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान कर रहे हैं।
- (29) जिस कीमत पर आयातित वस्तुओं को पुनः बेचा गया था, वह आयात के पत्तन पर दर्शाए गए पहुंच मूल्य से बहुत अधिक थी, जिसके फलस्वरूप ऐसे पहुंच मूल्य को, क्षति रहित कीमत और एनएसआर के साथ तुलना करने के प्रयोजनार्थ विकृत किया गया था।
- (30) जहां यूएसडी की तुलना में आईएनआर का अत्यधिक अवमूल्यन हो गया था, वहां विदेशी मुद्रा की दर में परिवर्तन किया गया था। ऐसे परिवर्तनों के फलस्वरूप आयात की कीमतों में वृद्धि हुई थी।
- (31) जैसे जांच शुरू होने के समय घरेलू उद्योग को पाटन, क्षति के विद्यमान होने और कारणात्मक संबंध होने के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं और वास्तव में क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन का निर्धारण करना नहीं होता है, वैसे ही समीक्षा के मामले में आवेदकों को केवल एक आवेदन-पत्र के साथ परिवर्तित परिस्थितियों के सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने अपेक्षित होते हैं।
- (32) घरेलू उत्पादकों ने यह तर्क दिया है कि असहयोगी निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण, भारत में सूचित निम्नतम कीमतों के आधार पर किया जाए। प्रतिवादी ऐसे निवेदनों के गलत होने से इन्कार करता है और निवेदन करता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए औसत भारित कीमत पर विचार करना चाहिए। वर्तमान मामले में संबद्ध देशों से निर्यातकों ने जांच में भाग लिया है और जहां तक कि संबद्ध देशों में घरेलू उत्पादकों से संबंधित पक्षकार जांच अधीन हैं। इसलिए क्षति मार्जिन का परिकलन, निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया जाए और न कि भारत में सूचित निम्नतम कीमत पर।
- (33) घरेलू उत्पादकों ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी, केवल उन्हीं सौदों पर विचार कर सकते हैं, जिनमें क्षति मार्जिन सकारात्मक है। प्रतिवादी घरेलू उद्योग के ऐसे निवेदनों के गलत होने से इन्कार करता है। ऐसा अनुरोध करने का पूर्णतया कोई आधार नहीं है और किसी भी जगह ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो कि केवल सकारात्मक क्षति मार्जिन पर विचार करने की अनुमति देता है।
- (34) घरेलू उत्पादकों ने यह तर्क दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की भावी निवेशों की जांच करने की आवश्यकता है। साथ ही निर्दिष्ट प्राधिकारी को इसका भी विश्लेषण करना चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग को कोई आर्थिक विलम्बन हुआ है। प्रतिवादी ऐसे निवेदनों के गलत होने से इन्कार करता है। प्रतिवादी का निवेदन है कि घरेलू उत्पादक यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भावी निवेश किया है, लेकिन वे यह सिद्ध करने में असमर्थ हैं कि उन्होंने ऐसा कोई निवेश, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए पाटन-रोधी शुल्क लागू किए जाने के बाद किया है, जबकि संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई थी।
- (35) निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे घरेलू उत्पादकों से यह कहें कि वह किए गए अपने आयातों के बारे में खुल कर पेश हों। उनके लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वे किन कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का आयात करते हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि घरेलू उत्पादकों के पास अपनी निबल बिक्री वसूलियों की सूचना है, उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि क्या उनके द्वारा किए



गए आयात निबल बिक्री वसूली से अधिक हैं अथवा नहीं? साथ ही घरेलू उत्पादकों को उन कीमतों का प्रकटन भी करना चाहिए जिन पर आयातित वस्तुओं को खुले बाजार में पुनः बेचा गया था।

- (36) घरेलू उत्पादक मुख्यतया अपनी संबद्ध वस्तुओं को बहुत अच्छी कीमत पर गुजरात और उसके आस-पास के क्षेत्र में बेच रहे हैं। घरेलू उत्पादकों ने यह स्वीकार किया है कि वे अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं। ऐसा बताया गया है कि अकेले पश्चिम बंगाल में कीमत में अत्यधिक गिरावट आई है और ऐसी गिरावट, गुजरात और भारत के अन्य भागों में अधिक नहीं है।
- (37) वर्तमान मामले में आयात की मात्रा और कीमतों के बीच कोई संबंध नहीं है तथा घरेलू उत्पादक आयातों की मात्रा और कीमतों के निरपेक्ष अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। प्रयोक्ताओं को घरेलू उत्पादकों के संरक्षण की किसी आवश्यकता के बिना पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान करना पड़ रहा है।
- (38) संबद्ध देशों में घरेलू उत्पादकों की सहायक कंपनियां स्थित हैं। निरमा की सहायक कंपनी संयुक्त राज्य अमरीका में और टाटा की सहायक कंपनियां केनिया और संयुक्त राज्य अमरीका में स्थित हैं। इसलिए घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों में निर्यातक का सामान्य मूल्य प्रदत्त करने में समर्थ होना चाहिए। प्राधिकारी को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में घरेलू उत्पादकों की सहायक कंपनियों से प्राप्त की गई कीमत अथवा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के संरचित मूल्य के आधार पर चीन और यूकेर्राइन के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन करना चाहिए। प्राधिकारी को अपने पास अन्य विकल्प उपलब्ध होने की स्थिति में घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत पर विचार नहीं करना चाहिए।
- (39) सबसे बड़ा भारतीय उत्पादक "टाटा केमिकल्स लिमिटेड" (जिसे आगे टाटा कहा गया है) ने केनिया में स्थित अपनी सहायक कंपनी तथा यूरोपीय यूनियन और चीन से गैर-संबंधित उत्पादकों से सामग्री आयातित की थी। घरेलू उत्पादक ने यह दावा किया है कि केनिया से आयातित उत्पाद निम्नतम ग्रेड का था और उससे उसे भारत में घरेलू उत्पादकों से भी निम्न कीमत प्राप्त हुई है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यदि गुणवत्ता में भिन्नता होने के कारण तुलना के लिए कीमत में 20% का समायोजन किया गया है, तो आयात अत्यधिक महंगे बन जाते हैं, लेकिन प्रयोक्ता इसे इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वे पर्याप्त आपूर्तियां प्राप्त नहीं कर रहे हैं। आयात के बाद घरेलू उत्पादक जिस कीमत पर संबद्ध वस्तुओं को प्रयोक्ताओं को बेचते हैं, उसकी तुलना निबल बिक्री वसूली और क्षति रहित कीमत के साथ की जानी चाहिए।
- (40) घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि भाड़े के प्रभारों को क्षति रहित कीमत के परिकलन में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन है। पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-III में ऐसा स्पष्ट उल्लेख है कि क्षति रहित कीमत के प्रयोजनार्थ बाह्य भाड़े पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि यह विनिर्माण पश्चात व्यय है।
- (41) यह प्रमाणित करने का कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। इसके अतिरिक्त संबद्ध देशों से आयातों और बाजार के हिस्से में गिरावट आई है। इसलिए संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा नगण्य बन गई है और यह घरेलू उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव डालने में अक्षम है।
- (42) घरेलू उद्योग का यह दृढ़ मत है कि प्राधिकारी को ऐसे किसी भी आयात की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिसकी कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। तथापि, घरेलू उद्योग मनमाने ढंग से बहुत अधिक बिक्री कीमत निर्धारित कर रहा है और विदेशों में सोडा एश के सभी प्रमुख उत्पादकों से आयात को रोकने के प्रयास कर रहा है।
- (43) आयातों के कारण कीमत ह्रास अथवा कीमत न्यूनीकरण नहीं हो रहा है क्योंकि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, जबकि बिक्रियों की लागत में केवल 6% की वृद्धि हुई है। जांच पश्चात अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है, लेकिन बिक्रियों की लागत में गिरावट आई है।
- (44) सभी आर्थिक प्राचलों के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। उसके उत्पादन और बिक्रियों में वृद्धि हुई है, क्षमता उपयोग 80% से अधिक बना हुआ है, मालसूचियों में वृद्धि हुई है, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ सहित लाभ में वृद्धि हुई है और साथ ही रोजगार में भी मामूली वृद्धि हुई है।
- (45) लाभप्रदता और एनएसआर में व्यापक वृद्धि हुई है तथा कोई कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण नहीं हुआ है। निर्यात निष्पादन को छोड़ कर घरेलू उद्योग ने समग्र कार्य बहुत अच्छे ढंग से निष्पादित किया है।
- (46) कीमत में कटौती केवल उसी मामले में प्रासंगिक है जिसमें आयातों के कारण कीमत ह्रास अथवा कीमत न्यूनीकरण होता है। लेकिन वर्तमान मामले में कोई कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण नहीं हुआ है और इसलिए यह वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं है।
- (47) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने अपनी वस्तुओं को आयातों की पहुंच कीमत के समान कीमत पर बेचा था। तब भी घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ अर्जित किया था, जो कि 22% से अधिक है। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

- (48) घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार, ऐसी क्षमता संवर्धन के चालू होने की तारीख के बिना अनिश्चित है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग को किसी भी निवेश को अर्थक्षम बनाने के लिए नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, 8839 रूपए प्रति मी.टन की दर से प्राप्त करना चाहिए।

### घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

51. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) पाटन-रोधी शुल्क के प्रतिसंहरण के लिए घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में मात्र सुधार आना अपर्याप्त आधार है। नियम 23 (1क) प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थिति पर ध्यान संकेन्द्रित करने के बजाय घरेलू उद्योग पर शुल्क के प्रतिसंहरण के प्रभाव की जांच करने का अधिदेश प्रदान करता है।
- (2) स्थाई प्रकृति का तात्पर्य परिस्थितियों में ऐसे परिवर्तन से है, जो कि वापिस वैसे बदली नहीं जा सकती हैं, जैसी वे पहले थीं। आयात कीमत में गिरावट से स्पष्ट सिद्ध होता है कि परिवर्तन स्थाई प्रकृति के नहीं थे और ये पूर्णतया अस्थायी प्रकृति के थे।
- (3) निर्यातकों के असहयोग के मामले में पाटन मार्जिन का निर्धारण भारत में सूचित निम्नतम कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी को केवल क्षति पहुंचाने वाले आयातों पर ही विचार करना चाहिए और ऐसे आयातों की अनदेखी करनी चाहिए जो कि क्षति रहित कीमत से अधिक के हैं। नकारात्मक क्षति मार्जिन का तात्पर्य पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने से नहीं है।
- (4) प्राधिकारी को पहले इसकी जांच करनी अपेक्षित है कि क्या घरेलू उद्योग को कोई आर्थिक क्षति हुई है। यदि प्राधिकारी का यह निष्कर्ष निकलता है कि घरेलू उद्योग को कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है, तो प्राधिकारी को इसकी जांच करने की आवश्यकता है कि क्या पाटन-रोधी शुल्क को समय से पूर्व समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति होने का कोई खतरा है। यदि ऐसा नहीं है, तो प्राधिकारी को इसकी जांच करनी चाहिए कि क्या विचाराधीन उत्पाद के निरंतर पाटन से देश में घरेलू उद्योग की अवस्थापना में आर्थिकरूप से कोई मंदी आने की संभावना है।
- (5) इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग की निबल बिक्री कीमत 19,000 रूपए प्रति मी.टन से अधिक है, सूचीबद्ध आंकड़ों से पता चलता है कि बिक्री कीमत, सुनवाई के समय हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताई गई निबल बिक्रियों की वसूली से काफी कम है।
- (6) लेखा बहियों के आधार पर नियोजित पूंजी के मुद्दे के संबंध में निर्धारित प्रपत्र केवल क्षति के निरंतर जारी रहने का निर्धारण करने के लिए ही प्रासंगिक है और न कि संभावित क्षति और क्षति की संभावना के लिए। क्षति की संभावना के लिए संभावित स्थिति को देखे जाने की आवश्यकता है।
- (7) भाडे को शामिल करने के मुद्दे पर दोहराए जाने (रेस-ज्यूडिकाटा) के सिद्धांत को लागू करने के संबंध में निवेदन है कि यह सिद्धांत तभी लागू होता है, जब मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। मूल जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष उठाया गया मुद्दा अभी विचाराधीन है क्योंकि माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील दायर की गई है, इसलिए यह मुद्दा जीवित है और इस समय वर्तमान वैध है।
- (8) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने भाडे के बारे में तर्क देते हुए धरातल पर क्षति मार्जिन के बारे में बात की है, जब कि उसका वास्तव में अभिप्राय क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने से है, दोष युक्त है क्योंकि ये दोनों भिन्न शब्दावलियां हैं।
- (9) निम्नतर शुल्क नियम से संबंधित ब्राजील की पद्धतियों पर विश्वास करना उपयुक्त है, चूंकि क्षति मार्जिन का निर्धारण करने संबंधी कोई दिशानिर्देश नहीं होने की स्थिति में पद्धति और सिद्धांत विकसित होते रहते हैं। कुछ चुनिन्दा उत्पादों के लिए भाडे का मामला महत्वपूर्ण है और इसलिए विगत में उसे प्रचंडता से उत्तेजित नहीं किया गया है।
- (10) शुल्कों के अनेक वर्षों से लागू रहने के संबंध में निवेदन है कि पाटन-रोधी शुल्क वर्ष 2012 में लागू किए गए थे। वर्ष 2011-12 से घरेलू उद्योग को घाटे हो रहे थे और वह वर्ष 2013-14 तक निचले स्तर पर लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ अर्जित कर रहा था। शुल्कों को लागू किए जाने के बाद घरेलू उद्योग की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है और बाजार की अर्थक्षमता में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप विस्तार की योजना बनी है।
- (11) भावी निवेश ठोस प्रकृति के हैं और उन्हें वापिस नहीं लिया जा सकता है। चीन से प्योर सिल्क टाईपराईटर रिबन फैब्रिक्स के आयातों के इसी मामले पर विश्वास करना अनुचित है क्योंकि इसके तथ्य भिन्न हैं।

- (12) घरेलू उद्योग की अधिक लाभप्रदता के संबंध में यह देखा गया है कि सोडा एश अत्यधिक सघन पूंजी युक्त होती है, कच्चे माल की लागत कम है और यह उच्च परिष्कृत उत्पाद भाड़ा उद्योग है। भाड़े की लागत, उत्पादन की लागत का बहुत अधिक प्रतिशत भाग बनती है। इसलिए इस मामले को विचाराधीन उत्पाद की विशेषताओं के आलोक में देखा जाना चाहिए।
- (13) जांच पश्चात अवधि में भारत में निर्यात कीमत में अत्यधिक गिरावट आई है।
- (14) रूपए के अवमूल्यन और विनिमय दर में परिवर्तन के मुद्दे के संबंध में निवेदन है कि रूपए के अवमूल्यन ने भी घरेलू उद्योग को प्रभावित किया है क्योंकि उसे चूना-पत्थर, कोयला, कोक आदि जैसे विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का आयात करना होता है। जबकि विनिमय दर में परिवर्तन हुआ है, फिर भी यदि भारतीय रूपयों में आयातों को देखा जाए तो इस समय वास्तव में घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर आयात हो रहे हैं।
- (15) केप्टिव खपत में गिरावट इस कारण से हुई है क्योंकि एक घरेलू उत्पादक कड़ी प्रतिस्पर्द्धा होने के कारण निचले स्तर के उत्पाद का उत्पादन नहीं कर सका है। गिरावट ने समग्र खपत पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है और यह घरेलू उद्योग की क्षति का एक कारण नहीं है। डिटरजेंट की समग्र खपत में वृद्धि हुई है और इस प्रकार डिटरजेंट के उत्पादन के लिए सोडा एश की खपत में कोई गिरावट नहीं आई है।
- (16) ऐसा दावा करने का कोई साक्ष्य अथवा आधार नहीं है कि पहुंच कीमत की तुलना क्षति रहित कीमत तथा एनएसआर की तुलना आयातित वस्तुओं की पुनःबिक्री की कीमत के साथ की जाए, जो कि आयात के पत्तन पर दर्शाए गए पहुंच मूल्य से अधिक थी।
- (17) नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ के संबंध में निवेदन है कि उद्योग द्वारा चलाए जा रहे संयंत्र अपकर्ष की स्थिति में हैं जो कि बहुत कम प्रतिलाभ अर्जित कर रहे हैं। चूंकि अचल परिसम्पत्तियां सही मूल्य को प्रदर्शित नहीं करती हैं, इसलिए घरेलू उत्पादकों ने नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का परिकलन करने के लिए निवेश के मूल्य के वर्तमान मूल्य पर विचार किया है।
- (18) वर्तमान प्रयोजनार्थ वित्तीय लेखाकरण में मालसूची के मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जा सकता है। ऐसा करना क्षति रहित कीमत के विशिष्ट नियमों के समनुरूप नहीं होगा, जिन पर इस समय विचार किया जाना चाहिए।
- (19) गुजरात में आयात कीमत तुलनीय है। उत्तर में कीमत अपेक्षाकृत अत्यधिक है और गुजरात में आयातों का हिस्सा, कुल आयातों के हिस्से से 5% से कम है।
- (20) इस तर्क के संबंध में कि पहुंच मूल्य को, सामान्यतया क्षति मार्जिन अथवा क्षति का मूल्यांकन करने के लिए क्षति रहित कीमत अथवा एनएसआर के साथ तुलना करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता सकता है, यह निवेदन किया जाता है कि केनिया से अधिकतर आयात, सीधे उपभोक्ताओं द्वारा किए जाते हैं।
- (21) लाभ मार्जिन को अनुचित माने जाने के संबंध में यह निवेदन किया जाता है कि निवेश करने वाला कोई भी व्यवसाय, कानूनी रूप से ऐसे प्रतिलाभ की आशा करेगा।
- (22) कीमत में 20% का समायोजन करने के आरोप के संबंध में निवेदन है कि घरेलू उद्योग का ऐसे समायोजन करने का कोई दावा नहीं है।
- (23) ऐसी संभावनाओं के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है कि ऐसे ग्रेड हो सकते हैं जो कि प्रतिस्थापनीय नहीं हैं।
- (24) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उत्पादक कुछ क्षेत्रों में आपूर्ति करने में असमर्थ हैं और इसलिए आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क प्रभारित नहीं किए जाने चाहिए, घरेलू उद्योग का यह मानना है कि इस कारणवश भाड़े को क्षति मार्जिन का निर्धारण करते समय जोड़ा जाना चाहिए।
- (25) कच्चे माल की उपलब्धता में घरेलू उद्योग की सन्निकटता के संबंध में निवेदन है कि ऐसी सन्निकटता ने उपभोक्ता के हितों के पक्ष में कीमत को कम किया है। कच्चे माल पर व्यय किए गए भाड़े की लागत पर उत्पादन की लागत और क्षति रहित कीमत के एक भाग के रूप में विचार किया जा रहा है, जिसका वहन उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है।
- (26) घरेलू उत्पादकों की निवेश करने की गंभीर इरादे हैं। लाभ की वर्तमान दर पर भी नए निवेश की राशि को 32 वर्षों में वसूल कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसको ध्यान में रखते हुए कि शुल्क तालिका में नामित निर्यातकों द्वारा निर्यात किए गए हैं, जांच अवधि के दौरान पाटन-रोधी शुल्कों की भारित औसत मात्रा 1200 रूपए प्रति मी.टन थी। इस प्रकार यदि घरेलू उद्योग को पाटन-रोधी शुल्क की मात्रा से अपनी कीमत को करना पड़ता है, तो भी इस समय किए जा रहे नए निवेशों की वसूली 34 वर्षों में हो जाएगी। इस प्रकार पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की संभावना में ऐसा समाविष्ट होगा कि इन निवेशों पर गंभीर रूप से पुनर्विचार किया जाए।

- (27) आईएचएस केमिकल ग्लोबल सोडा एश द्वारा सूचित की गई कीमत, विभिन्न देशों/क्षेत्रों में घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तुओं की प्रचलित कीमतों की एक अच्छी संकेतक है। इसके अतिरिक्त चूंकि जर्नल में उच्च और निम्न कीमतों का उल्लेख है, इसलिए घरेलू उत्पादकों ने औसत कीमत को अपनाया है।
- (28) आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि 32% थी और न कि 56%, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किया गया है।
- (29) घरेलू उद्योग द्वारा की गई कीमत वृद्धि 27% थी, जब कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा 65% वृद्धि होने का दावा किया गया है। ऐसा देश में उत्पाद के पाटन पर नियंत्रण रखने के कारण से है।
- (30) आयात से प्रतिस्पर्द्धा के कारण दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता काफी हानिकर है।
- (31) क्षति अवधि में समग्र मांग में वृद्धि हुई है। पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद क्षति अवधि में आयातों में वृद्धि हुई है।
- (32) उत्पादन की तुलना में आयातों में भी वृद्धि हुई है।
- (33) पाटन-रोधी शुल्क के प्रितसंहरण की स्थिति में कीमत अत्यधिक सकारात्मक होगी।
- (34) कच्चे माल की उपलब्धता के कारण एश के भारतीय उत्पादक गुजरात में अवस्थित हैं। पर्याप्त परिवहन लागतों के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना, परिवहन लागतों को जोड़ने के बाद ही आयातों की पहुंच कीमत के साथ की जानी चाहिए।
- (35) प्राधिकारी को इसका निर्धारण करना चाहिए कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत के साथ तुलना करने पर पाटित आयातों द्वारा कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है। शुल्कों को समय पूर्व समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप बाजार में कीमत में अत्यधिक कटौती होने की संभावना है।
- (36) पाटन-रोधी शुल्क लागू होने से इस समय कीमत ह्रास अथवा कीमत न्यूनीकरण नहीं हुआ है। तथापि, यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो पाटन होने के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर अत्यधिक ह्रास होने का प्रभाव पड़ेगा।
- (37) पाटन-रोधी शुल्क लागू किए जाने से उत्पादन और क्षमता उपयोग, लाभ, निवेशों पर प्रतिलाभ, नकदी प्रवाह के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार होना शुरू हुआ है। शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति की पुनरावृत्ति होगी।
- (38) मूल जांच में कारणात्मक संबंध होने की पहले से ही पुष्टि हो गई है। पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध देशों से पाटित आयातों में वृद्धि हुई है।
- (39) संबद्ध आयात घरेलू कीमतों से कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमताएं होने से ऐसा पता चलता है कि शुल्कों के प्रितसंहरण की स्थिति में पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है।
- (40) कीमत में कटौती होने के फलस्वरूप उपभोक्ता आयातित सामग्री प्राप्त करना पसंद करेंगे जिससे घरेलू उद्योग की बिक्रियां कम होंगी। इसके फलस्वरूप माल-सूचियों में वृद्धि होगी जिससे उत्पाद में गिरावट आएगी तथा क्षमता उपयोग और कम होगा।
- (41) कीमत के प्रभाव के संबंध में कीमत कटौती होने के फलस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसमें घरेलू उद्योग कीमतों में वृद्धि नहीं कर पाएगा जिससे उसकी लाभप्रदता में गिरावट आएगी। ऐसी गिरावट के फलस्वरूप सकल लाभ में गिरावट आएगी जिससे नकदी लाभ घटेगा जिसके परिणाम स्वरूप नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में और अधिक गिरावट आएगी।
- (42) विगत में प्राप्त किए गए स्तरों पर कच्चे माल के उपयोग और प्रयोज्यताओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि खपत में वृद्धि होने का कारण ऐसी इनपुट का अपर्याप्त उपयोग होना नहीं है, बल्कि इनपुट की वास्तविक परिस्थितियों में परिवर्तन होना है।
- (43) बाजार कीमत पर केप्टिव इनपुट पर विचार किया जाना चाहिए। वास्तविक कच्चा माल और प्रयोज्यताओं की खपत पर विचार किया जाना चाहिए। उत्पादन की काल्पनिक निम्न लागत के बजाए उत्पादन की वास्तविक लागत का निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि ऐसी कीमत का निर्धारण किया जा सके जिसकी तुलना आयात कीमत के साथ की जा सके जिससे क्षति मार्जिन का मूल्यांकन हो सके।
- (44) सहयोजित भाड़े को शामिल किए बगैर आयातों की पहुंच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना करने से उचित तुलना नहीं हो सकेगी और इसके फलस्वरूप उद्योग को हुई क्षति का सकल अनुमान कम होगा।
- (45) भाड़े की लागत, उत्पादन की लागत का एक भाग बनती है। घरेलू उद्योग फैक्टरी से डिपो/गोदामों तक वस्तुओं को ले जाने के लिए भाड़े की लागत का वहन करता है, जो कि फैक्टरी के गेटों तक बढ़ाया जाता है। वस्तुओं का स्वात्वाधिकार उत्पादकों के पास बना रहता है और उसे गोदामों से सामग्री की क्लीयरेंस पर ही क्रेताओं को अंतरित किया जाता है।

- (46) चूंकि सीमा शुल्क को क्षति रहित कीमत के साथ तुलना करने से पहले जोड़ा जाता है, यदि उसका भुगतान नहीं किया गया है, तो उसमें घरेलू उत्पाद पर उपगत अंतरदेशीय भाडे को भी जोड़ा जाना चाहिए। इसका अनुसरण सफेद सीमेंट के मामले में किया गया था और इसका अनुसरण वर्तमान जांच में भी किया जाना चाहिए।
- (47) घरेलू उद्योग द्वारा उपगत भाडे की लागत, विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों और भारतीय उद्योग द्वारा पेश की गई भुगतान की शर्तों में अत्यधिक अंतर जिसके फलस्वरूप आयात होते हैं, घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच करें और शुल्कों में विषमताएं, वर्तमान क्षति रहित कीमत विधि की मौजूदगी तथा उससे निकाला गया प्रतिपादन, क्षति रहित कीमत विधि के विद्यमान होने के बावजूद प्रमुख संघटकों पर सुव्यवस्थित पद्धति नहीं होने की स्थिति जैसे कारकों पर विचार नहीं किया जाना ऐसे कुछेक उदाहरण हैं, जो कि संरक्षण के ऐसे स्तर को जो कि पाटन-रोधी विधि के अंतर्गत घरेलू उद्योग प्राप्त करने का हकदार है, घटा कर पाटन-रोधी शुल्क की मात्रा पर पृथक रूप से और संचयी रूप से प्रभाव डालते हैं।
- (48) जांच अवधि और जांच पश्चात अवधि के दौरान भारत को संबद्ध देशों से निर्यातों की मात्रा से निर्यातों में और साथ ही पाटित कीमतों में व्यापक वृद्धि होने का पता चलता है। पाटन-रोधी शुल्कों को समय से पूर्व समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन न केवल निरंतर जारी रहेगा बल्कि उसमें गहन वृद्धि भी होगी।
- (49) विगत और वर्तमान पाटन का अत्यधिक स्तर विद्यमान है, जिसका निर्यातकों द्वारा प्रतिवाद नहीं किया गया है।
- (50) घरेलू उद्योग द्वारा सूचीबद्ध कीमतों पर भारी छूट दी जा रही है। इसलिए (छूट के बाद) बिक्री कीमत वास्तविक रूप से सूचीबद्ध कीमत से कम है।
- (51) घरेलू उद्योग द्वारा चलाए जा रहे संयंत्र अपकर्ष की स्थिति में हैं। एनएफए घरेलू उत्पादकों की परिसम्पतियों के सही मूल्य का प्रतिनिधिक नहीं करता है। प्राधिकारी को नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का परिकलन करने के लिए निवेश के वर्तमान मूल्य पर विचार करना चाहिए। निबल बही मूल्य पर घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित पूंजी, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त आंकड़ा नहीं है। नियोजित वर्तमान पूंजी 29,94,94.35 मी.टन की क्षमता के आधार पर है, जबकि 8 लाख मी.टन तक क्षमता का संवर्धन करने के लिए \*\*\* करोड़ रूपए का निवेश किया जा रहा है। इससे स्वतः स्पष्ट पता चलता है कि नियोजित वर्तमान पूंजी, घरेलू उद्योग द्वारा अपेक्षित प्रतिलाभ का निर्धारण करने के लिए विकट रूप से अपर्याप्त है।
- (52) पाटन-रोधी शुल्क के प्रतिसंहरण की स्थिति में कीमत में कटौती अत्यधिक सकारात्मक है। परिवहन लागत, उत्पादन की लागत का बहुत पर्याप्त भाग बनती है और इसका प्रभाव पर्याप्त है। इस प्रकार परिवहन लागतों को जोड़ने के बाद ही बिक्री कीमत की तुलना, आयातों की पहुंच कीमत के साथ की जानी चाहिए। नियम में ऐसी व्यवस्था निहित नहीं है कि कीमत में कटौती को कैसे निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है, इसलिए कीमत में कटौती का निर्धारण करने के लिए उचित प्रतिस्पर्द्धा के सिद्धांतों पर विचार करनेपर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- (53) विश्व व्यापार संगठन के समक्ष भारत की स्थिति भी ऐसी है कि आयातित उत्पाद की कीमत की तुलना, घरेलू उद्योग की कीमत के साथ जितनी बारीकी से संभव हो खपत के बिन्दु तक की जाए। यदि प्राधिकारी द्वारा इसे स्वयं लागू नहीं किया जाता है, तो यह घरेलू उद्योग के लिए विभेदकारी होगा।
- (54) विगत में प्राधिकारी ने विभिन्न कार्य प्रणालियां अपनाई हैं, जैसे कि उत्पाद किस्म वार (पीसीएन वार) कीमत में कटौती का निर्धारण, मासिक वार अथवा त्रैमासिक वार कीमत में कटौती का निर्धारण, बिक्री पश्चात व्यय - वारंटियों, गारंटियों, अनिवार्य अतिरिक्त पुर्जों, भारतीय कार्यालय व्यय का समायोजन, जिससे निदेशालय द्वारा मान्यता देने और उचित प्रतिस्पर्द्धा के सिद्धांतों को अपनाए जाने की स्वीकृति का पता चलता है।
- (55) कीमत में कटौती का निर्धारण करने का उद्देश्य पाटित आयातों के प्रभाव का निर्धारण करना है। इन कीमतों का अभिप्राय केवल उपभोक्ता के स्थल पर सुपुर्दगी कीमतों से है क्योंकि यही एक अकेला ऐसा स्थल है जहां पाटित आयात घरेलू उद्योग को प्रभावित करते हैं।
- (56) कीमत में कटौती होने और क्षति मार्जिन के परिप्रेक्ष्य में घरेलू उद्योग द्वारा भाडे के मुद्दे का खंडन किया जा रहा है, जबकि निदेशालय द्वारा क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के परिप्रेक्ष्य में इस पर विचार किया जा रहा है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए इस मुद्दे को अपवर्तित कर दिया गया है ताकि उनके दुर्भावपूर्ण हितों की रक्षा हो सके।
- (57) सफेद सीमेंट के मामले में प्राधिकारी ने मूल जांच के चरण में और साथ ही अंतिम निर्णायक समीक्षा जांच में कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए भाडे की लागत की स्वीकृति दी थी। तथापि, प्राधिकारी को यह विश्वास करने के लिए

भ्रमित कर दिया गया था कि भाडे की लागत, क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने का एक मुद्दा है और चूंकि भारत ने क्षति रहित कीमत की विधि को शुरू किया है, इसलिए क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए भाडे की लागत की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

#### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

52. प्राधिकारी ने क्षति पर हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और तर्कों के प्रत्युत्तरों को नोट किया है।
53. क्षति विश्लेषण में एक कारक के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा भाडे पर किए गए व्यय पर विचार करने के लिए घरेलू उद्योग के तर्कों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि सबसे पहले पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-III ऐसी पद्धति की अनुमति नहीं देता है। इसके अतिरिक्त सफेद सीमेंट के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच में प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम में उल्लेख किया गया है कि भाडे से संबंधित मामला सेस्टेट के समक्ष न्यायाधीन हैं। इसी प्रकार के मामले दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष भी विचाराधीन हैं।
54. यहां प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण से यथा तथ्यतः हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए विभिन्न तर्कों का समाधान हो जाता है।

#### **ज. संचयी मूल्यांकन**

55. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि:-
- क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत से कम है, जहां अलग-अलग देश का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है, वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक बनता है; तथा
- ख. आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।
56. इस संबंध में प्राधिकारी यह पाते हैं कि:
- i. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन के मार्जिन उपर्युक्त निर्धारित सीमाओं से अधिक हैं।
- ii. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है।
- iii. आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात में भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं से सीधे ही प्रतिस्पर्धा है। यह निम्नलिखित आधार पर पुष्ट है:
- क. विभिन्न संबद्ध देशों से और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए संबद्ध सामान समान वस्तुएं हैं।
- ख. यहां समान पक्षकार हैं जो विभिन्न स्रोतों और घरेलू सामग्री से आयातित सामग्री के इस्तेमाल का सहारा ले रहे हैं। अतः आयातित और घरेलू सामग्री परस्पर परिवर्तनीय रूप से इस्तेमाल की जा रही हैं और घरेलू उत्पाद तथा आयातित उत्पाद के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा है।
- ग. संबद्ध देशों और घरेलू उद्योग से निर्यातकों ने समान ग्राहकों को समान अवधि में समान उत्पाद बेचे हैं। बिक्री चैनल तुलनीय है।
- घ. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा काफी है।
- ङ. ग्राहक विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पेश की गई कीमतों के आधार पर खरीददारी का निर्णय लेते हैं।
57. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी आयातित उत्पाद और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में घरेलू उद्योग पर चीन जन गण, यूरोपीय संघ, केन्या, ईरान, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त मानते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन की मात्रा और संबद्ध देशों से आयात की मात्रा उपर्युक्त निर्धारित सीमाओं से अधिक है।
58. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखा है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह उपबंध है कि क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच का प्रावधान है। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव की जांच करते समय प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना होता है कि क्या पाटित

आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी होती है कि क्या पाटित आयातों से भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक हो गई होती।

59. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II का पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लिखित है:

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन शामिल है, जिनमें लाभ, आउटपुट, मार्केट शेयर, उत्पादकता, निवेश पर वापसी या क्षमता का उपयोग, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, वास्तविक पाटन मार्जिन की मात्रा और नकदी प्रवाह पर संभावित ऋणात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, संवृद्धि, पूंजीगत निवेशों को जुटाने की क्षमता सम्मिलित है।"

60. भारत में घरेलू आयातों के प्रभाव की जांच के लिए प्राधिकारी ने उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले अन्य ऐसे तथ्यों पर नियमावली के अनुबंध-III(iv) के अनुसार विचार किया है, जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि।
61. प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए बारीकी से क्षति मानदंडों की जांच की है। क्षति मानदंडों को औपचारिक रूप देते हुए घरेलू उद्योग के तुलन पत्र सहित सभी संगत दस्तावेजों की जांच की गई है और प्राधिकारी द्वारा उन्हें सत्यापित किया गया है। भारतीय उद्योग के हितों से संबंधित मुद्दों और अन्य मुद्दों को भी प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त शीर्षों के अंतर्गत लिया गया है।

#### मांग एवं बाजार हिस्सा

62. संबद्ध सामानों के घरेलू उपभोग/मांग के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग तथा अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री की मात्रा को भारत कुल आयात में शामिल कर लिया गया है और उसे नीचे संक्षिप्त रूप में दिया गया है:

विवरण	यूओएम	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई (2014-15)	पीओआई के पश्चात वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	14,31,825	15,19,990	15,78,148	16,01,302	16,45,357
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	110	112	115
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी. टन	7,51,493	7,26,475	7,37,588	7,55,169	7,59,164
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	98	100	101
कुल घरेलू बिक्री + कैप्टिव अंतरण	मी. टन	21,83,318	22,46,466	23,15,737	23,56,471	24,04,521
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	106	108	110
आयात – संबद्ध देश	मी. टन	3,29,828	5,53,416	4,89,270	6,73,706	6,94,779
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	168	148	204	211
आयात – शुल्क लगाने वाले अन्य देश	मी. टन	1,10,695	1,19,014	62,103	49,071	38,611
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	56	44	35
आयात – अन्य देश	मी. टन	3,952	19,799	16,214	1,201	2,246
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	501	410	30	57
कुल मांग (कैप्टिव अंतरण सहित)	मी. टन	26,27,793	29,38,694	28,83,324	30,80,449	31,40,157
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	110	117	119
घरेलू उद्योग	%	54.49	51.72	54.73	51.98	52.40
अन्य भारतीय उत्पादक	%	28.60	24.72	25.58	24.51	24.18
समग्र रूप में भारतीय उत्पादक	%	83.09	76.44	80.31	76.50	76.57
संबद्ध देश	%	12.55	18.83	16.97	21.87	22.13

विवरण	यूओएम	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई (2014-15)	पीओआई के पश्चात वार्षिकीकृत
शुल्क लगने वाले अन्य देश	%	4.21	4.05	2.15	1.59	1.23
अन्य देश	%	0.15	0.67	0.56	0.04	0.07
मांग	%	12.55	18.83	16.97	21.87	22.13
भारतीय उत्पादन	%	14.00	23.44	20.95	27.87	28.10

टिप्पणी : जांच की अवधि के बाद (अप्रैल, 15 से सितंबर, 15)

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बढ़ी है। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान मांग में वृद्धि 17 प्रतिशत थी। मांग में जांच की अवधि के बाद (अप्रैल, 15 से सितंबर, 15) के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाती है।

#### ट. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

##### आयात मात्रा एवं बाजार हिस्सा

64. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना होता है कि क्या भारत में समग्र रूप से अथवा उत्पादन या उपभोग की दृष्टि से पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएस से प्राप्त किए गए आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात की मात्रा का विश्लेषण नीचे किया गया है:

विवरण	यूओएम	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई (2014-15)	पीओआई के पश्चात (अप्रैल, 15 से सितंबर, 15)	पीओआई के पश्चात वार्षिकीकृत
आयात मात्रा							
चीन	मी. टन	3,307	1,18,277	98,735	1,25,589	37,105	74,210
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	3,576	2,986	3,798	1,122	2,244
यूरोपीय संघ	मी. टन	98,968	1,86,264	1,89,139	2,43,032	1,16,264	2,32,528
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	188	191	246	117	235
केन्या	मी. टन	1,58,255	1,43,093	1,62,244	1,31,656	60,524	1,21,047
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	103	83	38	76
पाकिस्तान	मी. टन	24,108	19,989	16,948	37,447	19,520	39,040
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	70	155	81	162
ईरान	मी. टन	5,276	9,040	-	5,427	7,742	15,483
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	171	-	103	147	293
उक्रेन	मी. टन	39,913	12,305	196	43,276	27,083	54,165
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	31	0	108	68	136
संयुक्त राज्य अमेरिका	मी. टन	—	64,447	22,009	87,279	79,153	1,58,306
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	—	100	34	135	123	246
संबद्ध देश	मी. टन	3,29,828	5,53,416	4,89,270	6,73,706	3,47,389	6,94,779
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	168	148	204	105	211
शुल्क लगने वाले अन्य	मी. टन	1,10,695	1,19,014	62,103	49,071	19,305	38,611



विवरण	यूओएम	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई (2014-15)	पीओआई के पश्चात (अप्रैल, 15 से सितंबर, 15)	पीओआई के पश्चात वार्षिकीकृत
देश							
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	56	44	17	35
अन्य देश	मी. टन	3,952	19,799	16,214	1,201	1,123	2,246
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	501	410	30	28	57
कुल आयात	मी. टन	4,44,475	6,92,228	5,67,587	7,23,978	3,67,818	7,35,636
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	156	128	163	83	166
<b>बाजार हिस्सा</b>							
चीन	%	0.74	17.09	17.40	17.35	10.09	10.09
यूरोपीय संघ	%	22.27	26.91	33.32	33.57	31.61	31.61
केन्या	%	35.60	20.67	28.58	18.19	16.45	16.45
पाकिस्तान	%	5.42	2.89	2.99	5.17	5.31	5.31
ईरान	%	1.19	1.31	-	0.75	2.10	2.10
उक्रेन	%	8.98	1.78	0.03	5.98	7.36	7.36
संयुक्त राज्य अमेरिका	%	0.00	9.31	3.88	12.06	21.52	21.52
संबद्ध देश	%	74.21	79.95	86.20	93.06	94.45	94.45
शुल्क लगाने वाले अन्य देश	%	24.90	17.19	10.94	6.78	5.25	5.25
अन्य देश	%	0.89	2.86	2.86	0.17	0.31	0.31
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि क्षति अवधि के आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात में समग्र वृद्धि हुई है। तथापि, गहन विश्लेषण से यह बात सामने आती है कि 3 प्रमुख उत्पादक संबद्ध देशों (चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय यूनियन) में से दो देशों अर्थात् चीन और यूरोपीय संघ में जांच अवधि के बाद की अवधि में आयात में घटती हुई प्रवृत्ति सामने आयी है। यहां तक कि समग्र आधार पर (सभी संबद्ध देशों को एक साथ लेकर) जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयात में केवल 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

#### ठ. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

66. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना होता है कि क्या पाटित आयातों से भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक हो गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच घटती हुई कीमतों, कम कीमत पर बिक्री, कीमत दबाव और कीमत ह्रास के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) तथा गैर क्षतिकारक कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयात की पहुँच लागत के साथ की गई है।

#### पाटित आयातों के कीमत दबाव एवं ह्रास प्रभाव

67. पाटित आयातों के कीमत दबाव एवं ह्रास की जांच भी, जांच की अवधि तथा जांच के बाद की अवधि सहित क्षति अवधि के संदर्भ में संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पहुँच मूल्य, उत्पादन लागत तथा निवल बिक्री वसूली के संदर्भ में की गई है।

विवरण	यूओएम	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई	पीओआई के पश्चात
संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	12,939	15,135	15,203	16,820	17,482
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	117	130	135
बिक्री की लागत	रु./मी. टन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	110	106	102
बिक्री कीमत	रु./मी. टन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	113	123	125

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री कीमत वर्ष दर वर्ष निरंतर बढ़ी है जिसने यह सिद्ध किया है कि घरेलू बिक्री कीमत पर कीमत न्यूनीकरण प्रभाव का स्पष्ट अभाव रहा है। जहां तक पाटित आयात के कारण कीमत न्यूनीकरण प्रभाव का संबंध है, उसमें भी कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं है। यद्यपि, 2012-13 में बिक्री कीमत में वृद्धि आयातों के पहुंच मूल्य में वृद्धि के अनुपात में नहीं रही है तथापि, बाद के वर्षों में उसमें उच्च तुलनात्मक वृद्धि दर्ज की है।

### कीमत कटौती

69. घरेलू उद्योग की कुल बिक्री वसूली निकालते समय घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई छूट, रियायत और कमीशन तथा दिया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटा दिया गया है। जैसा कि प्रत्येक उत्तरदायी निर्यातक ने सूचित किया है, संबद्ध देशों से सीआईएफ कीमतों पर शिक्षा उप-कर तथा लागू आधारभूत सीमा शुल्क एवं 1 प्रतिशत पहुँच प्रभार जोड़कर, आयातों का पहुँच मूल्य परिकलित किया गया है। अन्य श्रेणी के लिए डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों के अनुसार मूल्यांकनयोग्य मूल्य पर शिक्षा उप-कर तथा लागू आधारभूत सीमा शुल्क जोड़कर पहुँच कीमत का परिकलन किया गया है। घरेलू उद्योग ने कहा है कि कीमत कटौती के निर्धारण के लिए भाड़ा शामिल किया जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री कीमत से भाड़ा अलग करने के बाद मूल जांच के समय विचाराधीन उत्पाद का निर्धारण किया गया था और वर्तमान समीक्षा केवल मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधिक समीक्षा है। अतः प्राधिकारी ने कीमत कटौती का निर्धारण फैक्ट्री के बाहर के स्तर पर घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर विचार करके जारी रखा है।

विवरण	यूनिट	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई	पीओआई के पश्चात
<b>चीन</b>						
आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	14,048	14,985	14,126	17,174	16,990
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	रु./मी. टन	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	%	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	% रेंज	0-5	5-10	10-15	5-10	5-10
<b>यूरोपीय संघ</b>						
आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	12,660	15,716	16,148	17,229	18,606
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	रु./मी. टन	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	%	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	% रेंज	10-15	0-5	0-5	0-5	नकारात्मक
<b>केन्या</b>						
आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	12,714	15,222	14,805	15,618	16,969
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	रु./मी. टन	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	%	****	****	****	****	****

विवरण	यूनिट	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई	पीओआई के पश्चात
कीमत कटौती	% रेंज	10-15	0-5	10-15	10-15	5-10
<b>पाकिस्तान</b>						
आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	14,384	17,288	18,023	19,033	19,958
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	रु./मी. टन	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	%	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	% रेंज	0-5	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक
<b>ईरान</b>						
आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	14,150	14,317	-	16,598	16,517
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	****	****	-	****	****
कीमत कटौती	रु./मी. टन	****	****	-	****	****
कीमत कटौती	%	****	****	-	****	****
कीमत कटौती	% रेंज	0-5	10-15		5-10	10-15
<b>उक्रेन</b>						
आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	13,400	16,741	17,473	17,086	17,524
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	रु./मी. टन	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	%	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	% रेंज	5-10	नकारात्मक	नकारात्मक	5-10	0-5
<b>संयुक्त राज्य अमेरिका</b>						
आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	11,265	12,682	12,660	15,915	15,922
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	रु./मी. टन	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	%	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	% रेंज	20-25	20-25	20-25	10-15	10-15
<b>समग्र रूप में संबद्ध देश</b>						
आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	12,939	15,135	15,203	16,820	17,482
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	रु./मी. टन	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	%	****	****	****	****	****
कीमत कटौती	% रेंज	10-15	5-10	5-10	5-10	0-5

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, जांच की अवधि और जांच की अवधि की बाद की अवधि सहित कीमत कटौती सकारात्मक है तथापि, यदि बारीकी से नजर डालें तो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती पिछले वर्ष की तुलना में वास्तव में कम हुई है और यूरोपीय यूनियन केन्या, पाकिस्तान और यूक्रेन के लिए जांच की अवधि की तुलना में जांच की अवधि के बाद की अवधि में कम हुई है।

**ड. घरेलू उद्योग के अन्य आर्थिक मानदंडों की जांच**

**उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग**

71. उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

विवरण	यूओएम	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई	पीओआई के पश्चात वार्षिकीकृत
संस्थापित क्षमता	मी. टन	19,61,000	19,61,000	19,61,000	19,61,000	20,31,000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100	104
उत्पादन	मी. टन	15,78,674	16,11,377	16,02,002	16,45,154	16,96,272
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	101	104	108
क्षमता उपयोग	%	80.50%	82.17%	81.69%	83.89%	83.52%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	101	104	104
घरेलू बिक्री	मी. टन	12,67,561	13,86,286	14,66,643	15,03,224	15,36,499
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	116	119	122
मांग	मी. टन	26,27,793	29,38,694	28,83,324	30,80,449	31,40,157
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	110	117	119

72. उपर्युक्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की क्षमता जांच की अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है। तथापि, बिक्री और क्षमता उपयोग, दोनों मांग में वृद्धि के अनुरूप आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बढ़े हैं।

### मालसूची

73. मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित रूप में दर्शाए गए हैं:

विवरण	यूओएम	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई	पीओआई के पश्चात
प्रारंभिक	मी. टन	****	****	****	****	****
अंतिम	मी. टन	****	****	****	****	****
औसत	मी. टन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	101	73	122

यह नोट किया जाता है कि औसत मालसूची कमोवेश जांच की अवधि से पूर्व स्थिर रही है, फिर जांच की अवधि में घटती हुई दिखाई दी है तथा फिर जांच की अवधि के बाद बढ़ती हुई दिखाई दी है।

### नकद प्रवाह पर लाभ तथा वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

74. जहां तक लाभ/हानि तथा नकद प्रवाह का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता कर पूर्व लाभ तथा व्याज एवं नकद लाभ के संदर्भ में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में अत्यधिक बढ़ी है। इस स्थिति में जांच की अवधि के बाद की अवधि में और भी अधिक सुधार आया है। निवेश पर आय में भी काफी वृद्धि हुई है और जांच की अवधि के बाद उसमें और सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग का यह कहना है कि प्राधिकारी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि: (क) वर्तमान परिसंपत्तियों में काफी मूल्य हास हुआ है और निवल अचल परिसंपत्तियों के मूल्य उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, (ख) घरेलू उद्योग ने काफी निवेश करके क्षमता बढ़ाई है। तथापि, प्राधिकारी ने लाभ, नकद लाभ तथा आरओआई का निर्धारण अपनी स्थिर परिपाटी के आधार पर किया है। फिर भी प्राधिकारी नोट करते हैं कि भावी निवेश विगत क्षति तथा निवेश पर आय का निर्धारण करने के लिए संगत नहीं है।

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई	पीओआई के पश्चात वार्षिकीकृत
बिक्री की लागत	रु./मी. टन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	110	106	102
बिक्री कीमत	रु./मी. टन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	113	123	125
लाभ/हानि	रु./मी. टन	****	****	****	****	****

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई	पीओआई के पश्चात वार्षिकीकृत
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	176	146	293	356
लाभ/हानि	रु. लाख	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	193	169	347	432
पीबीआईटी	रु. लाख	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	133	215	256
नकद लाभ	रु. लाख	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	168	153	270	342
निवेश पर लाभ	%	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	140	233	279

### रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

75. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं:

विवरण	यूओएम	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई	पीओआई के पश्चात वार्षिकीकृत
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	99	102	105
कर्मचारी	संख्या	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	103	102	102
मजदूरी	रु. लाख	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	113	117	133

76. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तथापि, 2012-13 से मजदूरी और कर्मचारियों की उत्पादकता के संबंध में निरंतर बढ़ती हुई प्रवृत्ति रही है।

### ढ. पाटन की मात्रा

77. पाटन मार्जिन से संबंधित खंड में यह पाया गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटन मार्जिन जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक और पर्याप्त हैं तथा जांच के अवधि के बाद की अवधि में भी सकारात्मक रहे हैं।

### वृद्धि

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री कीमत, लाभप्रदता और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि जांच की अवधि के दौरान तथा जांच की अवधि के बाद सकारात्मक थी। जांच की अवधि के बाद के दौरान इन मानदंडों में वृद्धि घरेलू उद्योग के क्षति की संभावना के तर्क को कमजोर करती है।

### निधियां जुटाने की योग्यता

79. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष से लेकर जांच की अवधि तक संबद्ध सामानों के उत्पादन में अपनी क्षमता नहीं बढ़ाई है। तथापि, घरेलू उद्योग इस समय काफी पूंजीगत निवेश कर रहा है और उसने अपनी क्षमताएं बढ़ाने में \*\*\*\* करोड़ रुपयों के कुल निवेश की योजना बनाई है। यह दर्शाता है कि पूंजी निवेश जुटाने में उनकी योग्यता प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुई है।

**ण. वास्तविक क्षति से संबंधित निष्कर्ष**

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान यद्यपि, उत्पादन की क्षमता पूरी क्षति अवधि में स्थिर रही है, तथापि, घरेलू उद्योग का निष्पादन उत्पादन, बिक्री मात्रा, लाभ, नकद प्रवाह, लगाई गई पूंजी पर आय तथा मालसूची के संदर्भ में सुधरा है। जांच की अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में बाजार हिस्से में कमी आई है। जांच की अवधि के बाद के दौरान आर्थिक मानदंड बाजार हिस्से में बढ़ी हुई प्रवृत्ति सहित सतत सुधार दर्शाते हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड उनको भी कोई क्षति नहीं दर्शाते हैं। यहां तक कि घरेलू उद्योग ने भी स्वीकार किया है कि उसे वर्तमान अवधि में क्षति नहीं हुई थी।

**त. अन्य ज्ञात कारक एवं कारणात्मक संबंध**

81. भारतीय नियमावली और पाटनरोधी करार में सूचीबद्ध अन्य संकेतात्मक मानदंडों, कीमत कटौती तथा कीमत दबाव एवं ह्रास के प्रभाव की दृष्टि से घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और क्षति तथा मात्रा की स्थिति की जांच करने के बाद प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित रूप में यह जांच की गई कि क्या पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है:

**(क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा तथा कीमतें**

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों के अलावा अन्य देशों तथा पाटनरोधी शुल्क लगने वाले देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात मात्रा में बहुत कम रहे हैं।

**(ख) मांग में कमी तथा उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन**

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान मांग में कोई कमी नहीं हुई है। इसके विपरीत, जांच की अवधि के दौरान तथा जांच की अवधि के बाद की अवधि में भी संबद्ध सामानों के लिए समग्र मांग में सुधार हुआ है।

**(ग) प्रौद्योगिकी में विकास**

प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में ऐसे कोई परिवर्तन दर्शाने का कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

**(घ) व्यापार की प्रतिबंधात्मक परिपाटियां तथा विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा**

प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामान स्वतंत्र रूप से आयात किए जा सकते हैं। घरेलू उद्योग संबद्ध सामानों का बड़ा उत्पादक है तथा उसका घरेलू उत्पादन और बिक्री में भारी हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादकों के बीच कोई मान्य प्रतिस्पर्धा नहीं है, सिवाय बाजार अर्थव्यवस्था को छोड़कर, जो कि स्पष्ट है।

**(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन**

घरेलू उद्योग के निर्यात के संबंध में उनका निष्पादन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूओएम	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई	पीओआई के पश्चात वार्षिकीकृत
निर्यात	मी. टन	186279	51342	63660	25255	14043
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	28	34	14	8

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निर्यात भारी मात्रा में कम हुआ है। घरेलू उद्योग ने मूल जांच के समय यह कहा है कि देश में उत्पाद के पाटन को देखते हुए वे उत्पाद का निर्यात करने के लिए मजबूर था, जैसा कि प्राधिकारी ने मूल जांच के अंतिम निष्कर्षों के पैरा 146 में रिकार्ड किया है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर घरेलू उद्योग घरेलू बिक्री बढ़ा पाया और निर्यात को कम कर पाए।
83. उपर्युक्त विश्लेषण से प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो सूचीबद्ध ज्ञान मानदंड और न ही ऊपर विश्लेषित किए गए अन्य कारक यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान या जांच की अवधि के बाद के समय में निरंतर कोई क्षति हुई है। घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

**थ. क्षति जारी रहने की संभावना अथवा होते रहने की संभावना**

84. तथापि, एक समीक्षा जांच में प्राधिकारी को यह निर्धारित करना है कि क्या संबद्ध सामान भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर आते जा रहे हैं या आते रहने की संभावना है तथा क्या यदि शुल्क हटा दिया जाए या अलग-अलग लिखे जाएं, तो इन पाटित

आयातों के कारण भारतीय उद्योग को क्षति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-II (vii) के संदर्भ में वास्तविक क्षति खतरे से संबंधित मानदंडों पर विचार करते हुए पाटन और क्षति पुनः होने अथवा उसके जारी रहने की संभावना की जांच की है।

*“वास्तविक क्षति की आशंका का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा और न कि आरोप, निराधार कल्पना या सुदूर संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन जिनसे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिनमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए और आसन्नवर्ती होने चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों पर विचार करेंगे और;*

- (क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अधिक दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।
- (ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।
- (ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी हासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है तथा
- (घ) उस वस्तु की वस्तु सूची की जांच की जा रही हो।”

#### **आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

85. आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. जिन परिस्थितियों में निर्यातक पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, उनमें बहुत टिकाऊ प्रवृत्ति के काफी परिवर्तन हुए हैं और स्थिति मौजूदा पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की बनती है क्योंकि वर्तमान शुल्क हटाए जाते हैं अथवा उनमें अंतर किया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा पुनः होते रहने की संभावना नहीं है।
- ii. घरेलू उत्पादकों की यह समझ कि शुल्क तब तक वापस नहीं लिया जा सकता जब तक कि पाटन बंद न हो जाए अथवा यह कि पाटन होते रहने की कोई संभावना नहीं है, सही नहीं है। यदि घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना न हो तो शुल्क वापसी कानूनी रूप से अपेक्षित है।
- iii. घरेलू उद्योग ने इन साक्ष्यों के आधार पर अनुरोध का निष्कर्षस्वरूप विरोध किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा होते रहने की संभावना नहीं है, यदि उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क हटाया जाए अथवा उसमें अंतर किया जाए, जो कि यह दर्शाता है कि कोई संभावना भी नहीं है।
- iv. यह दर्शाने के लिए भी कोई साक्ष्य नहीं है कि संबद्ध देशों में निर्यातकों के पास पर्याप्त रूप से मुक्त निपटान योग्य अथवा आसन्न, निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि है जो भारतीय बाजार में पर्याप्त रूप से बढ़े हुए निर्यात की संभावना दर्शाए।
- v. वर्तमान मामले में आयात की पहुँच कीमत, गैर क्षतिकारक कीमत और क्षति मार्जिन जैसे महत्वपूर्ण मामलों में काफी परिवर्तन आए हैं। उपर्युक्त तथ्यों से जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार बन जाते हैं तथा यह भी सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के लगाए जाने से निरंतर होने अथवा होते रहने की संभावना नहीं है।
- vi. घरेलू उत्पादकों को गैर सहकारी माना जाए तथा जांच की अवधि आरंभ होने की तारीख से ही तत्काल रूप से शुल्क वापस ले लिया जाए। घरेलू उत्पादक आयात की मात्रा और मूल्य से प्रभावित नहीं हैं; अतः यदि पाटनरोधी शुल्क वापस लिया जाता है तो कोई क्षति होने अथवा होते रहने की कोई संभावना नहीं है। यह तथ्य कि प्रमुख घरेलू उत्पादक भी संबद्ध सामानों का आयात कर रहा है, भी इस निष्कर्ष का समर्थन करता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- vii. ओलंपिया का वर्तमान जांच में पूरे संबद्ध देशों में न्यूनतम शुल्क है। इस स्थिति के बाद ही यदि निर्यातक ने भारत में अपनी मात्रा नहीं बढ़ाई और निरंतर कीमतें बढ़ाता रहा तो यह स्पष्ट रूप से टिकाऊ प्रकृति की परिस्थिति में परिवर्तन दर्शाता है तथा यह कहने के लिए कोई स्थिति नहीं है कि निर्यातक शुल्क हटाने पर अधिक निर्यात करेंगे। ओलंपिया से कोई वर्तमान अथवा संभावित निर्यात नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो। ओलंपिया से संबंधित शुल्क को हटाए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने अथवा बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।

- viii. ओलंपिया 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत स्तर के उपयोग पर चल रहा है जो कि इष्टतम स्तर के ऊपर है। इसके अतिरिक्त, निर्यात मात्रा घटी है, परंतु निर्यात कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। अतः उन पर किसी भी सस्ती दर पर सामग्री का निपटान करने का कोई मात्रात्मक दबाव नहीं है और न ही उसके पास आसन्न रूप से कोई नई अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध है।
- ix. ओलंपिया की निर्यात कीमत भारत में पहुँच स्तरों पर निरंतर बढ़ी जा रही थी और घरेलू उद्योग की एनआईपी से अधिक रही है जिससे नकारात्मक क्षति मार्जिन हुआ है जो घरेलू कीमतों पर काफी दबाव के किसी भी प्रभाव को नकारता है। कंपनी के पास कोई महत्वपूर्ण मालसूची स्तर भी नहीं है। ओलंपिया से निर्यात की स्थिति काफी परिवर्तित हुई है और यदि ओलंपिया पर वर्तमान शुल्क हटाए जाते हैं अथवा उसमें अंतर किया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना नहीं है। इस प्रकार, प्राधिकारी उसकी वापसी की सिफारिश कर सकते हैं।
- x. घरेलू उद्योग की बिक्री वसूली सहित निर्यातक देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संबद्ध सामानों की कीमतों में परिवर्तन को टिकाऊ प्रकृति की जांच के लिए विचार में रखा जाना चाहिए क्योंकि संबद्ध सामानों की कीमतों में परिवर्तनों को विश्व बाजार में दर्शाया जाता है और भारत को निर्यात कीमत में वृद्धि एक मात्र घटना नहीं है।
- xi. इसके अतिरिक्त, यदि शुल्क हटाए जाते हैं तो निर्यातक भारत में मांग एवं आपूर्ति के वर्तमान अंतर के कारण कीमतें और बढ़ाने जा रहे हैं। घरेलू उद्योग शुल्क लगाए जाने के कई वर्षों के बाद भी तथा पूरी क्षति अवधि में लगभग 80 प्रतिशत क्षमता उपयोग होने के बावजूद भारतीय मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं।
- xii. प्राधिकारी को अनुबंध-II की शर्तों का पालन करने के लिए, निर्यातकों के संबंध में वेशी क्षमता और मालसूची की जांच करनी होती है। ऋषिरूप पॉलीमर प्रा. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मद्देनजर यह माना गया है कि जांच के विभिन्न मानदंडों में परिवर्तन के संबंध में प्राप्त सूचना तक सीमित हो। अतः प्राधिकारी जांच के किसी भी पहलू के संबंध में अपर्याप्त अथवा सूचना न होना नोट कर सकते हैं।
- xiii. इसके अतिरिक्त, विदेशी क्षमता में गिरावट आई है, यथा – चीन में सोडा ऐश उत्पादक होउ प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण चीन सोडा ऐश का "आयातक" बन गया है, टाटा केमिकल मगादी – केन्या ने 5 लाख टन क्षमता वाले अपने एक संयंत्र को बंद कर दिया है, सोलवे ने यूरोप में अपने दो संयंत्र बंद कर दिए हैं। जीएचसीएल ने रोमानिया में अपना संयंत्र बंद कर दिया है।
- xiv. सोडा ऐश उपभोग वैश्विक रूप से 2-2.25 प्रतिशत की दर पर बंट रहा है और वैश्विक उत्पादन 55 मिलियन मी. टन है। अतः जो भी उत्पादित किया जाता है उसका उपभोग हो जाता है जिससे मांग को पूरा करने के लिए वार्षिक रूप से 1.25-1.50 मी. टन अतिरिक्त सोडा ऐश की और आवश्यकता होती है।
- xv. पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन क्षतिकारक पाटन के व्यापार नष्ट करने वाले प्रभाव को समाप्त करना है न कि उम्मीद की गई क्षमता अभिवृद्धि का संरक्षण करने के लिए शुल्क को जारी रखना है।
- xvi. वास्तविक क्षति के खतरे और क्षति की संभावना का मामला पाटनरोधी करार स्पष्ट रूप से भिन्न बात है तथा उन्हें साथ-साथ एक ही तराजू में नहीं रखा जा सकता। नियमावली समीक्षा के संदर्भ में अनुबंध-II के पैरा (vii) के सिद्धांतों के संबंध में बात नहीं करती। प्राधिकारी को चाहिए कि वे वर्तमान मामले में उपर्युक्त सिद्धांतों को अपनाना अनिवार्य न बनाएं।

### घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

86. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. याचिकाकर्ता को संभावनाओं पर सूचना देनी थी तथा इस संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य भी प्राधिकारी को नहीं दे पाया है। जांच शुरू करते समय संगत मानदंडों से संबंधित साक्ष्य दिए ही जाने चाहिए थे।
- ii. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार का संबंध है, निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया इस बात की जांच करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने से घरेलू उद्योग को पहले से संस्थापित क्षमताओं तथा प्रचालनात्मक क्षमताओं, जो अभी तक संस्थापित नहीं हुई है परंतु निकट भविष्य में प्रचालनात्मक हो जाएंगी, दोनों के संबंध में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
- iii. पूर्व की जांचें तथा वर्तमान जांच में निर्धारित क्षति मार्जिन काफी है। काफी सकारात्मक पाटन मार्जिन से स्वतः पाटनरोधी शुल्क जारी रखना आवश्यक हो जाता है।



- iv. वास्तविक क्षति के खतरे की जांच के लिए निर्धारित मानदंड वस्तुतः यह दर्शाते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की समय पूर्व वापसी की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
- v. सिंगापुर से पॉलीप्रॉपिलिंग, चीन जन गण से कॉमरिन, चीन जन गण से जिंक ऑक्साइड, चीन जन गण से फ्रंट एक्सल बीम तथा स्टेयरिंग नकल्स, चीन जन गण से क्लोरोफिन फॉस्फेट, चीन जन गण से डिक्लोफेनक सोडियम, यूरोपीय संघ, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका से एसिटोन पर मामलों के लिए समीक्षा जांच में पाटन मार्जिन नकारात्मक पाया गया था। तथापि, इन मामलों में शुल्क बढ़ाया गया था।
- vi. एसिटोन और फेनल समीक्षा मामलों के संदर्भ दिया जाता है जिनमें जांच की अवधि में भारत के लिए जांच की अवधि में नकारात्मक क्षति मार्जिन तथा तीसरे देशों के लिए सकारात्मक क्षति मार्जिन निर्धारित किए गए थे और इस प्रकार शुल्क बढ़ाए गए थे।
- vii. पॉलीप्रॉपिलिंग समीक्षा मामले का संदर्भ दिया गया था जिसमें भारत के लिए जांच की अवधि में नकारात्मक क्षति मार्जिन, भारत के लिए जांच की अवधि के बाद में नकारात्मक क्षति मार्जिन तथा जांच की अवधि के बाद में तीसरे देशों के लिए सकारात्मक क्षति मार्जिन निर्धारित किए गए थे और इस प्रकार शुल्क बढ़ाए गए थे।
- viii. ताइवान से डक्टाइल आयरन पाइप्स, कास्टिक सोडा, कोरिया से पैटेशियम कार्बोनेट की समीक्षा मामले का संदर्भ दिया गया था जिसमें भारत और तीसरे देशों के लिए जांच की अवधि में नकारात्मक क्षति मार्जिन, भारत और तीसरे देशों के लिए जांच की अवधि के बाद में नकारात्मक क्षति मार्जिन निर्धारित किए गए थे तथा भारत अथवा तीसरे देशों को क्षतिकारक निर्यात की मात्रा काफी पाई गई थी और इस प्रकार शुल्क बढ़ाए गए थे।
- ix. परसल्फेट, विटामिन ई, सोडियम फॉर्मेलिहाइड, सल्फॉक्साइड, पीवीसी, फ्लेक्स फिल्म, फेनल समीक्षा मामलों का संदर्भ दिया गया था जिसमें भारत के लिए जांच की अवधि में सकारात्मक क्षति मार्जिन, तीसरे देशों के लिए जांच की अवधि के बाद में सकारात्मक क्षति मार्जिन निर्धारित किए गए थे और इस प्रकार शुल्क बढ़ाए गए थे।
- x. चीन से सफेद सीमेंट, जिंक ऑक्साइड का संदर्भ दिया गया था जिसमें भारत और तीसरे देशों के लिए जांच की अवधि में नकारात्मक क्षति मार्जिन, भारत के लिए जांच की अवधि के बाद में नकारात्मक क्षति मार्जिन, तीसरे देशों के लिए जांच की अवधि के बाद में नकारात्मक क्षति मार्जिन निर्धारित किए गए थे और इस प्रकार शुल्क रद्द किए गए थे।
- xi. जब भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मध्यावधि समीक्षाओं नकारात्मक क्षति मार्जिन पाया, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नियम 23(1)(क) के तहत एक अनिवार्य मामले के रूप में जांच की कि यदि उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क वापस लिया जाता है, तो क्या घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है अथवा नहीं।
- xii. कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेसटेट ने माना है कि ऐसी स्थिति में, जिसमें भारित औसत क्षति मार्जिन नकारात्मक हो, प्राधिकारी को उन निर्यातों की मात्रा पर विचार करना होता है जो एनआईपी से कम हो। यह निर्णय नई जांच में है और अंतिम समीक्षाओं में कई मामलों में लागू किया गया है। यद्यपि यह निर्णय क्षति मार्जिन के संदर्भ में है, तथापि, इसे कीमत कटौती में भी लागू किया जाना अपेक्षित है।
- xiii. घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि कीमत की आकर्षकता निर्धारित करने के लिए कीमत कटौती पूर्ण रूप से असंगत है। निर्यातक किसी भी तरह घरेलू उद्योग की एनआईपी को नहीं मानेंगे तथा निर्धारित करेंगे कि क्या भारतीय बाजार उनके लिए आकर्षक है।
- xiv. विश्व में प्रत्येक संबद्ध देश से कई देशों को पर्याप्त निर्यात ऐसी कीमतों पर होते हैं कि परिणामी कीमत कटौती सकारात्मक है। संबद्ध देशों में कई महत्वपूर्ण अनुपयुक्त क्षमताएं हैं। इससे स्पष्ट होता है कि क्षति होने की पूरी संभावना है।
- xv. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता यह दर्शाती है कि निर्यातक अपना निर्यात तीसरे देशों की तरफ करेंगे और/अथवा कम कीमतों पर भारतीय बाजार को भारी मात्रा में निर्यात करने के लिए अपने वेशी क्षमताओं का उपयोग करेंगे।
- xvi. विश्व में अन्य देशों को संबद्ध देशों से निर्यात की काफी मात्रा से सकारात्मक पाटन मार्जिन हो रहा है और कीमत में कटौती हो रही है, भारत को तीसरे देशों से ये निर्यात हो रहे हैं जिससे भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता आसन्न है।
- xvii. प्राधिकारी को क्षति होने की जांच करने के लिए निम्नलिखित परीक्षण करने होते हैं, यथा - क्या जांच की अवधि में भारत को निर्यात के संबंध में कीमत कटौती सकारात्मक है, क्या जांच की अवधि के बाद में भारत को निर्यात के संबंध में कीमत कटौती सकारात्मक है, क्या जांच की अवधि में विभिन्न तीसरे देशों को निर्यात के संबंध में कीमत कटौती सकारात्मक है, क्या जांच की अवधि के बाद में विभिन्न तीसरे देशों को निर्यात के संबंध में कीमत कटौती

सकारात्मक है और जांच के अवधि के दौरान तीसरे देशों को निर्यात की मात्रा, जो कम कीमत पर थी, (i) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और (ii) भारत को निर्यात कीमत, सकारात्मक थी तथा क्या भारतीय मांग को देखते हुए निर्यात की यह मात्रा काफी है।

- xviii. निर्यातकों ने एसएसआर प्रश्नावली भाग-II दायर नहीं किया है जिसमें योजना की तारीखों तथा उसमें शामिल क्षमता/उत्पादन मात्रा सहित विस्तारों जैसी सूचना की आवश्यकता है तथा ऐसे परिवर्तन के कारणों, उन बाजारों (देशों), जिनको ऐसी अतिरिक्त क्षमता अथवा उत्पादन दिया जाएगा, साक्ष्यों सहित; पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप विकसित निर्यात बाजारों (भारत के अलावा) की पहचान, उत्पादन क्षमता, उत्पादन, घरेलू बाजार लदान, भारत को निर्यात तथा अन्य बाजारों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संदर्भ में महत्व तथा पाटनरोधी शुल्क की वापसी से प्रत्याशित मालसूची, परिवर्तनों जैसी सूचना की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, घरेलू बाजार में उत्पादन, निर्यातक और अन्य निर्यातक बिक्री, मांग निर्यातक द्वारा निर्यात और तीसरे देशों को अन्य निर्यातक संबंधित सूचना तीन वर्षों के अवधि तथा दो वर्षों के लिए संभावित सूचना मांगी गई थी।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

87. प्राधिकारी ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के 2016 के एससीए 16426 से 16429 में निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, नियमावली के अनुबंध-II (vii) के अनुसार, वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों पर विचार करते हुए, क्षति के जारी रहने की संभावना अथवा होते रहने की संभावना की जांच की। माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में पाया है:

इस प्रकार क्षति के निर्धारण के प्रयोजन से जिन अधिकतर कारकों को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है, उनमें वे हैं – मात्रा में वृद्धि, पाटन में वृद्धि, पाटन मार्जिन में वृद्धि तथा कीमत कटौती सभी सकारात्मक हैं और केवल कीमत दबाव तथा कीमत ह्रास नहीं है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने निर्णय का आधार बनाने के प्रयोजन से उपर्युक्त कारकों पर विश्वास करने के बजाए, कि क्या निर्धारित उपायों के साथ जारी रखे जाने अथवा रहने, असंगत कारक पर विश्वास किया है, यथा क्षति मार्जिन, जिसे कि नियमावली के अनुबंध-II की धारा (vii) के तहत संभावित पहलों पर विचार करते समय ध्यान में न रखे जाने की आवश्यकता थी। नियमावली के अनुबंध-II की धारा (vii) में चार कारकों का प्रावधान है, जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता थी, यथा: (क) पर्याप्त रूप से बड़े हुए आयात की संभावना दर्शाने वाले धारक ने पाटित आयात की वृद्धि की काफी मात्रा; (ख) भारतीय बाजार में अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजारों को बड़े हुए काफी मात्रा में पाटित निर्यातों की संभावना को दर्शाने वाले पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, अथवा एक आसन्न, निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि; (ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर दबाव अथवा काफी ह्रासपूर्ण प्रभाव हो, तथा जिनसे आयात के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना हो; तथा (घ) जिस वस्तु की जांच की जा रही है, उसकी मालसूची।

उपर्युक्त चार कारकों में से निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उप धारा (क) और (ग) के तहत निर्धारित कारकों पर ही विचार किया है। तथापि, उप धारा (ग) का संबंध है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने गलत तथ्य पर विश्वास किया है, यथा – यद्यपि, कीमत कटौती सकारात्मक है, तथापि, उन्होंने उसे नकारात्मक माना है और तदनुसार अपना निष्कर्ष निकाला है।

जहां तक नियमावली के अनुबंध-II की धारा (vii) की उप धारा (ख) और (घ) के तहत निर्धारित कारकों का संबंध है, उत्तरदायी की ओर से इसका विरोध किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उन कारकों पर भी विचार किया है। इस संबंध में, प्रकटन विवरण के अवलोकन से यह बात सामने आती है कि यद्यपि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उपर्युक्त दो कारकों पर विचार किया है, तथापि, यह दर्शाता है कि ऐसा करते समय उसने भारतीय बाजारों को काफी मात्रा में बड़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना दर्शाने वाले निर्यातकों के उत्पादन की क्षमता पर विचार करने के बजाए गलत तथ्यों पर विचार किया है। जैसा कि उप धारा (ख) के तहत उल्लिखित है, उसने घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता पर विचार किया है; और जिन पाटित आयातों से आयात के लिए वृद्धि अथवा भावी मांग पूरी हो सकती थी, उनकी मालसूची के अस्तित्व पर विचार करने के बजाए घरेलू उद्योग की मालसूची पर विचार किया है। अतः स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट प्राधिकारी वास्तविक क्षति के खतरे के निर्धारण के प्रयोजन से नियमावली के अनुबंध-II की धारा (vii) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन उसके तहत निर्धारित तरीके से नहीं कर पाए।

88. माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी पाया है कि:

इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने निष्कर्षों को "क्षति मार्जिन" तथा "कीमत कटौती" और इस तथ्य कि कीमत कटौती नकारात्मक है, के आधार पर अनिवार्य तथ्यों पर अपना निष्कर्ष निकाला है। जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, जहां तक क्षति मार्जिन और कीमत कटौती का संबंध है, प्रकटन विवरण में क्षति की संभावना की जांच के स्तर पर वे संगत कारक नहीं हैं। अतः

निर्दिष्ट प्राधिकारी शुल्क रद्द करने के मामले में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के प्रश्न पर विचार करते समय "क्षति मार्जिन" तथा "कीमत कटौती" जैसे कारकों पर विश्वास करने में न्यायपूर्ण नहीं थे।

89. उपर्युक्त के मद्देनजर नियमावली के अनुबंध-II की धारा (vii) के तहत संभावित पहलुओं पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार किया है:

**क्या भारत ने पाटित आयातों की काफी वृद्धि दर पर्याप्त रूप से बड़े हुए आयात की संभावना दर्शा रहा है।**

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, क्षति की अवधि के आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान आयात में समग्र वृद्धि हुई है। तथापि, तीन प्रमुख उत्पादक संबद्ध देशों (चीन, संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ) में से दो देश अर्थात् चीन और यूरोपीय संघ जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयात में घटती हुई प्रवृत्ति दर्शा रहे हैं। यहां तक की समग्र आधार पर भी (सभी संबद्ध देशों को एक साथ लेकर) जांच की अवधि के बाद वार्षिक आधार पर आयात में वृद्धि केवल तीन प्रतिशत है। यदि और वस्तुनिष्ठ संभावित विश्लेषण किया जाए तो वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए आयात आंकड़े भी प्राधिकारी द्वारा डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त किए गए थे। चीन, केन्या और यूक्रेन से आयात में जांच की अवधि के बाद दो वर्षों के दौरान निरंतर कमी दर्ज हुई है। जांच की अवधि के बाद की अवधि में यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका से आयात पहले 2015-16 में कम हुए और फिर 2016-17 में बढ़ गए। अतः भारत ने पाटित आयातों में काफी वृद्धि की आवश्यकता वास्तव में पूरी नहीं की गई।

**क्या निर्यातक की क्षमता में आसन्न, पर्याप्त वृद्धि अथवा पर्याप्त स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य वृद्धि है**

91. भारतीय बाजार को निपटान योग्य मात्रा भेजने की संभावना का पता लगाने के लिए मौजूदा अधिशेष क्षमताओं और क्षमता अभिवृद्धि का मूल्यांकन करना वास्तविक क्षति का खतरा सुनिश्चित करने के मानदंड के लिए अपेक्षित है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देशों के उत्पादकों के सामने काफी अधिशेष क्षमताओं की समस्या पहले से ही आ रही है। घरेलू उद्योग ने आईएचएस केमिकल जर्नल की प्रतियां प्रस्तुत की हैं जिनमें संबद्ध देशों में सोडा ऐश मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी गई है, यथा मौजूदा क्षमता, मौजूदा उत्पादन, उपयोग में न लाई गई क्षमता तथा क्षमता विस्तार आदि। निम्नलिखित तालिका यह दर्शाती है कि भारतीय मांग की लगभग 3 मिलियन मी. टन के विरुद्ध संबद्ध देशों में उपयोग में न लाई गई क्षमता लगभग 9.26 मिलियन मी. टन क्षमता विस्तार (पहले से ही तथा आने वाली के आधार पर) 4.55 मिलियन मी. टन तक है। ये आंकड़े इस तथ्य पर आधारित हैं कि सभी सोडा ऐश विनिर्माता कंपनियों को 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर प्रचालन करना होता है जोकि वास्तव में एक वास्तविकता की स्थिति नहीं हो सकती। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क भी दिया है कि सोडा ऐश संयंत्रों का इष्टतम क्षमता उपयोग लगभग केवल 80 प्रतिशत है। संभावना विश्लेषण निर्धारित करने के लिए नियम स्पष्टतः निर्धारित करते हैं कि विश्लेषण सख्त तथ्यों के आधार पर होना चाहिए और अटकलों और सुदूर संभावनाओं के आधार पर ही नहीं। इसके अतिरिक्त अधिकतम क्षमता वृद्धि (40 लाख टन) अर्थात् लगभग 88 प्रतिशत क्षमता वृद्धि चीन द्वारा ली जाती है जिसकी इस उत्पाद के लिए बहुत ही कम निर्यातानुमुखता (8 प्रतिशत) है। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातकों की क्षमता में आसन्न अथवा पर्याप्त वृद्धि के कारण क्षति का खतरा होना नहीं दिखाई देता।

विवरण	यूओएम	संबद्ध देश					
		चीन	संयुक्त राज्य अमेरिका	यूरोपीय संघ	पाकिस्तान	ईरान	कुल
मौजूदा क्षमता*	मी. टन	319,61,000	125,48,000	91,22,750	4,90,000	7,25,000	548,46,750
मौजूदा उत्पादन*	मी. टन	252,76,000	116,57,000	76,49,750	4,01,250	5,93,750	455,77,750
उपयोग न की गई क्षमता	मी. टन	66,85,000	8,91,000	14,73,000	88,750	1,31,250	92,69,000
क्षमता विस्तार**	मी. टन	40,00,000			2,50,000	3,00,000	45,50,000
कुल निर्यात	मी. टन	19,42,574	65,63,293	16,49,095			101,54,962
निर्यात अभिमुखीकरण	मी. टन	8%	56%	22%			22%
भारत का निर्यात***	मी. टन	1,29,466	87,833	67,823			2,85,122

भारत को एफओबी निर्यात कीमत***	यूएसडी/मी. टन	211.92	171.22	231.60			
तीसरे देशों को निर्यात - मात्रा							
कुल***	मी. टन	18,13,108	64,75,460	15,81,272			98,69,840
भारत से कम कीमत पर***	मी. टन	1,23,173	6,04,303	15,03,361			22,30,837
भारत से अधिक कीमत पर***	मी. टन	16,89,934	58,71,157	77,911			76,39,003
तीसरे देशों को निर्यात - कीमत							
कुल***	यूएसडी/मी. टन	217.51	198.39	194.31			
भारत से कम कीमत पर***	यूएसडी/मी. टन	210.51	152.05	187.77			
भारत से अधिक कीमत पर***	यूएसडी/मी. टन	218.02	203.16	320.50			

स्रोत:

\* आईएचएस केमिकल सप्लायमेंट सितंबर, 2015

\*\* आईएचएस केमिकल ग्लोबल

\*\*\* वर्ल्ड ट्रेड एटलस

## 92 क्या आयात उन कीमतों पर पहुँच रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर ह्रासमान/न्यूनीकरण प्रभाव पड़ रहा है।

आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह नोट किया जाता है कि बिक्री कीमत वर्ष दर वर्ष निरंतर बढ़ी है तथा तदनुसार, कीमत न्यूनीकरण स्पष्ट रूप से नहीं है। जहां तक पाटित आयात के कारण कीमत न्यूनीकरण प्रभाव का संबंध है, कोई स्पष्ट प्रवृत्ति भी नहीं है। यद्यपि, 2012-13 में बिक्री कीमत में वृद्धि आयात के पहुँच मूल्य में वृद्धि के अनुपात में नहीं रही है, तथापि, उसने बाद के वर्ष में उच्चतर तुलनात्मक वृद्धि दर्ज की है।

## 93. मालसूची का स्तर

संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास उपलब्ध मालसूची का स्तर पर्याप्त सहयोग के अभाव में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। तदनुसार, क्षति के खतरे/क्षति की संभावना सुनिश्चित करने के लिए इस मानदंड की प्राधिकारी जांच नहीं कर पाए।

## 94. निर्यात अभिमुखीकरण

सभी संबद्ध देशों की निर्यातोन्मुखता समग्र रूप से 22 प्रतिशत है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए निर्यातोन्मुखता 56 प्रतिशत तक है, यह चीन के मामले में 8 प्रतिशत है।

### भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयात का पहुँच मूल्य समग्र रूप से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, इस प्रकार यह जांच की अवधि में तथा जांच की अवधि के बाद में सकारात्मक कीमत कटौती दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूटीए (वर्ल्ड ट्रेड एटलस) के आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि कई अन्य देशों को संबद्ध देशों से निर्यात उन देशों से भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पाई गई है। इन निर्यातों की मात्रा 2.23 मिलियन मी. टन है जो भारत में मौजूदा मांग का 72.42 प्रतिशत है। तथापि, निष्कर्ष स्वरूप पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने पर ऐसे कम कीमत वाले निर्यातों की मात्रा भारत में आएगी जो काफी दूर तक जाएगी। यदि कम मात्रा वाली निर्यात लेनदेन तुलनात्मक रूप से अधिक कीमत पर भारत में किए जाते हैं तो इस विश्लेषण से भ्रामक परिणाम आ सकते हैं। फिर कीमत उत्पाद के ग्रेड से भी संबंधित है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क

वापस लिए जाने के कारण कुछ क्षेत्रों द्वारा निर्यात कीमत में वृद्धि की संभावना पर बाजार बदलना इतना आसान नहीं है। अतः इस मानदंड के संबंध में यह विश्लेषण अटकलों तथा वस्तुपरकता से परिपूर्ण है।

#### घ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ:

96. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात निवेदन प्राप्त हो गए हैं। इनमें उठाए गए अधिकतर मुद्दे वही हैं जो जांच के दौरान पहले उठाए गए हैं और साथ ही जिनका उचित रूप से निदान भी कर लिया गया है। अतिरिक्त निवेदनों का विश्लेषण किया गया है जोकि निम्नानुसार है :-

#### आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध :

97. आवेदक, अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

- i. गुजरात उच्च न्यायालय ने कुछ सीमित बिन्दुओं पर मामले को वापस भेज दिया है। इस विलंबित चरण किन्हीं नए तथ्यों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 में किसी नई सूचना अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार गुजरात उच्च न्यायालय के प्रेक्षणों के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई है।
- ii. 24.4.2017 को हुई मौखिक सुनवाई को कारगर इसलिए नहीं का जा सकता क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे संबद्ध आंकड़े/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचाराधीन मूल तथ्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वास किया था। विश्व व्यापार एटलस/आईएचएस आंकड़े प्रदान नहीं किए हैं, उस पर विश्वास किया गया है। आंकड़े प्रदान नहीं करना प्राकृतिक न्याय के विधि और सिद्धांत की मूल आवश्यकताओं के विपरीत है।
- iii. रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेज घरेलू उद्योग की नई क्षमताओं के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रेक्षण का समर्थन नहीं करते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी को क्षमता संवर्धन से संबंधित दस्तावेज प्रदान करने चाहिए थे जबकि क्षमता संवर्धन से संबंधित सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी के ध्यान में लाई गई थी।
- iv. यदि आंकड़े प्रथम प्रकटन से पहले उपलब्ध थे तो प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों को पहले से ही सूचित करना चाहिए था। लेकिन यदि उन्हें बाद में प्रस्तुत किया गया है तो इसे नई सूचना माना जाता है, इसलिए इसे वर्तमान विवरण में शामिल नहीं किया जा सकता है।
- v. जैसा कि घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है, पाटित आयातों से उसको कोई क्षति नहीं हुई है।
- vi. संभावना के लिए कम कीमत पर बिक्री होना एक निर्णायक कारक नहीं हो सकता है, लेकिन अभी भी यह क्षति पर निर्णय लेने के लिए एक अनिवार्य संघटक है और इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- vii. प्राधिकारी पहले के प्रकटन की टिप्पणियों में अपने विगत मंतव्य से पीछे हट गए हैं। उत्पादकों के मात्र निर्यातोन्मुख होने से यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि घरेलू बाजार में पाटित आयात होंगे। यह अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है।
- viii. प्राधिकारी ने निर्यातकों पर गलत रूप से यह दायित्व अंतरित कर दिया है कि उत्पादन क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है बजाए यह कहने के कि आवेदकों को यह सिद्ध करना चाहिए कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है।
- ix. प्राधिकारी अपने विगत प्रकटन विवरण से विचलित हुए हैं जिसमें उन्होंने यह कहा था कि आयातों का पहुंच मूल्य भारतीय बाजार में क्षतिरहित कीमत से अधिक था। तथापि, उन्होंने बिना कोई औचित्य बताए अपने इस मंतव्य में परिवर्तन कर दिया है और यह कहा है कि संबद्ध देशों से समग्र पहुंच मूल्य घरेलू बिक्री कीमत से कम है।
- x. चीन और संयुक्त राज्य अमरीका अधिकतर अपने निर्यात भारतीय निर्यात कीमतों से अधिक कीमतों पर कर रहे हैं। इस प्रकार, संबद्ध देशों में उत्पादकों के लिए यह बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है।
- xi. संबद्ध देशों से तीसरे देशों को कीमतें कुल मिलाकर समान स्तर पर हैं।
- xii. जिन देशों पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है, उनके साथ संबद्ध देशों का विश्लेषण करना विधिसंगत नहीं है। केवल संबद्ध देशों के लिए ही कारणात्मक संबंध का विश्लेषण किया जाना चाहिए। संयुक्त विश्लेषण विपरीत परिणाम दर्शाते हैं।
- xiii. प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लागू होने वाले सभी देशों से संयुक्त आयातों पर विश्वास करने के बजाए संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में गिरावट को नोट करने में विफल रहे हैं।
- xiv. प्राधिकारी ने विगत जांच के अपने मंतव्य में परिवर्तन कर लिया है जिसमें घरेलू उद्योग का दर्जा आयातक/निर्यातक के बीच संबंध होने के आधार पर नहीं दिया गया था। यहां आवेदक आयातक है, इसलिए उसे घरेलू उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए।

- xv. सूचना की परिशुद्धता के संबंध में, घरेलू उत्पादकों द्वारा सही सूचना प्रस्तुत करने को इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता कि बाद में सत्यापन किया गया है।
- xvi. हितबद्ध पक्षकारों को सही सूचना प्रदान की जानी चाहिए। विगत मामले में निर्यातक के उत्तर को लिपिकीय त्रुटियों, अनुचित पते आदि के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान मामले में भिन्न दृष्टिकोण क्यों अपनाया जा रहा है।
- xvii. माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जिन आंकड़ों पर विश्वास किया गया है कि ये पुराने हैं और जांच पश्चात अवधि से संबंधित हैं, जोकि पूर्व दो वर्ष के हैं।
- xviii. आईएचएस आंकड़ों के अनुपात हाल ही की अवधि में संयुक्त राज्य अमरीका, चीन और यूक्रेन से आयातों में काफी गिरावट आई है। विभिन्न संबद्ध देशों में प्रयोज्य क्षमता की कमी से स्पष्ट पता चलता है कि इन देशों से आयातों के बढ़ने की कोई संभावना नहीं है।
- xix. वास्तव में आईएचएस के अनुसार, स्थानीय मांग में चीन और यूरोपीय यूनियन (जोकि सोडा ऐश के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं) में स्थानीय उत्पादन का प्रमुख अनुपात बनता है, इसलिए बड़े हुए आयातों की कोई संभावना नहीं है।
- xx. प्रकटन विवरण में प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, क्षमता उपयोग से पता चलता है कि संबद्ध देशों में क्षमता उपयोग लगभग 80-85 प्रतिशत है। तथापि, हालांकि संबद्ध देशों में अप्रयुक्त क्षमताएं विद्यमान हैं, फिर भी इन्हें "स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य क्षमताओं" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
- xxi. आएचएस स्रोत से प्राप्त ऐतिहासिक आंकड़ों से यह स्पष्ट पता चलता है कि सोडा ऐश के संयंत्र 80-85 प्रतिशत की क्षमताओं के अनुकूलतम स्तर पर प्रचालित होते हैं।
- xxii. संबद्ध देशों में क्षमता उपयोग पहले से ही अनुकूलतम अथवा लगभग अनुकूलतम स्तर अर्थात् एचआईएस के अनुसार लगभग 80-85 प्रतिशत पर है।
- xxiii. यहां तक कि घरेलू उद्योग भी (जिसने यह स्वीकार किया है कि उसे क्षति नहीं हुई है) जांच अवधि और जांच पश्चात अवधि में लगभग 83-84 प्रतिशत का क्षमता उपयोग कर रहा है।
- xxiv. आ एच एस के अनुसार संबद्ध देशों के साथ-साथ अन्य निर्यात गंतव्य देशों (भारत से भिन्न) में विचाराधीन उत्पाद के लिए पर्याप्त मांग है, जिनमें इनके बाजार बड़े हुए निर्यातों को सुगमता से खपा सकते हैं।
- xxv. विशेषकर दो सबसे बड़े उत्पादक देशों अर्थात् चीन और यूरोपीय यूनियन में स्थानीय मांग पहले से ही कुल उत्पादन का प्रमुख अनुपात है (जोकि दोनों देशों में 90 प्रतिशत से ऊपर है) और आगामी 2-3 वर्षों में भी इसी प्रवृत्ति के निरंतर बने रहने की प्रत्याशा है।
- xxvi. वर्ष 1990 से 2015 तक क्षमता में ऐतिहासिक विस्तार की जांच करने पर यह देखा गया है कि क्षमताओं में वृद्धि की औसत दर 3.43 प्रतिशत प्रति वर्ष रही है। प्रकटन विवरण में अभिज्ञात किया गया क्षमता विस्तार (4.5 मिलियन मीट्रिक टन) के आगामी 3-4 वर्षों में खुलने की प्रत्याशा है जोकि 2-3 प्रतिशत की औसत संवृद्धि दर होगी। यह मांग और क्षमता में ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के समनुरूप है।
- xxvii. भारतीय कीमतों के तृतीयक देश की कीमतों से अधिक होने से यह स्पष्ट पता चलता है कि पाटन होने की कोई संभावना नहीं है।
- xxviii. हालांकि भारत की कीमतों से कम कीमतों पर देशों को निर्यात हुए हैं, इन निर्यातों की कीमत अमरीकी डॉलर 210.51 है जोकि भारतीय कीमत से मात्र 1.41 अम.डॉ./मी.ट. ही कम है। इन दोनों कीमतों के बीच अंतर 1 प्रतिशत से भी कम है।
- xxix. ऐसी कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है कि चीन के निर्यातक विक्रियों के अपने माध्यम में परिवर्तन करेंगे और अपनी सभी मात्राओं को भारत में कीमत में मात्र 0.5 प्रतिशत वृद्धि के लिए अपवर्तित कर देंगे।
- xxx. आईएचएस ग्लोबल सोडा ऐश सप्लीमेंट (फरवरी, 2017 संस्करण) के अनुसार भारतीय बाजार में इस समय केवल 2 प्रतिशत चीन के निर्यात हैं।
- xxxi. हालांकि इन निर्यातों में गिरावट आ रही है, जोकि वर्ष 2016 में सभी स्रोतों से चीन के निर्यातों में 17 प्रतिशत गिरावट दर्शाते हैं। इसका प्रमुख कारण यह तथ्य है कि चीन में घरेलू मांग इस समय घरेलू उत्पादन के 90 प्रतिशत से अधिक हैं और यही परिदृश्य आगामी 2-3 वर्ष में भी बने रहने की संभावना है। इसलिए चीन से भारत को आयातों की कोई संभावना नहीं है।

वस्तुतः चीन को अपनी बढ़ती हुई घरेलू मांग को पूरा करने के लिए हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका से कुछ सोडा ऐश का आयात करना पड़ा था।

- xxxii. इन्हीं आंकड़ों (आई एच एस अनुपूरक रिपोर्ट) के हाल ही के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय भारत संयुक्त राज्य अमरीका के निर्यातों का लगभग 1 प्रतिशत भाग ही बनता है।
- xxxiii. भारत में बिक्रियों और भारत से अधिक कीमतों पर देशों को निर्यात के बीच तुलना करने से मात्रा के रूप में लगभग 98:2 का अनुपात बनता है।
- xxxiv. यदि भारत से कम कीमतों वाले देशों में बिक्रियों को अधिक कीमत आकर्षित करने वाले बाजारों की ओर निर्देशित कर दिया जाता है तो वे उसी अनुपात में विभाजित होंगी जिसे यह पता चलेगा कि केवल लगभग 12,000 मी.ट. ही भारत को भेजे जाने की संभावना है जिससे यह स्पष्ट पता होता है कि इससे कोई खतरा होने की संभावना नहीं है।
- xxxv. आईएचएस के अनुसार, हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका आधारित उत्पादकों का प्रमुख संकेन्द्रण उनका अपना घरेलू बाजार और कुछ चुनिंदा निर्यात बाजार हैं जैसे कि मैक्सिको, चीन, थाइलैंड और वियतनाम।
- xxxvi. संयुक्त राज्य अमरीका में प्रत्याशित क्षमता विस्तार लगभग 90,000 मी.ट. है जोकि भारतीय मांग के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमरीका की समग्र क्षमता, दोनों की तुलना में बहुत मामूली है।
- xxxvii. इसमें संयुक्त राज्य अमरीका की क्षमता लगभग 13000000 मी.ट. है जिसे आई एच एस के अनुसार घरेलू मांग ने पहले से ही पीछे छोड़ दिया है। इससे पता चलता है कि 90,000 मी.ट. क्षमता का विस्तार 1 प्रतिशत वृद्धि से भी कम होगी।
- xxxviii. यूरोपीय यूनियन से भारत को कीमतें (प्रकटन विवरण के अनुसार) अमरीकी डॉलर 231.60/मी.ट. है जबकि भारत से कम कीमतों वाले देशों को यह कीमत अमरीकी डॉलर 187.77/मी.ट. है। 187.77 की कीमत में 9.17 अम.डॉ./मी.ट. की पाटनरोधी शुल्क की दर को जोड़ने से परिणामी आंकड़ा 196.84 अम.डॉ./मी.ट. निकलेगा। अन्य शब्दों में यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क लागू रहता है तो यूरोपीय यूनियन आधारित उत्पादकों के लिए भारत बहुत अधिक कीमत आकर्षक बाजार बना रहेगा क्योंकि वे अपनी कीमतों में पाटनरोधी शुल्क को आसानी से खपा सकते हैं और फिर भी अमरीकी डॉलर 187.77/मी.ट. से अधिक कीमत पर बेच सकते हैं। तथापि, इतना अधिक कीमत आकर्षक बाजार (वर्तमान पाटनरोधी शुल्क सहित) होने के बावजूद भारत यूरोपीय यूनियन के लिए निर्यात बाजारों का मात्र 4 प्रतिशत भाग बनता है। आईएचएस ग्लोबल सोडा ऐश सप्लीमेंट से यह पता चलता है कि यूरोपीय यूनियन में स्थानीय मांग पहले से ही स्थानीय उत्पादन का 90 प्रतिशत से अधिक भाग बनती है और इस पद्धति के आगामी 2-3 वर्षों में भी अपरिवर्तित रहने की संभावना है। इसलिए यूरोपीय यूनियन से भारत को आयात होने की कोई संभावना नहीं है।
- xxxix. ऐसा प्रतीत होता है कि केन्या, यूक्रेन, ईरान और पाकिस्तान से निर्यातों के लिए प्रकटन विवरण में कोई आंकड़ा अथवा विश्लेषण नहीं है।
- xl. तथापि, अन्य देशों (जिनकी ऊपर जांच की गई है) के लिए संभावना की कमी को देखते हुए यह सुस्थिर रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि इन देशों से भी क्षति होने की संभावना नगण्य होगी।
- xli. वास्तव में केन्या के लिए यह सुस्थापित तथ्य है कि देश में इस समय केवल एक ही सक्रिय संयंत्र है जिससे उनके निर्यातों के अत्यधिक नियंत्रित होने की संभावना है।
- xlii. याचिकादाता ने क्षतिरहित कीमत के संबंध में अपने आंकड़ों में संशोधन किया है, इसलिए प्राधिकारी उत्पादन की लागत का परिकलन करने के लिए लागत लेखाकरण रिकॉर्ड पर विचार कर सकते हैं, चूंकि विचाराधीन उत्पाद लागत लेखाकरण रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है।
- xliii. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत से न्यायोचित संबंधी गंभीर प्रश्न उठते हैं जिनमें प्राधिकारी द्वारा इस समय मध्यावधि समीक्षा की जा रही है।
- xliv. उक्त जांच की शुरुआत यथार्थ रूप से इस मध्यावधि समीक्षा के निष्कर्ष के अध्यधीन है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने अपने इस आशय के पहले निष्कर्ष को पलटने का विचार बना लिया है कि क्षति की कोई संभावना नहीं है जबकि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई निर्णायक समीक्षा जांच संबंधी आवेदन पत्र पर वह प्रथमदृष्टया अपने ऐसे विचार नहीं बना पाते।

- xlv. प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार 60 दिनों के भीतर जांच को पूरा करना आवश्यक नहीं समझा है और अब वे कुछ तकनीकी मुद्दों का हवाला देकर निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने की कार्यवाही कर रहे हैं, जिससे घरेलू उद्योग का अत्यधिक हित होगा और उनका ऐसा करने का कोई न्यायोचित तर्क नहीं है।
- xlvi. ओलंपिया द्वारा न तो जांच अवधि में और न ही जांच पश्चात अवधि में निर्यात किए जाने के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, कीमत संबंधी क्षति होने की भी कोई संभावना नहीं है जिस पर निर्यात किए जाते हैं क्योंकि यह पाकिस्तान में संबद्ध वस्तुओं के लिए बहुत समान कीमतें प्राप्त कर रहा है और पाकिस्तान में संबद्ध वस्तुओं के लिए सुदृढ़ मांग की स्थिति है। उच्च घरेलू वसूलियों से ओलंपिया के मामले में सकारात्मक पाटन मार्जिन का पता लग सकता है लेकिन ऐसे पाटन मार्जिन ने घरेलू उद्योग पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाला है।
- xlvi. समग्र क्षति अवधि और जांच अवधि तथा साथ ही जांच पश्चात अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ और समग्र कार्य निष्पादन में वृद्धि के स्तर से यह स्पष्ट पता चलता है कि ऐसा किंचित मात्र भी संकेत नहीं मिलता है कि यदि वर्तमान शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है तो क्षति के निरंतर जारी होने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- xlviii. भारत में सोडा ऐश के उत्पादकों द्वारा अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से सोडा ऐश पर लागू पाटनरोधी शुल्कों का दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि वे अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकें।
- xlix. पाया गया सकारात्मक पाटन मार्जिन का घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और ऐसा सकारात्मक पाटन मार्जिन क्षति की संभावना नहीं होने से स्थिति को बिक्रीत नहीं करता है।
- I. वर्तमान मध्यावधि समीक्षा की जांच अवधि और समग्र क्षति अवधि में सभी क्षति प्राचलों पर घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन सुदृढ़ प्रतीत हुआ है और साथ ही जांच प्रसार अवधि में भी यही प्रवृत्ति बनी हुई है। यहां तक कि मूल मामले में भी घरेलू उद्योग क्षति रहित कीमतों से अधिक कीमतों पर बिक्री करने में सक्षम था।
- li. वापसी का अधिदेश आंकड़ों के नए सैट का अनुशीलन करने की अनुमति नहीं देता है और इस आशय का निर्णय लिया जाना है कि प्राधिकारी की फाइल में पहले से क्या विद्यमान है, विशेषकर जबकि ऐसे आंकड़ों पर ऐसी रिपोर्टों का समग्र रूप से प्रकटन किए बिना ऐसे आंकड़ों पर विश्वास किया गया है।
- lii. “संभावना” जैसे जटिल प्राचल पर निर्णय लेने के लिए आईएचएस कैमिकल-ग्लोबल सोडा ऐश के कुछ चुनिंदा और छुटपुट पृष्ठों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकार तब तक अपना खंडन नहीं कर सकते हैं जबकि कि उन्हें संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है।
- liii. वास्तव में घरेलू उद्योग ने अपने लिखित निवेदनों में ऐसी रिपोर्ट के कुछ पृष्ठों पर विश्वास किया था और उन्होंने अपने प्रत्युत्तर के निवेदन में यह मुद्दा उठाया था कि यह रिपोर्ट कुछ अन्य पृष्ठों पर घरेलू उद्योग के दावों का खंडन करती है।
- liv. सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया गया 9 पृष्ठों का दस्तावेज रिपोर्ट का स्रोत है जिसके दस्तावेज के शीर्ष में तथा पृष्ठ सं. 7 और 8 को छोड़कर फुटर में प्रकाशन का महीना दिया गया है (यह सूचना तुर्की आदि के बारे में है)। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पृष्ठ को विनिर्मित किया गया है। रिपोर्ट जांच पूरी होने के बाद की अवधि से संबंधित लगती है।
- lv. प्राधिकारी द्वारा जिन डब्ल्यूटीओ आंकड़ों पर विश्वास किया गया है, वे भी हमें प्रदान नहीं किए गए हैं।
- lvi. पाकिस्तान के मामले में संभावना की जांच सहयोगी उत्पादकों के आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए और न कि कुछ निराधार रिपोर्टों के आधार पर।
- lvii. ऐसी कोई अतिरिक्त मात्रा अथवा वेशी क्षमता नहीं है जोकि शुल्क को रद्द किए जाने की स्थिति में भारत को अपवर्तित कर दी जाएगी। पाकिस्तान और साथ ही विश्व में उत्पाद की मांग और पूर्ति की स्थिति बहुत संतुलित है तथा कोई भी देश ऐसे किसी भी दबाव पर नहीं है कि वह सोडा ऐश को इस समय प्राप्त होने वाली कम कीमत पर बेचेगा।
- lviii. जबकि नियमावली में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है कि संभावना की जांच अनुबंध-11 के पैरा (7) के सिद्धांतों के अनुसार जांच की जानी चाहिए फिर भी यह समझ में नहीं आता कि प्राधिकारी ऐसे सिद्धांतों को सीधे क्यों अपना रहे हैं।
- lix. मामूली रूप से सकारात्मक कीमत कटौती से क्षति की स्थिति की संभावना का पता नहीं चलता जबकि इस समय लाभ के अत्यधिक उच्च स्तर बने हुए हैं। घरेलू उद्योग सोडा ऐश के पाटनरोधी शुल्कों का दुरुपयोग करके अत्यधिक बढ़ी हुई कीमतें प्राप्त करने के परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हो रही है।
- lx. कुछ निर्यातकों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है और जहां कहीं भी उन्होंने भाग लिया है वहां संभावना की जांच ऐसे सहयोगी निर्यातकों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर की जानी चाहिए और प्राधिकारी को मात्र उपलब्ध तथ्यों को नहीं अपनाना चाहिए।



- lxi. गुजरात उच्च न्यायालय के अधिनिर्णय में निर्णय का कार्यक्षेत्र निर्णय तक ही सीमित किया गया है। मामले को जांच पूरी करने के लिए वापस भेज दिया गया है और मुद्दे पर अंतिम जांच परिणाम 60 दिनों के भीतर दिए जाने का निर्देश है। उच्च न्यायालय से आदेश की प्राप्ति के लिए 7 दिन लगते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए भी निर्धारित समय समाप्त हो गया है।
- lxii. अधिकतर प्रेक्षण प्रक्रियात्मक संबंधी है। यदि आर्थिक क्षति के खतरे के 4 कारकों को ध्यान में रखा जाता है तब भी उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है।
- lxiii. कीमत में कटौती होने का विश्लेषण ऐसे मामलों में असंगत है जिनमें घरेलू उद्योग को कोई कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण नहीं हुआ है। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के कारण कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और ये घरेलू उद्योग की कीमत पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रहे हैं।
- lxiv. यूरोपीय यूनियन, ईरान और संयुक्त राज्य अमरीका के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण आईएचएस कैमिकल में यथाप्रकाशित जांच अवधि के दौरान प्रचलित औसत कीमतों के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी आई एच एस कैमिकल की उन कीमतों के आंकड़े प्रदान करने में विफल रहे हैं जिनका उन्होंने उपयोग किया है।
- lxv. हालांकि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है, उसका मुख्य कारण यह है कि घरेलू उद्योग बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में अक्षम हैं।
- lxvi. संयुक्त राज्य अमरीका का भविष्य में क्षमता विस्तार करने की कोई योजना नहीं है और इसके अतिरिक्त उसके सभी निर्यात भारतीय कीमतों से अधिक कीमतों पर हुए हैं। इसलिए आंकड़ों से यह पता चलता है कि ऐसा विचार करने का कोई कारण नहीं है कि संयुक्त राज्य अमरीका से आयातों में वृद्धि होने की संभावना है।
- lxvii. यूरोपीय यूनियन से निर्यातकों की क्षमता विस्तार करने की कोई योजना नहीं है। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय यूनियन से निर्यात अमरीकी डॉलर 320.50 प्रति मी.ट. की उच्च कीमत पर हुए हैं और इसके अतिरिक्त जांच पश्चात अवधि में यूरोपीय यूनियन से कीमतों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में कोई कटौती नहीं की है।
- lxviii. चीन का निर्यातोन्मुखीकरण मात्र 8 प्रतिशत है और इसके अतिरिक्त उसके सभी निर्यात तृतीय देशों को हुए हैं जिनकी कीमतें भारत को निर्यातित कीमतों से अधिक हैं।
- lxix. निर्यातोन्मुखीकरण मात्र ही आयातों के तथ्य का ऐसा कोई संकेत नहीं है कि जिससे भारत में आयात में वृद्धि होगी, यदि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है।
- lxx. यदि संबद्ध देशों के आयातों पर लगाए गए शुल्क को हटा लिया जाता है तो निर्यातक केवल अपनी कीमतों में और वृद्धि करेंगे। चूंकि भारतीय बाजार में मांग और पूर्ति के बीच अंतर व्याप्त है, इसलिए निर्यातकों के लिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे बढ़ती मांग का लाभ नहीं उठाएंगे क्योंकि उनका उपभोक्ता आधार पहले से ही इन अधिक कीमतों का भुगतान करने के लिए तैयार है।

### घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

98. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

- i. निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे पहले उठाए गए प्रारंभिक आपत्ति पर निर्णय लें कि क्षति की संभावना के साक्ष्य के बिना मध्यावधि समीक्षा करने का क्या न्यायोचित आधार है।
- ii. निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति नहीं होने तथा क्षति की पुनरावृत्ति न होने की संभावनाप को सिद्ध करने का दायित्व आवेदक पर है। यह दायित्व घरेलू उद्योग का नहीं है।
- iii. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना आयातों की पहुंच कीमत के साथ परिवहन लागत को जोड़ने के बाद ही की जानी चाहिए क्योंकि परिवहन लागत उत्पादन की लागत का बहुत पर्याप्त भाग बनती है।
- iv. उचित तुलना के सिद्धांत यह मांग करते हैं कि घरेलू कीमत की तुलना व्यापार के उचित स्तर पर आयात कीमत के साथ की जाए। जबकि व्यापार का ऐसा स्तर सामान्यतः एक्स-पोर्ट की तुलना में कारखानागत स्तर पर हो सकता है, जहां तक घरेलू उद्योग का संबंध है, इसलिए यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि व्यापार के स्तर को निरपवाद रूप से कारखानागत स्तर पर ही होने की आवश्यकता है।
- v. विश्व व्यापार संगठन के समक्ष भारत की स्थिति घरेलू उद्योग के इन तर्कों का स्पष्ट समर्थन करती है कि आयातित उत्पाद की कीमत की तुलना यथा संभव खपत के बिन्दु पर घरेलू उद्योग की कीमत के साथ की जाए।

- vi. जांच अवधि और जांच पश्चात अवधि के दौरान पाटित आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- vii. यदि पाटनरोधी शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक ह्रास अथवा न्यूनीकरण होने का प्रभाव पड़ेगा।
- viii. विश्व भर में अनेक देशों को संबद्ध देशों से अत्यधिक निर्यात किए जा रहे हैं। जहां कीमतों भारतीय कीमत से वास्तविक रूप से कम है। इसके अतिरिक्त इन निर्यातों की संयुक्त मात्रा विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय मांग से बहुत अधिक है। निर्यातकों के पास अत्यधिक बेशी और अनप्रयुक्त क्षमताएं विद्यमान हैं और इसलिए यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में वे संभवतः अपने निर्यातों को बढ़ा देंगे।
- ix. ऐसी स्थिति में जिसमें शुल्कों का वांछित प्रभाव पड़ा है, क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के पर्याप्त साक्ष्य हैं जो इस प्रकार प्राधिकारी को लगाए गए शुल्कों को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। निदेशालय की यह सुस्थापित स्थिति है कि लगाए गए शुल्कों पर भी कोई क्षति नहीं होती है तो भी शुल्को को बढ़ाया जाता है। इस संबंध में कोरिया से पोलीप्रोपीलीन, जिंग ऑक्साइड, पोटोशियम कार्बोनेट, ताइवान से कॉस्टिक सोडा तथा चीन से डक्टाइल आयरन पाइप्स आदि जैसी जांच का उल्लेख किया जा सकता है।
- x. प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की है जिससे पता चलता है कि प्राधिकारी को वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच में विचारित जांच अवधि के बाद की अवधि के लिए आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति होने की संभावना के प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिस पर विचार करने पर वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की गई है। यह तथ्य स्वतः दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क के समय पूर्व समाप्त करने की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

99. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है:

- i. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है, डब्ल्यूटीए और आईएचएस आंकड़े नहीं दिए गए हैं तथा कोई नए तथ्य नहीं लाए जा सकते, यह नोट किया जाता है कि इस स्तर पर प्राधिकारी द्वारा किसी नए तथ्य पर विचार नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग ने अपने वर्तमान सुनवाई के बाद लिखित अनुरोधों में केवल अपने पूर्व के अनुरोधों/सूचना की पुनरावृत्ति की है। निर्यातक देशों के सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न देशों को निर्यातक देशों से निर्यात संबंधी सूचना मूल समीक्षा जांचों के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा दी गई थी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों की शुद्धता का सत्यापन करने के लिए केवल विश्व व्यापार एटलस के आंकड़ों का प्रयोग किया था। जहां तक इन डब्ल्यूटीए आंकड़ों को हितबद्ध पक्षकारों को बताए जाने का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि डब्ल्यूटीए आंकड़े सार्वजनिक पटल की सूचना नहीं हैं और अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा संकलनकर्ता एजेंसी के साथ हस्ताक्षरित करार के तहत भारत सरकार को स्वीकार्य है। एजेंसी के साथ इस करार से भारत सरकार किसी हितबद्ध पक्षकार और जनता को यह सूचना परिचालित नहीं कर सकती। प्राधिकारी ने अपने निजी स्रोतों से घरेलू उद्योग के दावों के सत्यापन के लिए ही इस सूचना का प्रयोग किया है। घरेलू उद्योग ने उनके संभावित दावे को पुष्ट करने के लिए निर्यातक देशों के सीमा शुल्क आंकड़ों को अपनाया है। प्राधिकारी ने विश्व व्यापार एटलस के साथ घरेलू उद्योग द्वारा अपनाए गए इन सीमा शुल्क आंकड़ों का सह संबंध बनाया है और यह पाया है कि ये आंकड़े सहयोगी हैं। इस प्रकार, तीसरे देशों के निर्यात के रूप में डब्ल्यूटीए के आंकड़े निर्यातक देशों के सीमा शुल्क आंकड़ों के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। केवल इस बात का कि स्रोत अलग-अलग हैं, यह अर्थ नहीं निकलता कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना प्रकट नहीं की गई है।
- ii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि रिकार्ड में दस्तावेज घरेलू उद्योग की नई क्षमताओं के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी की टिप्पणी का समर्थन नहीं करते, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षमता वृद्धि का दावा तथा संबद्ध दस्तावेज जांच की शुरुआत से ही घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा बढ़ाई गई क्षमताओं और इसके निमित्त किए गए व्यय पर वर्तमान निष्कर्षों में विचार नहीं किया गया है।
- iii. जहां तक इस बात का संबंध है कि संबद्ध देशों से तीसरे देशों को कीमतें कुल मिलाकर समान हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से पता चला है कि निर्यातक देशों से विभिन्न देशों में कीमतों में काफी अंतर है। उपर्युक्त पैरा 91 में तालिका यह दर्शाती है।

- iv. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि कीमत कटौती की जांच की जानी चाहिए थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति न होना निर्धारित किए जाने पर तथा घरेलू उद्योग द्वारा इसे स्वीकार किए जाने पर प्राधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात द्वारा जारी आदेश के मद्देनजर कम कीमत पर बिक्री निर्धारित नहीं की।
- v. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी पहले के निष्कर्षों से पीछे हट गए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्व के निष्कर्षों को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया है तथा अब वे मौजूद नहीं हैं। इस प्रकार, पिछले निष्कर्षों के किसी संदर्भ का कोई आधार नहीं बनता। इसके अतिरिक्त प्रकटन स्तर पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है तथा हितवद्ध पक्षकारों की ओर से इस संबंध में कोई टिप्पणी करना समय पूर्व था।
- vi. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि कारणात्मक संबंध का विश्लेषण केवल संबद्ध देशों के लिए किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कारणात्मक संबंधों का विश्लेषण केवल संबद्ध देशों के लिए ही किया गया है।
- vii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आईएचएस केमिकल ग्लोबल सोडा ऐश से चुनिंदा और छिटपुट पृष्ठों पर विश्वास नहीं किया जा सकता और संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पृष्ठ बनाए गए प्रतीत होते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दस्तावेज सार्वजनिक फाइल में रखे गए थे और विरोधी पक्षकारों के पास साक्ष्य के साथ इन दस्तावेजों के प्राधिकार पर प्रश्न लगाने का पर्याप्त अवसर था।
- viii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि नियम में यह उल्लेख नहीं है कि संभावना की जांच अनुबंध-II पैरा (vii) के सिद्धांतों के अनुसार की जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए कोई निर्धारित सिद्धांत नहीं है। तथापि, प्राधिकारी समीक्षा मामलों में क्षति की संभावना के निर्धारण के लिए इन प्रावधानों को लागू करते रहे हैं। गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कानून के तहत निर्धारित खतरे के मानदंडों को संभावना की जांच के लिए लागू किया जाना है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने इन मानदंडों के आधार पर ही अपने विश्लेषण को सीमित नहीं रखा है बल्कि घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना की जांच के लिए हितवद्ध पक्षकारों द्वारा सामने लाए गए अन्य क्षति के मानदंडों की भी जांच की है।
- ix. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी की साफगोई के संबंध में अंतिम समीक्षा जांच की शुरुआत संदेह करती है, यह नोट किया जाता है कि भारत संघ बनाम कुम्हो पैट्रोकेमिकल्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के मद्देनजर अंतिम समीक्षा जांच शुरू की गई है जिसमें यह माना गया है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बाद पाटनरोधी शुल्क का एक वर्ष बढ़ाया जाना गैर कानूनी है। चूंकि, वर्तमान जांच के अंतिम निष्कर्ष जारी करने के लिए अब भी समय था और मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो रहा था, अतः अंतिम समीक्षा जांच शुरू करना उपयुक्त माना गया था, जो कि वर्तमान जांच के परिणामों के अध्यधीन है।
- x. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि संभावित जांच सहकारी निर्यातकों से एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर होनी चाहिए, यह नोट किया जाता है कि क्षति की संभावना के संबंध में उन सहकारी निर्यातकों द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है तथा इसीलिए प्राधिकारी ने उनके पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना पर विचार किया है।
- xi. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि सहकारी निर्यातकों के संबंध में क्षति की कोई संभावना नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संभावना विश्लेषण किसी एक निर्यातक पर आधारित नहीं है। इसके बजाए वह देशविशिष्ट है।
- xii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा कमाए गए लाभ स्वतः क्षति की संभावना को नहीं दर्शाते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जैसा पहले ही ऊपर सिद्ध किया गया है, क्षति होने की कोई संभावना नहीं है।
- xiii. जहां तक विभिन्न संबद्ध देशों में निपटान योग्य क्षमताओं के न होने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन और यूरोपीय देशों में घरेलू खपत वस्तुतः काफी अधिक है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अधिकतम क्षमता अभिवृद्धि (40 लाख मी.ट. अर्थात् लगभग 88 प्रतिशत क्षमता अभिवृद्धि हुई) चीन द्वारा की गई है जो इस उत्पाद के लिए बहुत कम निर्यातोन्मुखता (8 प्रतिशत) है। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातकों की क्षमता में आसन्न अथवा पर्याप्त वृद्धि के कारण क्षति का कोई खतरा नहीं दिखाई देता।

### निष्कर्ष

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक मध्यावधि समीक्षा जांच होने के नाते, शुल्क जारी करने की आवश्यकता के लिए घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना की पुष्टि होनी चाहिए। भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 (vii) में क्षति के खतरे/क्षति की संभावना के निर्धारण के लिए संगत नियम ये उल्लेख करता है कि "वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों

के आधार पर होगा न कि आरोप, अटकलबाजी अथवा सुदूर संभावना के आधार पर। परिस्थितियों में परिवर्तन जोकि ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जिससे पाटन से क्षति होगी, उसे पहले से और आसन्न रूप से स्पष्टतः देखा जाना चाहिए।”

101. प्राधिकारी तथ्यों की विस्तृत जांच करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि : (i) पाटित आयातों की वृद्धि दर के संबंध में कोई निश्चयात्मक अथवा निष्कर्षात्मक प्रवृत्ति नोट करने योग्य नहीं है। (ii) आयात से घरेलू उद्योग पर कोई ह्रासमान अथवा न्यूनीकरण प्रभाव नहीं पड़ा है, पर्याप्त ह्रासमान अथवा न्यूनीकरण प्रभाव कदापि नहीं

(iii) निर्यातकों के पास विचाराधीन उत्पाद की मालसूची की कोई जांच करना निर्यातकों से सहयोग के अभाव के कारण इस सूचना की उपलब्धता न होने के निमित्त संभव नहीं था। (iv) निर्यातक देशों के पास निपटान योग्य क्षमता की उपलब्धता आभासी रूप से दिखाई देती है परंतु इससे यह अनुमान कि चीन (जिसकी अकेले लगभग 88 प्रतिशत क्षमता अभिवृद्धि है और इस उत्पाद के लिए बहुत ही कम निर्यातोन्मुखता है) में क्षमता अभिवृद्धि से भारत में पाटित आयातों की संभावना बढ़ेगी और यह कि सभी सोडा ऐश संयंत्र लगभग 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर प्रचालित होंगे, यह एक बहुत दूर की बात है तथा यथार्थहीन संभावना पर आधारित है, बजाए सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध सत्यापन योग्य ठोस साक्ष्य के।

102. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि शुल्क हटाए जाने पर क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। अतः पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आगे आवश्यकता नहीं है।

### सिफारिशें

103 प्राधिकारी नोट करते हैं कि समीक्षा जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित की गई थी तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा पाटनरोधी नियमावली के संदर्भ में क्षति की संभावना के संबंध में जांच शुरू किए जाने और जांच किए जाने पर प्राधिकारी दिनांक 17 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या 14/17/2010-डीजीएडी द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार और दिनांक 03 जुलाई, 2012 की केंद्र सरकार की अधिसूचना संख्या 34/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क नहीं जारी रखने की सिफारिश करते हैं।

104. तदनुसार, इस मध्यावधि समीक्षा के परिणाम के अध्याधीन 16 जून, 2017 को की गई निर्णायक समीक्षा रोक दी जाएगी और इसके लिए औपचारिक आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। वर्तमान मामले की तरह पांच वर्ष की शुल्क अवधि 3.7.2017 को समाप्त हो गई, अतः वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच के तहत पाटनरोधी शुल्क 3.7.2017 से बंद किए जाने की सिफारिश की जाती है।

105. इस अंतिम जांच परिणाम के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****DEPARTMENT OF COMMERCE**

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd July, 2017

**FINAL FINDINGS**

**Subject: Mid-term Review (MTR) Anti-dumping investigation concerning imports of ‘Soda Ash’, originating in or exported from China PR, European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA.**

**No. 15/28/2014-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Rules) thereof

**A. Background of the case:**

1. Whereas, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), had issued final findings vide Notification No.14/17/2010-DGAD dated 17th February, 2012, recommending imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of “Soda Ash” (hereinafter referred to as the subject goods, or product under consideration or Disodium Carbonate), originating in or exported from China PR, European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA (hereinafter referred to as the subject countries). The definitive anti-dumping duties were accordingly imposed by the Central Government vide Notification No. 34/2012- Customs (ADD) dated 3rd July, 2012.
2. Whereas, the All India Glass Manufacturers’ Federation (AIGMF), a representative body of importers/users of the subject goods, hereinafter referred to as the applicant, submitted an application on 21st Jul 2015 requesting for initiation of a mid-term review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods from the subject countries in accordance with section 9A of the Customs Tariff Act 1975 read with Rule 23 of the Rules. They claimed that the circumstances that were prevalent during the period of investigation of the original investigation had changed significantly leading to a situation where the existing anti-dumping duties were no longer warranted.
3. Whereas, the applicant submitted that the import prices as well as the domestic selling prices of the subject goods had increased significantly. It was also submitted that the cost of major raw materials had also increased, but not in proportion to the increase in the prices of the imports of the subject goods from the subject countries. The applicant further submitted that the significant increase in import prices led to increase in the landed value of imports resulting in decline of the injury margin and as a consequence the need for reviewing the current level of duties had arisen.
4. And Whereas, Rule 23 of the Rules read with Section 9A of the Act require that the Designated Authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, wherever warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the Designated Authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.
5. And whereas having regard to the information provided by the applicant, substantiating the need for such review and indicating changed circumstances necessitating prima facie a review of the measure in force, the Authority vide Notification No. 15/28/2014-DGAD dated 21<sup>st</sup> July, 2015, initiated the present Mid-term Review (MTR) investigation of the final findings notified vide Notification No. No.14/17/2010-DGAD dated 17th February, 2012.
6. And whereas the Designated Authority issued disclosure statements in terms of Rule 16 of the Rules on 14.09.2016 and sought comments from the interested parties.
7. And whereas the Designated Authority issued final findings on 23.09.2016 after considering the comments of the interested parties.

8. And whereas Nirma Ltd and DCW Ltd filed writ petitions before Hon'ble High Court of Gujarat initially challenging the disclosure statements dated 14.09.2016 issued by the Designated Authority in the present Midterm Review thereafter also challenged the respective final findings dated 23.09.2016 by amending their writ petitions.
9. And whereas Hon'ble Gujarat High Court vide its common judgment dated 23.02.2016 quashed the disclosure statements dated 14.09.2016, final findings dated 23.09.2016 as well as subsequent notifications issued by the Central Government under rule 18 of the rules and restored the proceedings to the designated authority, directing the Designated Authority to issue fresh disclosure statement, in consonance with the relevant statutory provisions and in the light of the observations made in the judgment
10. And whereas the Designated Authority conducted another oral hearing on 25.04.2017 giving opportunity to the interested parties to present their views orally. The interested parties were allowed opportunity to file written submissions and thereafter rejoinder to the submissions made by other interested parties.

**B. Procedure**

11. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

- i. The Authority sent copies of the initiation notification dated 21<sup>st</sup> July 2015 to the embassies of the subject countries in India, known exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, and the domestic producers, as per available information. The known interested parties were requested to file the questionnaire responses and make their views known in writing within the prescribed time limit.
- ii. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to embassies of the subject countries along with a list of known exporters/producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond within the prescribed time.
- iii. Copy of the non-confidential version of the application filed on behalf of the applicant was made available to the known exporters, domestic producers and the embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
- iv. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the MTR to the following known producers/exporters in the subject countries and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4) of the Rules:

Shandong Haihua Group, Shandong Haihua Group Co., Ltd. Develop Zone of Haihua Weifang City, Shandong, China
Qinghai Alkali Plant (Zhejiang Glass Chaina's Qingtai Alkali Plant ( Zhejiang Glass China's Qinghai Delingha Industrial Park Zip:817000 – China
Jinshan chemical co. China's Zhengzhou City in Henan Province, Zhengzhou City Fushoushan Street 87,China
Hebei Tangshan Sanyou Al kali Industry Company Nanpu Development Area,TangShan,Hebei,China
Tianjin Soda Ash Plant No. 87Xinhua Road Tanggu District Tianjin China
SIMAN LTD Pob 29 Kazanlak SL Zagora Bulgaria 6103
Solvay Sodi AD Zip Code: 9160 Bosnia and Herzegovina Brunner Monday Winnington Lane Mond House, Northwich, Cheshire, UK, CW8 4DT
SPIN INTERNATIONAL 13 RUE DE PASSY Paris 75016
BELVEDERE SRL ROMANIA Cetatianu Ioan GALATI, Romania 800198
Asha Trade Import Export Mangaliei Nr 71 BL PIS SC D Apt 36 Constanta 900116Romania
GHCL Romania Ghcl Upsom Ocna Mures Alba County Romania 515700
Sisccam Sode Lukavac " The first street 1 75300 Lukava

Bosnia and Herzegovina
Magadi Soda Company P O Box 1 - 00205, Magadi, Kenya.
ALLIED NETWORKX COMPANY LTD Asili Co-Op House Moi Avenue Nairobi Kenya 72964 00200
FMC Industrial Chemicals 1735 Market Street ' Philadelphia, PA 19103 USA
OCI Chemical Corporation 1800 West Oak Commons Court Suite 100 Marietta, GA 30062
SOLVAY SODA ASH Headquarters 5333 Richmond Ave., Houston, TX 77098 Mailing address: P.O. Box 27328, Houston, TX 77227
General Chemicals Industrial Products 120 Eagle Rock Avenue East Hanover, New Jersey, USA.
ANSAC 15 Riverside Avenue 2nd Floor Westport, CT 06880 USA
FMC Corporation Wells Fargo Bank N.A. Shareowner Services P.O. Box 64854 St. Paul, MN 55164-0854 Or161 N. Concord Exchange South it. Paul, MN
Soda Ash Soda Ash Business ICI Pakistan Limited 63-Mozang Road Lahore, Pakistan
Olympia Chemicals Ltd. 23-Davis Road, Lahore , Pakistan
Syrina Trade Co., Arum s.88 office 251a Donetsk Ukraine

- v. In response to the initiation of the subject investigation, following producers/exporters from Pakistan responded by filing questionnaire response and made submissions:
- Olympia Chemicals Limited, Pakistan.
  - ICI Pakistan Limited, Pakistan.
- vi. Questionnaires were sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Anti-dumping Rules:

Gujarat Guardian Ltd, Village- Kondh, Valia Road, Plant Sate Highway No.13, Ankleshwar, Bharuch 393001
Float Glass India Ltd., T-7, Midc, Industrial Area, Taloja, Maharashtra
Hindustan National Glass & Ind. Ltd., Rishra, West Bengal
Procter & Gamble Hygiene & HealthCare, Mandideep Plnt L&C-MFG, Plot No.182, Mandideep, Madhya Pradesh
Advatecg Industries Pvt Ltd, Dhanali, Village –Dhanali, Al-Kadi Distrcit, Mahesana, Gujarat
U.P. Glass Manufacturer,Syndicate, 14-Monapuram, Near Ganesh Nagar, Firozabad- 283203, U.P.
Fena (P) Ltd, A-237, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-20

Pollachi Chamber of Commerce & Industry, RP Complex, IInd floor, 14, Balagopalapuram Street, Pollachi-642001
Power Soap Ltd, 62-B, North Boag Road, T.Nagar Chennai – 600017
Alembic Glass Industries Ltd, Alembic Road, Baroda (Vadodara) Gujarat
Deepak Nitrite Ltd, 4/12, Chemical Complex, GIDC, Nanfessari, Baroda (Vadodara) Gujarat
Hindustan Unilive Ltd., Party Address Dakshina Building, 8th Floor, Plot No-2 Sector-11, CBD Belapur, Navi Mumbai
Albright Morarji & Pandit Ltd, Ambernath, Dist. Thane, Maharashtra
Saint-Gobain Glass India, Head Office and Plant: A-1 SIPCOT Industrial Park, Sriperumbudur-602105, Kanchipuram District – Tamil Nadu
Asahi India Glass Ltd., 5th Floor, Tower-B, Global Business Park, Mehrauli-Gurgaon Road, Gurgaon-122002(India)
Shree Union Organics P Ltd, BS-3, Apeejay. 130, Bombay Samachar Marg, Mumbai-23
Vasundhara Rasayan Ltd, C-104, MIDC Industrial Area, Mahed, Dist. Raigad, Maharashtra
Shantinath Detergents Pvt Ltd, P-15, Kalakar Street, Kolkata-700007
Advance Home & Personal Care Ltd, Advance Surfactants India Ltd, 511/2/1, Village Rajokri, New Delhi-38
S. Kumar Detergent P. Ltd, Plot No.34, Sector-2, Industrial Area, Pithampur-454775 Distt Dhar, M.P.
Hind Silicates Pvt Ltd., 3A, Auckland Place, 5th floor, Kolkata-17
P & J Cretechem (P) Ltd, 318, Swapnalok, 92/93, SD Road, Secunderabad-500003, AP, India
J.J. Patel Industries, Gondal Road, B/H Rajkamal Petrol Pump, Vavdi, Rajkot-360004
Modern Glass Industries, Coal Siding Road, S.N. Road, Firozabad-283203
Sandeep Organics Pvt Ltd., 104, Nain Krupa, 118/122, Kazi Syeed, Street, Masjid Bunder (West), Vadgadi, Mumbai -400003
Alembic Glass Industries Ltd., Alembic Road, Baroda(Vadodara) Gujarat
Rohit Surfactants(P) Ltd., 117/H-2/202, Pandu Nagar, Kanpur-05
BDJ Glass Industries Pvt. Ltd, 1 Kyd Street, Place Court, 1 <sup>st</sup> Floor, Suite-14-A, Kolkata-700016
Jagatjit Industries Ltd., Plot No.78, Sector-18, Institutional Area, Gurgaon-122001
Haldyn Glass Gujarat Ltd., 9, Gayatri Commercial Complex, Behind Mittal Industrial Estate No.5, Andheri Kurla Road, Marol Naka, Andheri(E), Mumbai-400059
Hipolin Limited, Madhuban”, 4 <sup>th</sup> Floor, Ellisbridge, Ahmedabad-380006



Modern Glass Industries, Coal Siding Road, S.N. Road, Firozabad-283203
Detergent Manufacturers, Association (Delhi Region) 148, New Okhla Industrial Complex-1, New Delhi-110020
Mauli Exports, Plot No.97-98, Sector – 25, Part-II, Industrial Area, HUDA, Panipat – 132 104, Haryana
M/s Chempex International, 393/III/6 Bazer, Bikanerian, Katra, Ahluwalia, Amritsar, Punjab
Tata Chemicals Ltd., Leela Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai -59
M/s Tuticorin Alkali Chemicals and Fertilizers Ltd., 534, Anna Salai, Teynampet, Chennai -18
AGI Glasspac, Glass factory Road, Moti Nagar, Post Box. 1930,Shanth Nagar, Hyderabad – 500 018
Power Soaps Ltd., A-8, 1st Main Road, Ambattur Industrial Estate Chennai – 600 058
Hindcon Chemicals (P) Ltd., 62/B, Braunfled Row, 1st floor, Calcutta – 700 027
Empire Industries Ltd., Empire House, 414, Senapati Bapat, Lower Parel, Mumbai – 13

vii. In response to the above notification, following importers/users filed importer questionnaire response and made submissions.

- a. Hindustan Unilever Limited
- b. Gold Plus Glass Industry Limited
- c. HNG Float Glass Limited
- d. HSIL Limited, Packaging Products Division
- e. La Opala Rg Limited
- f. Piramal Glass Limited

viii. Questionnaires were also sent to the known domestic producers of the subject goods in India for necessary information and response.

M/s DCW Ltd
M/s GHCL Ltd
M/s Nirma Ltd
M/s Saurashtra Chemicals Ltd
Tata Chemicals Ltd

ix. Initiation notification was also sent to the following associations:

Detergent Manufacturers Association (Delhi Region)
Indian Chemical Merchants & Manufacturers Association
Bulk Drug Manufacturers Association(India)
Indian Glass Manufacturers' Association
The Dyers & Chemical Merchants Association
All India Glass Manufacturer's Federation
Alkali Manufacturers Association of India
Indian Soap & Toiletries Maker's Association

- x. Apart from the foreign producers/exporters, importers/users, domestic producers and their representatives, the following domestic producers and interested parties also made submissions during the course of this investigation:
- i. Detergent Manufacturers Association of India
  - ii. Detergent Manufacturers Association (Delhi Region)
  - iii. Bengal Soaps and Detergents Manufacturers Welfare Association
  - iv. Hindustan Unilever Ltd
  - v. Sandeep Organics Ltd
  - vi. RSPL Ltd
  - vii. Asoka Enamel and Glass Works Pvt Ltd.
  - viii. Indian Council of Small Industries
  - ix. All India Glass Manufacturers Federation
  - x. Saint Gobain Glass India Ltd.
- xi. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- xii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange for details of imports of subject goods for the past three years in addition to the period of investigation. The Authority has, therefore, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis.
- xiii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry.
- xiv. Investigation was carried out for the period starting from 1st April, 2014 to 31st March, 2015 (POI). However, injury examination was conducted for a period from 2011-12, 2012-13, 2013-14 and the POI. The Authority also called for the relevant information/data from the interested parties for post POI (1<sup>st</sup> April 2015 to 30<sup>th</sup> Sep. 2015) for conducting likelihood analysis. The Authority also obtained further data on post- POI from DGCI&S to further supplement the likelihood analysis.
- xv. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority also provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 2nd March, 2016. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xvi. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, judgment of Gujarat High Court the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 25<sup>th</sup> April, 2017. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xvii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xviii. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts of the investigation were disclosed by the Authority to the known interested parties vide a disclosure statement issued on 7<sup>th</sup> June, 2017 and comments received on the same, to the extent considered relevant by the Authority, have been examined and addressed in this finding. Earlier disclosure statement dated 14.9.2016 was quashed by the Hon'ble High Court.
- xix. Wherever any interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded the disclosure on the basis of available facts.
- xx. \*\*\*represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by

the Authority under the Rules.

- xxi. The average exchange rate of 1US\$ = Rs 61.69 prevailing during the POI has been adopted by the Authority

### **C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE:**

12. The Product under Consideration (PUC) in the original investigation as well as in the present review is 'Soda Ash'. In the original investigation the product was defined as under:

*"i. The product under consideration in the present investigation is Disodium Carbonate, also known as Soda Ash having chemical formula  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ . Soda Ash is produced in two forms- Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is bulk density. It can be produced through synthetic route and natural route, known as dissolution process. The present investigation includes all types and forms of Soda Ash.*

*ii. Soda Ash is an essential ingredient in the manufacture of detergents, soaps, cleaning compounds, sodium based chemicals, float glass, container and specialty glasses, silicates and other industrial chemicals. It is also widely used in textiles, paper, metallurgical industries and desalination plants. Soda Ash is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act under subheading No. 2836.20. The customs classification is, however, indicative only and is not binding on the scope of the present investigation."*

13. None of the importers, consumers, exporters, domestic industry and other interested parties has made any comment or submissions with regard to product under consideration and like articles. In view of the above, the scope of the product under consideration in the present review investigation remains the same as that in the original investigation.

### **D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

#### **Submissions made by the Petitioner and other interested parties**

14. The following submissions have been made by the applicant and other interested parties with regard to standing and scope of the domestic industry:
- i. Concerned domestic producers claiming themselves to be domestic industry are themselves big importers of subject goods from the subject countries. Wholly owned subsidiaries of certain domestic producers have also exported subject goods to India significantly. Domestic producers categorically admitted that for supplying customers of southern and eastern India they are predominantly relying on imports. Therefore such domestic producers are not eligible for becoming domestic industry as per anti-dumping rules.
  - ii. The largest Indian domestic producer "Tata Chemicals Ltd." imported material from its subsidiary from Kenya and from unrelated producers from EU and China.
  - iii. Nirma has acquired wholly owned companies in other countries and have been importing subject goods from those companies. Designated Authority should examine whether low price of import may have been compensated in price received by Nirma.
  - iv. GHCL is also importing from other producers/exporters. GHCL has more than 87% capacity utilization in the period of investigation which is maximum for these industries. GHCL is a major producer with capacity of 8,50,000 MT and it has compulsion to import subject goods from various countries including subject countries. They are paying Anti-Dumping Duty while importing subject goods and still they are earning profits.
  - v. Saurashtra Chemicals Ltd. (SCL) is already amalgamated with Nirma and does not exist as a separate legal entity/company.
  - vi. Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers Ltd is the smallest and the most inefficient member of the domestic producers in terms of production. It suspends its production again and again because of non-availability of raw material
  - vii. Only DCW is a small player having the capacity of about 3,00,000 MT per year. It is utilizing the capacity at higher rate and earning profit. Such a company is not entitled for any continued protection.
  - viii. Neither the so-called domestic industry, nor the Authority, has clarified which of the domestic producers constitute domestic Industry" in terms of Rule 2(b) of anti-dumping rules .

**Submissions made by Domestic Industry**

15. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing of the domestic industry:
- i. Petitioner has not identified the Domestic Industry. Application seeking withdrawal of anti-dumping duty is incomplete unless the applicant has identified "a domestic industry", particularly when the allegation is that there is no injury to the domestic industry. The entire proceedings and the investigations are required to be terminated for this reason
  - ii. Barring GHCL and Tata Chemicals, none of the companies have themselves imported the subject goods during the POI.
  - iii. The imports by GHCL were only to maintain market presence in order to afford continuity when enhanced capacities are made available.
  - iv. GHCL had a related company in Romania which is now closed. Nirma has a related producer in USA, which has exported Soda Ash to India during the POI. However, the exports by this related company located in USA have been made directly by itself.
  - v. DCW does not have any related producer-exporter outside India.
  - vi. Tata Chemicals has a related producer in Kenya, US and Europe. The Kenyan company is a subsidiary of Tata Chemicals which has exported goods to India. These exports have been directly made by Tata Chemicals. TCL may be considered as ineligible domestic industry if it is deemed fit.
  - vii. There are many reasons for imports by domestic industry. Firstly, the landed price is materially below the price at which domestic producers can sell in these regions. Secondly, the near future expansion of capacities requires prior creation of demand which is being done by supplying imported product to these consumers. Thirdly very nominal profits have been earned on these imports. Fourthly, duties were recommended without including freight which should have been included to ensure fair comparison.
  - viii. Anti-dumping duties are on non discriminatory basis and if the domestic producers have imported the product under consideration they have paid applicable anti-dumping duty.
  - ix. As regards oral hearing being ineffective, it is to mention that it was incumbent upon the applicant importer association to identify the domestic industry and thereafter establish no injury and no likelihood therein.
  - x. The capacity of Nirma shown is including the capacity of SCL. SCL was a separate entity in the beginning of the injury period and later merged to Nirma. The information of Nirma includes information of SCL.

**Examination by the Authority**

16. The Authority notes that Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules read as follows:-

*"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".*

17. Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules provides that domestic producers which are related to the exporters or importers or which are themselves importers of the allegedly dumped articles may be excluded when determining the domestic industry in certain situations. The Authority is of the considered view that the use of the word 'may' in Rule 2(b) suggests that the two types of producers in question, i.e. related producers and producers importing the dumped product, are not automatically excluded from being part of the domestic industry. On the contrary, it has been the consistent practice that exclusion of such producers must be decided on a case-to-case basis, on reasonable and equitable grounds, and by taking into consideration all the legal and economic aspects involved.
18. The Authority notes that in the original investigation also the some of the domestic producers were involved in imports of subject goods from the subject countries or were related to the exporters/importers of subject goods from the subject countries. In the final findings of the original investigation, the Authority has clearly dealt with Domestic Industry and its standing. The Authority had considered GHCL, Nirma Ltd and DCW Limited as "domestic industry", in accordance the requirements of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules. For the purpose of present investigation, the Authority has decided to accept the conclusion drawn at the time of original investigation.

**E. MISCELLANEOUS SUBMISSION****Submissions made by the Applicant and other Interested Parties**

19. Following miscellaneous submissions have been made by applicant and other interested parties:

- i. The domestic industry did not exercise any due diligence or care in ensuring the accuracy of the data provided in response to the MTR and they did not even file the necessary certificate of correctness.
- ii. The claim of inclusion of freight has no legal tenability and in fact principle of res judicata is applicable to this issue since the domestic industry is once again pressing this issue before the same Authority which they did in the original investigation and was rejected by the Authority.
- iii. During the oral hearing, the domestic industry did not rebut the submissions made by the Respondents and in view of principle of 'Doctrine of Non-Traverse', it is deemed that the Domestic Producers admitted such submissions.
- iv. The two mid-term reviews should be combined as the product under consideration, the composition of the Domestic Producers as well as the period of investigation are the same.
- v. The domestic industry has to be inferred as domestic industry as defined in the previous investigation. It is only and only the domestic producers themselves, who can lead information in this regard and not the applicant. There exists no need under Rule 23(1A) of Anti-Dumping Rules for the Applicant to identify the domestic industry and make allegations.
- vi. Since writ petitions and appeals are pending in High Court and CESTAT on the issue of inclusion of freight, filed by the domestic producers, authority should not change its settled practice regarding determination of non-injurious price and continue to exclude inland freight while determining non-injurious price. This issue of inclusion/non-inclusion of freight may be decided as and when the matter is finally settled by the High Court or the CESTAT.
- vii. There is a demand supply gap in the domestic market since the domestic industry is unable to supply despite having capacities.
- viii. There are thousands of tiny, small and medium scale detergent producers in India providing employment to masses. Anti-dumping duties imposed on soda ash, the major raw material for detergents, cause much hardship to them. Non supply of required volume by domestic industry due to demand supply gap forces these industries to depend upon imported material by bearing the anti-dumping duty, thereby making their products cost ineffective.
- ix. There is a mutual understanding among the domestic producers of soda ash in terms of price fixation amounting to cartelization at the cost of downstream industries.
- x. The subject goods are covered under Cost Accounting Record Rules(CAR). Therefore, the Cost of production of the domestic industry to be considered on the basis of CAR. Therefore, the Authority to consider COP of the domestic industry based of CAR and if the same is not provided already the Authority may call for the relevant information.
- xi. Information submitted by the Domestic Industry ( DI ) is not in the prescribed format of the DA. Selective information with regard to capital employed like net fixed assets and working capital is only provided whereas the prescribed format requires capital employed based on the books of accounts for a particular period.
- xii. Dumping Margin is irrelevant in the MTR investigation as per Rule 23 as duty can be withdrawn where the injury to the DI is not likely to continue or recur, if the duty is withdrawn. Even positive dumping margin cannot justify the continuation of the duty.

**Submissions made By Domestic Industry**

20. Following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- i. The petition is deficient as it claims absence of injury without establishing "domestic industry".
- ii. The petition doesn't establish why antidumping duties are required to be withdrawn. The objective of midterm review is to analyze whether the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur in the event of premature revocation of duty.
- iii. The Authority is requested to consider the submissions by domestic industry with regard to methodology for determination of injury margin generally applied by the Authority and as applied at the time of original

- investigations and reasonableness and appropriateness of the same in the facts and circumstances of the present case. As regards NIP the provisions prescribed under Annexure III to the Anti-Dumping Rules were being practiced earlier and were being followed by the Authority prior to introduction of law.
- iv. As regards difference in production data in the standing table and injury statement, it is stated that there was a clerical error which is regrettable but it cannot be said to cause serious prejudice to the interested parties.
  - v. There is no prescribed requirement for filing of certificate of correctness with the information filed. The domestic industry cannot be penalized on the basis of clerical human errors by depriving it of a legitimate protection.
  - vi. As regards the argument of interested parties that domestic industry is not willing to supply in South due to freight, it is submitted that firstly domestic industry has not rejected any material to any consumer and secondly that this shows that freight could be recognized for determining injury margin.
  - vii. The reliance on Doctrine of Non Traverse is unfounded because hearing has a meaning when submissions are made and rejoinder submissions are made to submissions raised by other parties.
  - viii. The domestic industry has no objection to cumulation of two mid-term reviews, however this will render initiation invalid and warrant initiation of a fresh midterm review investigation.
  - ix. India has shortage in soda ash production vis-à-vis global market having surplus. RSPL Ltd, a leading detergent manufacturer, is setting up a soda ash plant in India with 5 lakh MT production capacity for captive consumption and sale in domestic market. With their entry, India would become self-sufficient in Soda Ash. If the present anti-dumping duties are withdrawn and the prices decline, then RSPL would suffer injury. Therefore, the present anti-dumping duties should continue.
  - x. Authority is required to determine injury margin only in those cases where the Designated Authority finds that the imports are causing injury – whether it is a fresh case or a midterm review or a sunset review. Injury margin is not to be calculated if the finding is based on likelihood and merely same quantum of ADD as existed is confirmed as has been the practice of the Authority.

### **EXAMINATION OF THE AUTHORITY**

21. Rule 23 of Anti-dumping Rules states as follows:

*(1) Any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.*

*(1A) The Designated Authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the Designated Authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.*

*(1B) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or (1A), any definitive anti-dumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the Designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.*

*(2) Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding twelve months from the date of initiation of such review.*

*(3) The provisions of rules 6, 7, 8, 9/10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall be mutatis mutandis applicable in the case of review.*

22. Article 11.2 of the Anti-dumping Agreement provides that the Authority shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review. Interested parties shall have the right to request the authorities to examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping,

whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review under this paragraph, the Authority determines that the anti dumping duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately.

23. The applicant and the other interested parties have contended that the scope of mid- term review is different from the scope of sunset review. The applicant has contended that in a mid-term review DGAD is required to consider and determine whether there is sufficient justification for withdrawal of anti-dumping duty before completion of five years, whereas in sunset review DGAD is required to determine whether anti- dumping duty is required to be extended further or not after expiry of five year. The domestic industry also contended that in a mid-term review, current performance alone is insufficient to conclude whether the anti-dumping duty can be withdrawn at this stage and that the Authority is required to consider the likely situation that may arise when anti dumping duty is withdrawn.
24. The Authority has examined the issues raised by the interested parties and domestic industry and notes that Rule 23 of the Anti-dumping Rules obligates the Authority to review the need for the continued imposition of an anti-dumping duty, *inter alia*, upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review after a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the Authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to the conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.
25. As regards the contention of the applicant and other interested parties that domestic industry did not exercise any due diligence or care in ensuring the accuracy of the data provided in response to the MTR and they did not even file the necessary certificate of correctness, the Authority notes that the relevant data/information of the domestic industry has been verified.
26. As regards the argument of applicant and other interested parties that the claim of the domestic industry for inclusion of freight in the NIP has no legal tenability and should not be acceded by the Authority, it is noted that the Gujarat High Court has held that NIP is not required to be determined in the present case
27. The applicant and other interested parties have argued that two mid-term reviews i.e. the present one and the one against Turkey and Russia initiated by the Authority should be combined as the product under consideration, the composition of the domestic producers as well as the period of investigation are the same. The Authority notes that the two midterm reviews are related to two different final findings and duty notifications involving different set of countries and therefore, it would not be appropriate to combine both these mid-term reviews.
28. As regards the argument of the interested parties that there is a demand supply gap in the domestic market since the domestic industry is unable to supply despite having capacities and because of which downstream industries, especially tiny, small and medium scale detergent producers, are suffering, the Authority notes that in the anti-dumping law the domestic industry is not obliged to fulfill the entire demand in the domestic market. Since imposition of anti-dumping duties does not prevent import and its intent is only to rectify an unfair position due to dumping, the user sector can always import and fulfill their extra demand. The Authority also notes that GHCL and Nirma were expanding their capacities during the present POI and the same have now gone commercial.
29. As regards the argument of the interested parties that there is a mutual understanding among the domestic producers of soda ash in terms of price fixation amounting to cartelization at the cost of downstream industries, the Authority notes that the allegation is unsubstantiated.

#### **F. Determination of Dumping Margin**

#### **Market Economy Claims, Normal Value, Export Price and Dumping Margin**

#### **Submissions made by the Applicant and Other Interested Parties**

30. The submissions made by the Applicant and other interested parties with regard to market economy, normal value, export price and dumping margin are as follows:
  - i. The cost of production is significantly lower when soda ash is produced from natural resources. If such revelation is correct, then the Normal Value in those countries would be significantly lower.
  - ii. Domestic producers have their subsidiary companies in the subject countries i.e. NIRMA has its subsidiary in USA and TATA has its subsidiary in Kenya and USA. Therefore the Domestic Industry should be able to provide the Normal Value of the exporter in the subject countries.
  - iii. Authority should calculate the normal value for China and Ukraine on the basis of price obtained from the subsidiary companies of the Domestic Producers in the Market economy country or the constructed value of

market economy third country.

- iv. Domestic industry has used its benchmark prices for determining normal value for the subject countries except China and Ukraine despite having related producers in most of these countries. Authority should not accept such methodology of determination of normal value.
- v. As no evidence has been provided by the Domestic Producers in respect to how they have taken the values for the Ocean freight, Marine Insurance, Commission, Inland Transportation, Port Expenses and Bank Charges, the Designated Authority is requested to call for evidence and seek such information instead of relying blindly on the information furnished by the domestic producers.
- vi. Normal Value and the Export Price for the non-cooperating exporters should be calculated on the basis of export price and normal value of the cooperating exporters.
- vii. There were only 3 producers operating in Ukraine at the time of original investigation. However, during the past few years, circumstances have changed drastically in Ukraine as a result of which two out of three plants have shut down and one operating plant is based in Crimea, which has since been annexed by Russia. Resultantly, there being no producer in Ukraine, the anti-dumping duties are required to be withdrawn against Ukraine.
- viii. Ukraine should be treated as market economy as it was treated the same in the previous investigation.
- ix. In case of European Union and US it has been determined on the basis of the average prices as published in IHS Chemicals in POI but the figures used has not been disclosed,
- x. Individual margin should be given to the exporters such as Soda Sanayii as it has cooperated throughout the investigation and has filed complete questionnaire response. Even the post POI data is duly filed and verified by the Authority.

#### **Submissions made by the domestic industry**

31. The submissions made by the domestic industry with regard to market economy, normal value, export price and dumping margin are as follows:
  - i. China and Ukraine are non-market economy. China and Ukraine have been treated as non-market economy by India, European Union and United States in the past three years.
  - ii. Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity.
  - iii. Market economy status cannot be given unless the responding exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values.
  - iv. Market economy status cannot be given unless the responding exporter establishes that their books are audited in line with international accounting standards.
  - v. Market economy status cannot be granted even if one of the parameters is not satisfied.
  - vi. It is for the responding exporters to establish that they are operating under market economy conditions.
  - vii. Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim.
  - viii. In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.
  - ix. Domestic industry has determined Normal Value in China and Ukraine on the basis of price paid in India. Additionally, domestic industry has determined normal value on the basis of cost of production in India, by taking the international price of the major raw materials and duly adjusted with selling, general and administrative expenses and considering the consumption norms of the domestic industry.
  - x. Domestic industry has considered prices for USA, and EU as per prices reported in IHS Chemical Global Soda Ash.
  - xi. Since trade law journals do not publish prices of product under consideration for Iran, the domestic industry has determined normal value in Iran on the basis of best estimates of cost of production in Iran, considering consumption norms of the domestic industry and power prices in Iran.
  - xii. Normal value for Pakistan has been made on the basis of Annual Report of ICI Pakistan, which also disclosed the production and sales value for the company.
  - xiii. Normal value for Kenya has been made on the basis of Annual Report of Tata Chemical Ltd, a listed company in India having a plant in Magadi, Kenya.
  - xiv. The export price has been on the basis of DGCI&S transaction wise data. The export prices have been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, inland transportation, port expenses, bank charges and VAT



difference.

- xv. Both the normal value and export price have been determined at ex-factory level. Domestic industry has taken into account all physical characteristics of the product for which the information is available. Thus, the comparison made by the domestic industry constitutes a fair comparison.
- xvi. The dumping margins are not only de-minimis but also substantial.
- xvii. As regards cost of production being lower in countries where production is from natural resources, the IHS Chemical Journal gives out the price prevalent in the countries which leads to presumption of high profits made in these countries.
- xviii. The domestic industry has provided price prevailing in the country which is what needs to be considered.
- xix. The basis of construction of normal value of China and Ukraine may be decided by Designated Authority as it deems fit.
- xx. The domestic industry has followed conservative approach with respect to evidence taken for various adjustments.
- xxi. The Authority should take the highest normal value and lowest export price transaction in order to determine dumping margin for non cooperative exporters.

#### **Examination of Market Economy Claims by the Authority :**

#### **China PR & Ukraine**

32. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested embassies of respective countries in India to advise the producers/exporters in their country to provide the required information. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti-Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and establish to the contrary. However, none of the producers/exporters in China PR and Ukraine have cooperated and filed response to the exporter's questionnaire and MET questionnaire in the present investigation. In view of the above position and in absence of rebuttal of non-market economy presumption, the Authority considers it appropriate to proceed with para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value for China PR and Ukraine.

#### **G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE**

33. The exporter's questionnaire responses submitted by the following producers/ exporters from Pakistan have been accepted by the Authority and considered for the purpose of determination of normal value, export price and dumping margin.
- a) Olympia Chemicals Limited, Pakistan
  - b) ICI Pakistan Limited, Pakistan
34. In respect of other producers/exporters from the respective subject countries the Authority has determined normal value on the basis of best available information as the Rules.

#### **China PR and Ukraine**

35. In view of non-cooperation by the Chinese and Ukrainian producers/exporters, the Authority considers it appropriate to proceed with the provisions of para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value. Para 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules provides that:

*"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated Authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."*

36. Accordingly, In the absence of any reliable price and cost details for the subject goods in any market economy third country, the Authority has constructed the normal value for China PR and Ukraine on the basis of price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin. Accordingly, the Normal Value for all the exporters from China PR has been constructed for PUC and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

**European Union (EU)**

37. The Authority notes that none of the producers/exporters from EU have submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8) of the Rules for determining normal value in respect of EU. Accordingly the Authority has determined the normal value of EU at ex-factory level on the basis of the average prices during the POI published in IHS Chemical Supplement an international journal which periodically publishes the prices of Soda Ash prevailing in various countries including EU, The normal value so determined for EU has been mentioned in the dumping margin table given below.

**USA**

38. The Authority notes that none of the producers/exporters from USA have submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8) of the Rules for the determination of normal value in respect of USA. Accordingly the Authority has determined the normal value in respect of USA at ex-factory level, on the basis of prices periodically published in IHS Chemical Supplement , an international journal which periodically publishes the prices of Soda Ash prevailing in various countries including USA. The normal value so determined for USA has been mentioned in the dumping margin table given below.

**Iran**

39. The Authority notes that none of the producers/exporters from Iran have submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8) of the Rules for the determination of normal value in respect of Iran. Accordingly the Authority has determined the normal value in respect of Iran at ex-factory level, on the basis of prices periodically published in IHS Chemical Supplement , an international journal which periodically publishes the prices of Soda Ash prevailing in various countries including Iran .The normal value so determined for Iran has been mentioned in the dumping margin table given below.

**Pakistan**

40. The Authority notes that the two exporters of Pakistan namely, ICI Pakistan Limited and Olympia Chemicals Limited, Pakistan have submitted exporter's questionnaire response furnishing details of domestic sales of subject goods during the POI.

**ICI Pakistan Limited**

41. In the exporter's questionnaire response, during the POI of the present MTR investigation, ICI Pakistan Ltd has reported total domestic sales of \*\*\*\* MT of subject goods for the gross invoice value of \*\*\*\* PKR. Adjustment has been claimed on account of sales tax, commission, discount, cargo handling charges, storage charges, insurance, selling and distribution cost i.e. salary, others and corporate general administration expenses, taxation on domestic profit, cost of holding finished goods and cost of credit. However, the respondent company could not furnish complete back up documents to substantiate the claimed adjustments. In view of the above position, the Authority could not determine the normal value for ICI Pakistan Ltd.

**Olympia Chemicals Limited, Pakistan**

42. Olympia Chemical limited, Pakistan has reported domestic sales of \*\*\*\* MT of subject goods during POI with gross invoice value of PKR \*\*\*\*. Adjustment has been claimed on account of VAT, discount, commission, inland freight, credit cost and bank charges. The Authority has admitted the adjustments as claimed and determined the normal value at ex-factory level in respect of Olympia Chemical Limited, Pakistan. The normal value so determined for Olympia Chemical Limited, Pakistan has been mentioned in the dumping margin table given below.

**Non Cooperative exporters of Pakistan**

43. The Authority notes that no other producer/exporter from Pakistan has submitted exporter's questionnaire response in the present investigation. Therefore, the Authority has adopted the highest normal value of the cooperative exporter from Pakistan for determining the normal value for the non-cooperative producers/exporters from Pakistan. The details of the normal value so determined for the non-cooperative producers/exporters from Pakistan have been mentioned in the dumping margin table given below.

**Kenya**

44. The Authority notes that none of the producers/exporters from Kenya has submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8) of the Rules for the determination of normal value in respect of Kenya and accordingly determined the normal value for all producers/exporters of Kenya. The details of the normal value so determined for the non-cooperative producers/exporters from Kenya have been mentioned in the dumping margin table given below.

**H. EXPORT PRICE****China PR, EU, USA, Iran, Kenya and Ukraine**

45. The Authority notes that none of the exporters/producers of subject goods from China PR, EU, USA, Iran, Kenya and Ukraine has responded to the Authority in the form and manner prescribed. In the absence of exporter's questionnaire response from the producers/exporters from the aforesaid countries, the Authority has determined the export price in respect of these countries on the basis of best available information in terms of Rule 6(8) of the Rules. The Authority has relied upon DGCIS import data for the purpose of arriving at the weighted average CIF value of imports from the aforesaid countries during the POI. Adjustments on account of ocean freight, insurance, commission, port expenses, inland freight and bank charges, as claimed by the petitioner, have been considered to arrive at the net export price in respect of the said countries. Accordingly, export price at ex-factory level for all exporters of China PR, EU, USA, Iran and Ukraine has been determined as given in the dumping margin table given below.

**Pakistan****ICI Pakistan Ltd.**

46. As per the exporter questionnaire response by ICI Pakistan Ltd., it has exported \*\*\*\*\* MT of subject goods to India for gross invoice value of PKR \*\*\*\*\* during POI . The Company has claimed adjustments on account of commission, discount, loading and unloading expenses, port charges, insurance, service charges, taxation on domestic profit, interest income on advance received. However, the respondent company could not furnish complete back up documents to substantiate the claimed adjustments. In view of the above position, the Authority could not determine the net export price for ICI Pakistan Ltd.

**Olympia Chemicals Ltd.**

47. As per the exporters questionnaire response filed by Olympia Chemicals Ltd., it has exported \*\*\*\*\* MT of subject goods to India for gross invoice value of US\$ \*\*\*\*\* during POI . After making adjustments, as claimed by the Company, on account of commission, inland freight, credit cost, bank charges, insurance and handling charges the net export price, at ex-factory level, has been determined. The details of the net export price so determined for Olympia Chemicals Ltd, Pakistan have been mentioned in the dumping margin table given below.

**All other exporters of Pakistan**

48. The Authority notes that no other exporter from Pakistan has submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has adopted the lowest representative net export price to India of the cooperative exporters for all other exporters as the net export price after making the due adjustments. The net export price so determined for the non-cooperative exporters from Pakistan has been mentioned in the dumping margin table given below.

**I. DUMPING MARGIN**

49. Comparing the aforesaid normal values and export prices as determined, the dumping margin determined for the subject countries during POI and Post POI are as follows, which indicates that dumping has continued even in the post-POI i.e. during the period subsequent to the period of investigation. However, the dumping margin during post- POI has come down in respect of all countries except USA where it has increased

**POI (2014-15)**

Country	Exporter/ Producer	Normal Value US\$/MT	Net Export Price US\$/MT	Dumping Margin US\$/MT	Dumping Margin %	Dumping Margin % Range
China PR	All	*****	*****	*****	*****	15-25
Ukraine	All	*****	*****	*****	*****	15-25
EU	All	*****	*****	*****	*****	5-15
Iran	All	*****	*****	*****	*****	5-15
USA	All	*****	*****	*****	*****	5-15
Kenya	All	*****	*****	*****	*****	10-20
Pakistan	Olympia Chemicals Limited, Pakistan	*****	*****	*****	*****	20-30
	Non-Co- operative producers/ exporters in Pakistan	*****	*****	*****	*****	30-40

**Post POI (April 2015 – Sep 2015)**

Country	Exporter/ Producer	Normal Value US\$/MT	Net Export Price US\$/MT	Dumping Margin US\$/MT	Dumping Margin %	Dumping Margin % Range
China PR	All	*****	*****	*****	*****	5-15
Ukraine	All	*****	*****	*****	*****	15-25
EU	All	*****	*****	*****	*****	0-10
Iran	All	*****	*****	*****	*****	0-10
USA	All	*****	*****	*****	*****	15-25
Kenya	All	*****	*****	*****	*****	0-10
Pakistan	Olympia Chemicals Limited, Pakistan	*****	*****	*****	*****	15-25
	Non-Co-operative producers/ exporters in Pakistan	*****	*****	*****	*****	20-30

## **J. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**

### **Submissions made by the Applicant and Other Interested Parties**

50. Following are the submissions made by the applicant and other interested parties in this regard:

- i. Import is occurring only because domestic producers are forcing it upon the users. Even the domestic producers, who use the subject goods in downstream production, use the imported products only. Therefore, the Anti-Dumping Duty may be recommended to be withdrawn with effect from the date on which such MTR has been initiated.
- ii. The domestic producers never disputed the fact that the capacity utilization could be achieved more than what has been achieved. It has not been disputed that Nirma along with earlier SCL made a claim before the BIFR that the plant of SCL was in the state of scrap.
- iii. 20% - 25% ROCE earned by the domestic producers has been arrived at from the Financial Records without applying the principles of Annexure III which requires to remove extra-ordinary expenses like expenses incurred during shutdown of the plant due to unavailability of the raw material.
- iv. Net Sales Realisation ( NSR) of the domestic producers for the price undercutting have been arrived at after adding freight. It has been done even though according to the practice of the designated authority Net Sales Realization is arrived at the ex-factory gate of the domestic producers.
- v. Gujarat Heavy Chemicals Limited ("GHCL") is a profit making company and that the related producers and exporters are not participating in the investigation as there is no dumping. The Domestic producers did not deny the fact that TATA Chemicals Limited ("TCL") is also a profit making company and earning huge profits on resale of the imported subject goods.
- vi. There are no price Suppression and Depression even after the inclusion of the non- functional plants of the domestic producers. Therefore it may be inferred that the domestic Industry is not suffering any injury.
- vii. Domestic Industry is not suffering any volume injury, price injury and that the plants are running at their best capacity utilizations. There is no need for continuation of Antidumping Duty on the import of subject goods from the subject countries.
- viii. The estimates of NIP, NSR and landed price show that there exists negative injury margin in the POI. Post POI also shows negative injury margin. Domestic Industry is not suffering any injury; there is no need for continuation of anti-dumping duty on the import of subject goods from the subject countries. There is no likelihood of continuation of injury as well to the domestic industry.
- ix. It is undisputed fact that the landed value increased significantly because of the increase in export price in USD. The domestic producers are not dependent on imported material and therefore unaffected by depreciation in INR against USD. Such change is of lasting nature and continued for more than 3 years now. Therefore, there is no remote possibility for recurrence of injury to the domestic producers.
- x. The production increased from 2,391,519 MT in base year to 2,405,410 MT in POI. The domestic producers have accepted during the public hearing that they are not suffering injury.
- xi. The total exports of domestic Industry have come down sharply from a figure of 2,00,354 MT in the year 2011-12 to 26,642 MT in the year 2014-15, which clearly falsifies the statement made by the Domestic producers that Domestic producers has to continue its exports to dispose of inventories.
- xii. The domestic sales of the product increased from a figure of 20,06,729 MT in 2011-12 to 22,18,766 MT in 2014-15. The total sales, however, very marginally decreased from 24,19,438 MT in 2011-12 to 24,03,783 MT due to sharp decline in Captive Consumption & Exports.
- xiii. The largest Indian domestic producer "Tata Chemicals Ltd." imported material from its subsidiary from Kenya and from unrelated producers from EU and China. The domestic producer claimed that the product imported from Kenya was of lower grade and fetches lower price than the domestic producers in India. The price at which the domestic producers sold subject goods to the users after import, should be compared with the Net sale realization and the NIP.
- xiv. The Domestic Producers achieved the optimal capacity utilization during the POI and injury period. The capacity indicated by them is only name plate capacity, the plants are worn out and they are not capable to achieve capacity utilization more than at which they are operating.
- xv. Even after several years of duty, Soda Ash industry did not increase the capacity to such levels so as to meet the entire Indian demand. The purpose of ADD is to eliminate the trade-distorting effects of injurious dumping and not to create a monopolistic situation for the domestic industries.

- xvi. The capacity of the domestic producers has not increased from the period of original investigation which is under review. Further the claims of Domestic Industry about the investments made in the plants for increasing the capacity is not substantiated with any evidence.
- xvii. As regard expansion plans, the domestic producers in ambiguous term are seeking protection to earn huge profits at the expense of the users. Here again the domestic producers made a false claim. The return of INR 1250 PMT is an average for the industry. It is not for the domestic producers who will expand capacities or the new entrant.
- xviii. There is no injury to the domestic producers for last two years from imports, examined with or without Anti-dumping Duty. It can thus be concluded that there is no need to continue Anti-Dumping Duty, which is an unnecessary burden on the users.
- xix. GHCL is operating at more than 87% during POI which is the maximum possible capacity utilization in these industries. GHCL is one of the major producers with capacity of 8,50,000 MT. It is earning good amount of profit also from the business. Even then it has its compulsions to import the subject goods from various countries including the subject countries. It may be noted that they are importing the goods after payment of Anti-Dumping Duty and then earning sufficient profit on resale of the same.
- xx. Domestic Industry is choosing the figures as it is suiting them. Such an approach cannot be accepted. Even though import was taking place, they kept on increasing prices. As may be seen from the correct data reported by the domestic industry vide their submission dated 02.03.2016, in 2013-14, cost of sales increased only to 111, but selling prices increased to 117. In 2014-15 when cost of sales witnessed a decline by 1 percentage points to 110, selling prices jumped by 10 percentage points compared to previous year.
- xxi. The change in the prices of the subject goods in the exporting country and international market along with sales realization of the domestic industry should be considered for examination of lasting nature as the changes in prices of the subject goods are reflected in the world market and increase in export price to India is not a standalone event.
- xxii. Annexure III under the AD Rules clearly says that freight outward which is a post manufacturing expense shall not be considered for the purpose of NIP. The DI is now trying to create an impression that their contention is not NIP determination but determination of injury margin, in effect both are the same as the injury margin is considered as the difference between landed price of imports and NIP at ex-factory levels.
- xxiii. The claim that the duties should be continued to protect an anticipated future investment which is not of any concrete nature has no tenability.
- xxiv. In cases where the injury margin itself is negative i.e., landed value is more than the NIP, no antidumping duty can be recommended by the Authority. Since no injury is caused to the domestic industry, anti-dumping duty should be withdrawn.
- xxv. Super profits being generated by the domestic industry is directly related to the fact that imports are at par with the NIP and this difference is being taken advantage of by the domestic industry. The customers are suffering due to artificially inflated price of soda ash required for their industries, which in turn would have a carry forward effect on various industrial and consumer items.
- xxvi. The increase in prices is on account of the exchange rate as well as increased prices in the international market. Domestic producers enjoy the benefits of devalued rupee in terms of the increased landed value, there is no effect on their costs due to the fact that domestic producers are using raw material which is abundantly available in India itself.
- xxvii. Import price is highest in Gujarat. The high price in the region where subject goods is available in sufficient quantity and low price where supply is not available also establishes that the decision to buy is not dependent on price preference.
- xxviii. There is no relation between import volume and prices. The domestic producers are earning huge profit irrespective of the import volume and prices. The users are ending up paying Anti-dumping Duty without any need of protection to the domestic producers.
- xxix. The price at which imported goods were resold were significantly higher than the landed value shown at the port of import resulting into a distorted Landed Value for the purposes of comparison of such Landed Value with the NIP and NSR.
- xxx. The foreign exchange rate changed where value of INR depreciated significantly against USD. The cumulative effect of such changes resulted into increase in import prices.

- xxxi. Just as domestic industry at the time of initiation of investigation has to only provide evidence regarding existence of dumping, injury and causal link and not actually determine injury margin and dumping margin, similarly in case of review, the applicants are only required to file an application giving positive evidence on changed circumstances.
- xxxii. The domestic producers have contended that the injury margin for non-cooperating exports should be determined on the basis of lowest prices reported in India. The Respondent denies the submissions as incorrect and submit that the Designated Authority should consider the Average weighted price for calculation of injury margin. In the present case exporters from the subject countries have participated in the investigation and even the Domestic producers have the related parties in the subject countries under the investigation. Therefore, the injury margin may be calculated on the basis of the data available with the Designated Authority and not at the lowest price reported in India.
- xxxiii. The domestic producers have contended that Authority may consider only those transactions, where the injury Margin which are positive. The Respondent denies the submissions of the Domestic Industry as incorrect. There is absolutely no basis for making such a request and there is no provision anywhere, which allows consideration of only positive injury margin.
- xxxiv. The Domestic Producers have contended that the Designated Authority requires to look into the future investments of Domestic Industry as well as the Authority should analyze if any material retardation is caused to the Domestic Industry. The Respondents denies the submissions as incorrect. The Respondent submits that the Domestic Producers are claiming that they have made future investments but are unable to establish that they had made any investments after the imposition of antidumping duty to improve their capacity, whereas the demand of the subject goods had increased.
- xxxv. DA is requested to also require the domestic producers to come clean regarding the imports made by them. It is necessary for them to clarify at what prices domestic producers import the subject goods. Further, since domestic producers have information of their net sales realizations, they must be aware whether imports made by them were above the net sales realization or not? Also, domestic producers must disclose the prices at which the imported goods were resold in the open market.
- xxxvi. Domestic producers have been predominantly selling their subject goods in Gujarat and region around Gujarat at a very good price. Admittedly, domestic producers are making huge profits. The price decline is stated to be high in West Bengal alone and the decline is not much in Gujarat and other parts of India.
- xxxvii. In present case there is no relation between import volume and prices and the Domestic Producers are earning huge profit irrespective of the import volume and prices. The users are ending up paying Anti-dumping Duty without any need of protection to the Domestic Producers.
- xxxviii. The Domestic producers have their subsidiary companies in the subject countries i.e. NIRMA has its subsidiary in USA and TATA has its subsidiary in Kenya and USA. Therefore the Domestic Industry should be able to provide the Normal Value of the exporter in the subject countries. Authority should calculate the normal value for China and Ukraine on the basis of price obtained from the subsidiary companies of the Domestic Producers in the Market economy country or the constructed value of market economy third country. The Authority should not consider the cost of Production of domestic Industry when other options are available with the Authority.
- xxxix. The largest Indian domestic producer “Tata Chemicals Ltd.” (Hereinafter referred as TATA) imported material from its subsidiary from Kenya and from unrelated producers from EU and China. The domestic producer claimed that the product imported from Kenya was of lower grade and fetches lower price than the Domestic Producers in India. Therefore, it is apparent if due to difference in quality an adjustment of 20% is made in price for comparison then imports become highly costlier, but users are buying it because they are not getting enough supplies. The price at which the Domestic Producers sold subject goods to the users after import, should be compared with the Net sale realization and the NIP.
- xl. DI contended that Freight charges needs to be included in the NIP calculation, the issue is *sub-judice* before the Delhi high court. Annexure III of the AD Rules clearly says that freight outward, which is a post manufacturing expense shall not be considered for the purpose of NIP.
- xli. There is no evidence to establish that injury is being suffered by the DI. Further imports and market share of imports from subject countries have declined therefore volume of imports from subject countries have become insignificant and incapable of having negative impact on the DI.

- xlii. Di's stand is that Authority should not allow any import at a price lower than the DI selling price. However, DI is arbitrarily fixing a very high selling price and trying to block the imports from all significant producers of soda ash overseas.
- xliii. Imports are not suppressing or depressing the price as the selling price of the DI has increased by 23% in the POI as compared to the base year while the cost of sales has increased by 6% only whereas post --POI selling price of the DI increased but the cost of sales has decreased.
- xliv. The performance of DI has improved in respect to all economic parameters . Production and sales have increased , capacity utilization has remained above 80%, inventories have decreased, profits have increased including cash profits and ROI and even the employment have increased marginally,
- xlvi. There is massive increase in profitability and NSR with no effect of price suppression and depression. Except the export performance l DI has overall performed very well.
- xlvi. Price undercutting is relevant only in case where there is price suppression or depression caused by the imports. But in present case there is no price suppression or depression and so it has no relevance in the present case,
- xlvi. During the POI DI has sold its goods at par with the landed price of imports even then DI have earned a ROI which is more than 22%. So, withdrawal of duty will not change the situation,
- xlvi. Capacity expansion by the DI is vague without the date of commencement of such capacity addition. Further the DI should get ROI of Rs. 8839/- Per MT to make any investment viable.

#### **SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY**

51. The domestic industry has submitted as under:-

- i. Mere improvement in performance of the domestic industry is insufficient ground for revocation of antidumping duty. Rule 23(1A) mandates the Authority to examine the effect of the revocation of duty on domestic industry, instead of merely focusing on the present situation of domestic industry.
- ii. The meaning of lasting nature is that the changes in circumstances are such that they would not reverse back to what it was earlier. The decline in import price clearly establishes that the changes were not of lasting nature and were purely temporary in nature.
- iii. Injury margin in case of non-cooperation of exporters should be determined on the basis of lowest price reported in India. Further, Authority must consider only injurious imports and ignore those imports which are above NIP. Negative injury margin does not mean withdrawal of antidumping duty.
- iv. The Authority is required to first examine whether the domestic industry has suffered material injury. If the authority comes to a conclusion that the domestic industry has not suffered material injury, the Authority needs to examine whether the domestic industry is threatened with material injury in the event of premature withdrawal of anti dumping duty. If not so, the Authority must examine whether continued dumping of the product under consideration is likely to materially retarded establishment of the domestic industry in the Country.
- v. As regards the claim that net selling price of domestic industry is above Rs. 19000 PMT, indexed figures show that the selling price is way below the net sales realization stated by the interested parties at the time of hearing.
- vi. As regards the issue of Capital employed based on books of accounts, the prescribed format is relevant only for determining continuation of injury and not potential injury and likelihood of injury. For likelihood of injury, potential situation is required to be seen.
- vii. As regards applicability of *res judicata* principle on issue of freight inclusion is concerned, the principle is applicable only when final judgment is made on issue. The issue as raised before the DA in original investigation is pending as an appeal before the Hon'ble Tribunal, therefore remains alive and valid presently.
- viii. As regards the contention that Domestic industry while arguing about freight is talking about injury margin on the surface when it actually means determination of NIP, is faulty as the two are different terms.
- ix. The reliance on Brazilian practices related to lesser duty rule is appropriate since in the absence of guidelines on determination of injury margin, the practice and principles keep on developing. The incidence of freight is important for certain selective products and therefore has not been agitated heavily in the past.
- x. As regards several years of duty is concerned the antidumping duties were levied in 2012. The industry was incurring losses in 2011-12 and was making low level of profits and ROI till 2013-14. After imposition of duties, the situation of domestic industry gradually improved and market viability increased consequently resulting in planning of expansions.
- xi. The future investments are of a concrete nature and cannot be withdrawn. The reliance on EC case on imports of pure silk typewriter ribbon fabrics from China is misplaced as the facts are different.



- xii. As regards high profitability of domestic industry, it is seen that soda ash is a highly capital intensive, low raw material cost and high finished product freight industry. The freight costs constitute very high percentage of cost of production. Therefore this case should be seen in the light of peculiarities of the product under consideration.
- xiii. Export price in India has significantly declined in the post POI.
- xiv. As regards issue of devaluation of rupee and exchange rate is concerned, the devaluation of rupee has also impacted domestic producers as they have to import various raw materials like Limestone, Coal, Coke etc. While exchange rate has changed the imports occurring at present are materially below the NIP of domestic industry even considering the imports in terms of Indian rupee
- xv. Decline in captive consumption is because one domestic producer could not produce downstream product due to stiff competition. The decline has not adversely affected the overall consumption and is not a cause of injury to the domestic industry. Overall consumption of detergent has increased and thus there is no decline in consumption of Soda Ash for production of detergent.
- xvi. There is no evidence or basis for the claim that comparison of landed value with NIP and NSR with the price of resold imported goods, which were higher than the landed value shown at the port of import.
- xvii. As regards ROCE, the plants being operated by industry are depreciated yielding very low returns. Since net fixed assets don't represent true value the domestic producers have considered present value of investment for calculating ROCE.
- xviii. The valuation of inventory in financial accounting cannot be considered for present purposes. That wouldn't be in conformity with the specific rules of NIP which must be considered herein.
- xix. The import price in Gujarat is comparable. The price in North is comparatively higher and share of imports in Gujarat is less than 5% of total imports.
- xx. As regards the argument that the landed value simply cannot be used for comparison with NIP or NSR to assess injury margin or injury, it is submitted that majority of the imports from Kenya are directly by the consumers.
- xxi. As regards the profit margin being considered unreasonable, it is submitted that any business making investment would legitimately expect such a return.
- xxii. As regards the allegation of adjustment of 20% in price, the domestic industry claims no such adjustment.
- xxiii. There is no evidence to support the possibilities that there may be grades that are not substitutable.
- xxiv. As regards the argument that domestic producers are unable to supply in some areas and therefore imports should not be charged with antidumping duties, the domestic industry holds that for this reason freight should be added while determining injury margin.
- xxv. As regards the domestic industry's proximity to raw material availability is concerned, such proximity has lowered cost in favour of consumer interests. The freight cost incurred on raw materials is being considered as a part of cost of production and NIP, which is being borne by the consumers.
- xxvi. The domestic producers have serious intentions of making investments. Even at present rate of profit the fresh investments will be recovered in 32 years. Further the weighted average quantum of anti dumping duties during the POI was Rs.1,290 PMT considering that exports have been made by exporters named in the duty table. Thus, if the domestic industry were to reduce its price by the quantum of anti dumping duty, the fresh investment now being made shall be recovered in 34 years . Thus, possible withdrawal of anti dumping duty shall imply serious reconsideration on these investments.
- xxvii. The price reported by IHS Chemical Global Soda Ash is a good indicator of the prevailing prices of subject goods in the domestic markets in various countries/regions. Further, since the journal mentions high and low prices, domestic producers have adopted average price.
- xxviii. The increase in landed price of imports was 32% and not 56% as claimed by the interested parties.
- xxix. The price increased by the domestic industry was 27% as against 65% claimed by the interested parties. This is due to check on dumping of the product in the country.
- xxx. Profitability of domestic industry is far adverse in Southern and Eastern regions due to import competition.
- xxxi. The overall demand has increased over the injury period. Imports have increased over the injury period despite antidumping duty in force.
- xxxii. Imports have also increased in relation to production
- xxxiii. Price would be significantly positive in the event of revocation of anti dumping duty.
- xxxiv. Indian producers of soda ash are located in the State of Gujarat due to availability of raw material. Due to substantial transportation costs the selling price of the domestic industry should be compared with the landed

price of imports only after adding transportation costs.

- xxxv. Authority should determine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India. Premature withdrawal of duties is likely to lead to significant price undercutting in the market.
- xxxvi. There are no current price suppression or depression effects with the antidumping duties in force. However, if the duties are withdrawn the dumping would cause significant depressing effect on the prices of the domestic industry in the market.
- xxxvii. Performance of the domestic industry in terms of production, and capacity utilization, profits, return on investments, cash flow has started improving with imposition of antidumping duty. The withdrawal of duties will lead to recurrence of material injury.
- xxxviii. The causal link has already been established in the original investigation. The dumped imports from subject countries have increased despite antidumping duties in force.
- xxxix. Subject imports are available at prices lower than domestic prices. The excess capacities of producers in subject countries show likelihood of increase in volume of dumped imports in case of revocation of duties.
  - xl. Price undercutting leads to consumers preferring imported material resulting in domestic industry losing sales. This leads to increase in inventories leading to decline in production and further decline in capacity utilization.
  - xli. As regards price effect the price undercutting will lead to a situation where the domestic industry is prevented from effecting price increases, which leads to decline in profitability. This decline leads to decline in gross profit earned leading to decline in cash profits resulting in further decline in the return on capital employed.
  - xl.ii. The raw material utilization and utilities utilization should not be considered at the best achieved levels in the past because the cause of increase in consumption is not inefficient utilization of such inputs but changes in input physical circumstances.
  - xl.iii. The captive inputs should be considered at market price. Actual raw materials and utilities consumption should be considered. Actual cost of production should be determined instead of a notional lower cost of production in order to determine a price which can be compared with the import price in order to assess injury margin.
  - xliv. A comparison of non injurious price of the domestic industry with landed price of imports without including associated freight will not constitute a fair comparison and would lead to gross under estimation of the injury suffered by the industry.
  - xl. v. Freight cost forms a part of cost of production. The domestic industry incurs the freight cost for shifting the goods from factory to depots/warehouses which are extended factory gates. Title of goods remains with the producers and gets transferred to the purchasers only on clearance of the material from warehouses.
  - xlvi. Since the customs duty is added before comparing with non-injurious price even if not paid, the inland freight being incurred in the domestic product must also be added. This was followed in the matter of white cement and should be followed in the present investigation as well.
  - xl. vii. Non-consideration of factors such as freight cost incurred by domestic industry, significant difference in payment terms offered by foreign producers/ exporters and Indian industry leading to imports, disparities in taxes & duties between domestic and imported product, existence of present NIP law and interpretations drawn therefrom, absence of codified practice on key elements despite existence of NIP law are some of the examples which are individually and collectively impacting the quantum of anti-dumping duties by reducing the protection level that the domestic industry should be entitled under anti-dumping law.
  - xl. viii. Volume of the exports from subject countries to India during the POI and post POI shows a massive growth in exports and also at dumped prices. In the event of premature withdrawal of the anti-dumping duties, dumping shall not only continue but also intensify
  - xl. ix. There exists significant level of past and current dumping which has not been disputed by the exporters.
    - l. Heavy discounts are being given by the domestic industry on the list prices. Therefore, selling price (after discounts) are materially below the price lists
    - li. The plants being operated by industry are depreciated. NFA don't represent true value of the domestic producers' assets value. The Authority should consider present value of investment for calculating ROCE. Capital employed by domestic industry at net book value is not appropriate figure for determining return on capital employed. Present capital employed is against capacity of 29,94,435 MT; whereas 4,025 Crores is being invested for enhancing capacities by 8 Lac MT. This itself clearly shows that the present capital employed is grossly insufficient to determine return required by the industry.
    - lii. Price undercutting is significantly positive in the event of revocation of anti-dumping duty. Transportation cost forms a very substantial portion of the cost of production and the incidence of which is substantial. Thus selling

price should be compared with the landed price of imports only after adding the transportation costs. The rule does not provide how undercutting needs to be determined, therefore there is no bar in considering application of principles of fair comparison for determination of price undercutting.

- liii. India's position before the WTO is also that the comparison of the imported product price be made with the domestic industry price as close as possible to the point of consumption. It would be discrimination against the domestic industry in case the same is not applied by its own Authority
- liv. Authority has in past have adopted different methodologies such as Product type wise (PCN wise) determination of price undercutting, Month wise or quarterly determination of price undercutting, adjustment of post sales expenses - warrantees, guarantees, mandatory spare parts, Indian office expenses, which shows recognition and acceptance of the principles of fair comparison by the Directorate
- lv. The purpose of determining price undercutting is to determine the effect of the dumped imports. These prices can only mean delivered prices at the consumers place, as this is the only place whether the dumped imports affect the domestic industry.
- lvi. The issue of freight is being contended by the domestic industry in the context of price undercutting and injury margin, whereas it is being considered by the Directorate in the context of determination of NIP. The issue has been diverted to NIP determination by interested parties in order to protect their malafide interests
- lvii. In the matter of white cement, the authority had allowed freight cost for determination of price undercutting and injury margin at the stage of original investigation as well as first sunset review. However, the authority was misled into believing that the freight cost is an issue of NIP determination and since India has introduced NIP law by them, the freight cost could not be permitted for determination of injury margin

#### **EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

- 52. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of the interested parties on injury.
- 53. As regards the contention of the domestic industry for consideration of freight incurred by domestic industry as a factor in injury analysis, the Authority notes that first of all Annexure III of the Anti-dumping Rules does not permit such a practice. Moreover, the final finding of the Authority in the anti-dumping investigation concerning imports of White Cement, involving the freight issue is sub-judice before CESTAT. Similar cases are also pending before the Delhi High Court.
- 54. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.

#### **K. Cumulative assessment**

- 55. Attention is invited to Annexure II para (iii) of the Anti-dumping Rules which provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that: -
  - a. the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three per cent of the import of like article or where the export of individual countries is less than three per cent, the imports collectively accounts for more than seven per cent of the import of like article and
  - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
- 56. In this regard the Authority observes that:
  - i. the margins of dumping from each of the subject countries are more than the limits prescribed above;
  - ii. the volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed;
  - iii. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market. This is evident from the following:
    - a. The subject goods supplied from various subject countries and by the domestic industry are like articles.
    - b. There are common parties who are resorting to use of imported material from various sources and domestic material. Imported and domestic materials are, therefore, being used interchangeably and there is direct competition between the domestic product & imported

product.

- c. The exporters from the subject countries and domestic industry have sold the same product in the same periods to the same set of customers. The sales channels are comparable.
- d. Volume of imports from each of the subject countries is significant.
- e. Consumers make purchase decision on the basis of prices offered by various suppliers.

57. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from China PR, EU, Kenya, Iran, Pakistan, USA and Ukraine on the domestic industry in the light of conditions of competition between imported product and like domestic product. The Authority notes that the margin of dumping and quantum of imports from subject countries are more than the limits prescribed above.

58. The Authority has taken note of submissions made by the interested parties. Annexure II of the Anti-dumping Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products. While examining the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to price effect of dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increase which would have otherwise occurred to a significant degree.

59. As regards the impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of Anti-dumping Rules states as follows:

*“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”*

60. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such further indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

61. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments of the interested parties. For analyzing the injury parameters, all relevant documents including the balance sheet of the Domestic Industry have been examined and verified by the Authority. The issues relating to the interest of the Indian industry and other issues have also been dealt by the Authority under appropriate headings.

#### **Demand and market share**

62. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of the domestic industry and other Indian producers have been added to the total imports into India and the same has been summarized below:

Particulars	UOM	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI ( 2014-15)	Annualised Post POI
Sales of Domestic Industry	MT	14,31,825	15,19,990	15,78,148	16,01,302	16,45,357
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>110</i>	<i>112</i>	<i>115</i>
Sales of Other Indian producers	MT	7,51,493	7,26,475	7,37,588	7,55,169	7,59,164
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>98</i>	<i>100</i>	<i>101</i>
Total Domestic Sales+Captive Transfer	MT	21,83,318	22,46,466	23,15,737	23,56,471	24,04,521
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>106</i>	<i>108</i>	<i>110</i>

Particulars	UOM	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI ( 2014-15)	Annualised Post POI
Imports- Subject Countries	MT	3,29,828	5,53,416	4,89,270	6,73,706	6,94,779
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>168</i>	<i>148</i>	<i>204</i>	<i>211</i>
Imports- Other Countries attracting duties	MT	1,10,695	1,19,014	62,103	49,071	38,611
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>56</i>	<i>44</i>	<i>35</i>
Imports- Other Countries	MT	3,952	19,799	16,214	1,201	2,246
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>501</i>	<i>410</i>	<i>30</i>	<i>57</i>
Total Demand(With captive transfer)	MT	26,27,793	29,38,694	28,83,324	30,80,449	31,40,157
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>112</i>	<i>110</i>	<i>117</i>	<i>119</i>
Domestic Industry	%	54.49	51.72	54.73	51.98	52.40
Other Indian Producers	%	28.60	24.72	25.58	24.51	24.18
Indian Producers as a whole	%	83.09	76.44	80.31	76.50	76.57
Subject Countries	%	12.55	18.83	16.97	21.87	22.13
Other Countries attracting duties	%	4.21	4.05	2.15	1.59	1.23
Other Countries	%	0.15	0.67	0.56	0.04	0.07
Demand	%	12.55	18.83	16.97	21.87	22.13
Indian production	%	14.00	23.44	20.95	27.87	28.10

Note : Post-POI : ( April 15-Sept 15)

63. The Authority notes that demand has increased during the POI as compared to the base year. The growth in demand during the POI over base year was 17%. The demand has shown increasing trend during the post POI ( April 15-Sept 15) as well.

#### **L. Volume Effects of Dumped Imports**

##### **Import Volume and Market Share**

64. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCIS. The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analysed as under:

Particulars	UOM	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI ( 2014-15)	Post POI ( April 15-Sept 15)	Annualised Post POI
<b>Import Volume</b>							
<b>China</b>	MT	3,307	1,18,277	98,735	1,25,589	37,105	74,210
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>3,576</i>	<i>2,986</i>	<i>3,798</i>	<i>1,122</i>	<i>2,244</i>
<b>EU</b>	MT	98,968	1,86,264	1,89,139	2,43,032	1,16,264	2,32,528
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>188</i>	<i>191</i>	<i>246</i>	<i>117</i>	<i>235</i>

Particulars	UOM	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI ( 2014-15)	Post POI ( April 15-Sept 15)	Annualised Post POI
<b>Kenya</b>	MT	1,58,255	1,43,093	1,62,244	1,31,656	60,524	1,21,047
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	90	103	83	38	76
<b>Pakistan</b>	MT	24,108	19,989	16,948	37,447	19,520	39,040
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	83	70	155	81	162
<b>Iran</b>	MT	5,276	9,040	-	5,427	7,742	15,483
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	171	-	103	147	293
<b>Ukraine</b>	MT	39,913	12,305	196	43,276	27,083	54,165
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	31	0	108	68	136
<b>USA</b>	MT	-	64,447	22,009	87,279	79,153	1,58,306
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	-	100	34	135	123	246
<b>Subject Countries</b>	MT	3,29,828	5,53,416	4,89,270	6,73,706	3,47,389	6,94,779
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	168	148	204	105	211
Other Countries attracting duties	MT	1,10,695	1,19,014	62,103	49,071	19,305	38,611
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	108	56	44	17	35
Other Countries	MT	3,952	19,799	16,214	1,201	1,123	2,246
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	501	410	30	28	57
Total Imports	MT	4,44,475	6,92,228	5,67,587	7,23,978	3,67,818	7,35,636
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	156	128	163	83	166
<b>Market Share</b>							
China	%	0.74	17.09	17.40	17.35	10.09	10.09
EU	%	22.27	26.91	33.32	33.57	31.61	31.61
Kenya	%	35.60	20.67	28.58	18.19	16.45	16.45
Pakistan	%	5.42	2.89	2.99	5.17	5.31	5.31
Iran	%	1.19	1.31	-	0.75	2.10	2.10
Ukraine	%	8.98	1.78	0.03	5.98	7.36	7.36
USA	%	0.00	9.31	3.88	12.06	21.52	21.52
Subject Countries	%	74.21	79.95	86.20	93.06	94.45	94.45
Other Countries attracting duties	%	24.90	17.19	10.94	6.78	5.25	5.25
Other Countries	%	0.89	2.86	2.86	0.17	0.31	0.31
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

65. The Authority notes that though there is overall increase in imports from subject countries during the POI as compared to the base year of the injury period, a deeper analysis reveals that out of three major producer subject countries ( China, USA and EU two countries namely, China and EU are showing declining trend in imports in

the post-POI . Even on overall basis , (i.e. all subject countries taken together) the increase in imports during the post POI is only miniscule 3%

#### **M. Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry**

66. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

#### **Price suppression and depression effects of the dumped imports:**

67. The price suppression and price depression effect of the dumped imports has also been examined with reference to the cost of production, net sales realization and the landed values of the subject goods from the subject countries in relation to injury period including POI and Post POI.

Particulars	UOM	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI	Post POI
Landed price of Subject Imports	Rs./MT	12,939	15,135	15,203	16,820	17,482
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>117</i>	<i>117</i>	<i>130</i>	<i>135</i>
Cost of Sales	Rs./MT	****	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>110</i>	<i>106</i>	<i>102</i>
Selling Price	Rs./MT	****	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>113</i>	<i>123</i>	<i>125</i>

68. The Authority notes that selling price has increased consistently year on year establishing the clear absence of price depression effect on the domestic selling price. There is also no clear trend in so far as price suppression effect on account of dumped import is concerned. While the increase in sales price in 2012-13 has not been in proportion to the rise in landed value of imports it has registered higher comparative growth in the subsequent year.

#### **Price Undercutting**

69. While working out the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been deducted. The landed value of imports has been calculated by adding 1% landing charge and applicable basic customs duty and education cess to the CIF prices from the subject countries, as reported by each responding exporter. For others category, landed price has been computed by adding applicable basic customs duty and education cess to the Assessable value as per DGCI&S data. The domestic industry contended that freight should be included for determination of price undercutting. The Authority however notes that the product under consideration was determined at the time of original investigation after excluding freight from the selling price and the present review is only a mid-term review of existing ADD. The Authority has therefore continued to determine price undercutting by considering domestic industry selling price at ex-factory levels.

Particulars	Unit	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI	Post POI
<b>China</b>						
Landed price of imports	Rs./MT	14,048	14,985	14,126	17,174	16,990
Net Sales Realisation	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	%	****	****	****	****	****
Price Undercutting	% Range	0-5	5-10	10-15	5-10	5-10
<b>EU</b>						
Landed price of imports	Rs./MT	12,660	15,716	16,148	17,229	18,606
Net Sales Realisation	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	%	****	****	****	****	****
Price Undercutting	% Range	10-15	0-5	0-5	0-5	Negative
<b>Kenya</b>						
Landed price of imports	Rs./MT	12,714	15,222	14,805	15,618	16,969
Net Sales Realisation	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	%	****	****	****	****	****
Price Undercutting	% Range	10-15	0-5	10-15	10-15	5-10
<b>Pakistan</b>						
Landed price of imports	Rs./MT	14,384	17,288	18,023	19,033	19,958
Net Sales Realisation	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	%	****	****	****	****	****
Price Undercutting	% Range	0-5	Negative	Negative	Negative	Negative
<b>Iran</b>						
Landed price of imports	Rs./MT	14,150	14,317	-	16,598	16,517
Net Sales Realisation	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	%	****	****	****	****	****
Price Undercutting	% Range	0-5	10-15		5-10	10-15
<b>Ukraine</b>						
Landed price of imports	Rs./MT	13,400	16,741	17,473	17,086	17,524
Net Sales Realisation	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	%	****	****	****	****	****



Particulars	Unit	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI	Post POI
Price Undercutting	% Range	5-10	Negative	Negative	5-10	0-5
<b>USA</b>						
Landed price of imports	Rs./MT	11,265	12,682	12,660	15,915	15,922
Net Sales Realisation	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	%	****	****	****	****	****
Price Undercutting	% Range	20-25	20-25	20-25	10-15	10-15
<b>Subject countries as a whole</b>						
Landed price of imports	Rs./MT	12,939	15,135	15,203	16,820	17,482
Net Sales Realisation	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	%	****	****	****	****	****
Price Undercutting	% Range	10-15	5-10	5-10	5-10	0-5

70. The Authority notes that while price undercutting is positive throughout including in POI and post-POI a closer look indicates that price undercutting for China and USA has actually declined during POI as compared to the previous year and for EU, Kenya , Pakistan and Ukraine declined during post-POI as compared to POI

**N. Examination of other Economic Parameters of Domestic Industry**  
**Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization**

71. The Production, Capacity and Capacity Utilization details are as follows:

Particulars	UOM	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI	Annualised Post POI
Installed capacity	MT	19,61,000	19,61,000	19,61,000	19,61,000	20,31,000
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>104</i>
Production	MT	15,78,674	16,11,377	16,02,002	16,45,154	16,96,272
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>101</i>	<i>104</i>	<i>108</i>
Capacity Utilization	%	80.50%	82.17%	81.69%	83.89%	83.52%
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>101</i>	<i>104</i>	<i>104</i>
Domestic Sales	MT	12,67,561	13,86,286	14,66,643	15,03,224	15,36,499
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>109</i>	<i>116</i>	<i>119</i>	<i>122</i>
Demand	MT	26,27,793	29,38,694	28,83,324	30,80,449	31,40,157
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>112</i>	<i>110</i>	<i>117</i>	<i>119</i>

72. From the above information, the Authority notes that the capacity of production of the domestic industry has remained constant during the injury period including the POI. However, both sales and capacity utilization have increased during the POI as compared to the base year in line with increase in demand.

**Inventories:**

73. Data relating to inventories shows as follows:

Particulars	UOM	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI	Post POI
Opening	MT	****	****	****	****	****
Closing	MT	****	****	****	****	****
Average	MT	****	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>101</i>	<i>73</i>	<i>122</i>

It is noted that average inventories has more or less remained constant prior to POI, then witnessed decline during POI and then increase during the post-POI period.

**Profits and actual and potential effects on the cash flow**

74. With regard to Profit/Loss and cash flow, it is noted that the profitability of domestic industry in terms of profit before tax and interest and cash profit has remarkably increased in the POI as compared to base year. The position has further improved during the post POI. The return on investment has also witnessed significant growth and has improved further in the post POI. The domestic industry contended that the Authority should take into account that (a) the present assets are significantly depreciated and net fixed assets values are not representative and (b) the domestic industry has added capacity incurring significant investment. The Authority has however determined profit, cash profit and ROI on the basis of its consistent practice. In any case, the Authority notes that the future investments are not relevant to determine past injury and return on investment.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI	Annualised Post POI
Cost of Sales	Rs/MT	****	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>110</i>	<i>106</i>	<i>102</i>
Selling Price	Rs/MT	****	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>113</i>	<i>123</i>	<i>125</i>
Profit/Loss	Rs/MT	****	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>176</i>	<i>146</i>	<i>293</i>	<i>356</i>
Profit/Loss	Rs.Lacs	****	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>193</i>	<i>169</i>	<i>347</i>	<i>432</i>
PBIT	Rs.Lacs	****	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>146</i>	<i>133</i>	<i>215</i>	<i>256</i>
Cash Profit	Rs.Lacs	****	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>168</i>	<i>153</i>	<i>270</i>	<i>342</i>
Return of investment	%	****	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>141</i>	<i>140</i>	<i>233</i>	<i>279</i>

**Employment, wages and productivity**

75. The data relating to employment, wages and productivity show as follows:

Particulars	UOM	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI	Annualised Post POI
Productivity per employee	MT	****	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>98</i>	<i>99</i>	<i>102</i>	<i>105</i>
Employment	Nos.	****	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>103</i>	<i>102</i>	<i>102</i>
Wages	Rs. Lacs	****	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>113</i>	<i>113</i>	<i>117</i>	<i>133</i>

76. It is noted by the Authority that though the increase in the number of employees during POI has been very marginal as compared to the base year yet there has been constant rising trend in respect of wages and employee productivity since 2012-13

**O. Magnitude of dumping**

77. It is observed from the section pertaining to Dumping Margin above that dumping margins in respect of the imports of the subject goods from the subject countries are positive and substantial during the POI and have remained positive even during post POI . However, the dumping margin during post- POI has come down in respect of all countries except USA where it has increased

**Growth**

78. The Authority notes that the growth of the domestic industry was positive during POI as well post POI in respect of selling price, profitability and return on investment. Growth in these parameters during post POI weakens domestic industry's argument of likelihood of injury

**Ability to raise funds**

79. It is noted that the domestic industry has not enhanced its capacity of production of the subject goods from the base year to POI. However, the domestic industry has been incurring significant capital investment at present and has planned a gross investment of Rs. 1025 crores in enhancing capacities. This signifies that their ability to raise capital investment has not been affected adversely.

**P. Conclusion on material injury**

80. The Authority notes that during injury period, while the capacity of production has remained constant throughout the injury period, the performance of the domestic industry has improved in terms of production, sales volumes, profit, cash profit, return on capital employed and inventory. The market share has declined during the POI as compared to the base year. During the post POI, the economic parameters has shown continued improvement including increased trend in the market share. Thus, the Authority notes that the economic parameters of the domestic industry do not exhibit any injury suffered by them. Even the domestic industry has admitted that it was not suffering injury during the present period.

**Q. Other Known Factors & Causal Link**

81. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting and price suppression and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry, as follows:-

**(a) Volume and prices of imports from third countries**

The Authority notes that during POI, imports of the subject goods from countries other than the subject countries and countries attracting anti-dumping duty have remained very minimal in volume.

**(b) Contraction of demand and changes in the pattern of consumption.**

The Authority notes that there is no contraction in the demand during the POI. On the contrary, overall demand for subject goods has shown improvement during the POI as well as post POI.

**(c) Developments in technology:**

The Authority notes that none of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.

**(d) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

The Authority notes that the subject goods are freely importable. The domestic industry is the major producer of the subject goods and account for significant domestic production and sales. Further there is no perceptible competition among the domestic producers, except that is obvious of a market economy.

**(e) Export performance of the domestic industry:**

The table below summarizes the performance of the domestic industry in respect of exports made by them.

Particulars	UOM	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI	Annualised Post POI
Exports	MT	*****	*****	*****	*****	*****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>28</i>	<i>34</i>	<i>14</i>	<i>8</i>

82. The Authority notes that the exports by the domestic industry have declined drastically during the POI as compared to the base year. The domestic industry contended at the time of original investigation that they were forced to export the product in view of dumping of the product in the Country, as recorded by the Authority under para 146 of the final findings of the original investigations. With the imposition of ADD, the domestic industry was able to increase domestic sales and reduce /lower exports.

83. From the above analysis, the Authority notes that neither the listed known parameters nor the other factors analyzed above show any continued injury to the domestic industry either during POI or post POI. The economic health of the domestic industry has improved

**R. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY**

84. However, in a review investigation, the Authority has to determine as to whether the subject goods are continuing to enter or likely to enter the Indian market at dumped prices and whether injury to the domestic industry is likely to recur due to these dumped imports if the duty is removed or varied. The Authority examined the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Indian Anti-Dumping Rules, which states as under:

*“A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter alia, such factors as;*

*a. a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.*

*b. Sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.*

*c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely to increase demand for further imports and,*

*d. Inventories of the article being investigated.”*

**Submissions made by the Applicant and other interested parties**

85. Following submissions have been made by the applicant and other interested parties:

- i. The circumstances in which the AD duty was imposed on the exporter have undergone substantial changes of very lasting nature and the situation warrants withdrawal of existing AD duties since the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur if the present duties are removed or varied.
- ii. The understanding of the domestic producers that the duty cannot be withdrawn unless the dumping ceased or that there was no likelihood of recurrence of dumping, is incorrect. It is legally required to withdraw duty if injury or likelihood of injury to the Domestic Industry is absent.
- iii. The domestic industry has not conclusively refuted the submission based on evidences that injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied which shows there is no likelihood also.
- iv. There is no evidence to show that exporters in subject countries are having sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase incapacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased exports to Indian markets.
- v. In the present case, crucial parameters such as landed price of imports, non-injurious price and injury margin have undergone significant changes. The above facts itself constituted sufficient ground for initiation of investigation and further establishes that injury to the domestic industry is not likely to continue or recur in the event of revocation of existing AD duties.
- vi. The domestic producers may be treated as non-cooperating and duty may be withdrawn immediately with effect from the date of commencement of POI. Domestic producers are not affected by volume and value of imports; therefore, there is no possibility of injury or any recurrence of injury if the Anti-dumping Duty is withdrawn. The fact that the major domestic producer is also importing the subject goods also supports the conclusion that there is no requirement for continued imposition of Anti-dumping Duty.
- vii. Olympia Chemicals Ltd. is having the lowest duty across subject countries in the present investigation. Even after this position if the exporter did not increase its volumes to India and have been increasing prices consistently then it clearly shows the change in circumstance of a lasting nature and there is not any situation to say that the exporter will export more on removal of duty. There is no current or potential export from Olympia which can cause any injury to the domestic industry. There is no likelihood of continuation or recurrence of dumping in case of withdrawal of duty concerning Olympia.
- viii. Olympia Chemicals Ltd. is running at a utilization of 90% to 100% level which is above optimal level.. Further, export volumes have declined but the export prices have increased significantly. So, they are not under any volume pressure to dispose off the material at any cheaper rate nor it has any imminent fresh additional available volume.
- ix. The export price of Olympia at landed levels in India was increasing consistently and has been higher than the NIP of the DI leading to negative injury margin which rules out any significant depressing or suppressing effect on domestic prices. The company isn't having any significant inventory levels also. The position of exports from Olympia have changed significantly and the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur if the present duties on Olympia are removed or varied, thus, the Authority may recommend for the withdrawal of the same.
- x. The change in the prices of the subject goods in the exporting country and international market along with sales realization of the domestic industry should be considered for examination of lasting nature as the changes in prices of the subject goods as are reflected in the world market and increase in export price to India is not a standalone event.

- xi. Further if the duties are removed exporters are going to increase the prices further due to demand supply gap present in India. DI is not able to meet the Indian demand including captive even after several years of duty imposition and having around 80% capacity utilization in the entire injury period.
- xii. Authority is required to examine surplus capacity and inventories with respect to the exporters in order to comply with requirement of Annexure II. In *Rishiroop Polymer Pvt. Ltd. Vs. DA* it has been held that the inquiry has to be limited to the information received with respect to change in the various parameters. Therefore, Authority can note insufficient or no information with respect to any aspect of investigation.
- xiii. Further, there is a decline in the overseas capacity such as Soda Ash producing facilities in China using hou process, due to which China has become “importer” of Soda Ash, Tata Chemical Magadi-Kenya has closed one of its plants with 5 lakh tonnes capacity, Solvay has shut down two of its plants in Europe. GHCL has closed its plant in Romania.
- xiv. Soda Ash consumption globally has been increasing @ 2-2.25% per annum and global production is 55 million MT. So, whatever is produced is consumed which leads to a further requirement of 1.25-1.50 million MT extra soda ash annually to meet the demand.
- xv. Purpose of ADD is to eliminate the trade distorting effect of injurious dumping and not to continue the duty to protect the expected capacity additions.
- xvi. A case of threat of material injury and likelihood of injury are clearly different phenomenon in the AD agreement and they cannot be put together under the same basket. Rules does not talk about Principles of para (vii) of Annexure II in the context of the Review. The authority should not make it mandatory to adopt the said principles in the present case.

#### **Submissions made by the Domestic Industry**

86. Following submissions have been made by Domestic industry

- i. Petitioner is obliged to provide information on likelihood and has failed to supply the authority with even prima facie evidence in this regard. There must be evidence pertaining to relevant parameters while seeking initiation of investigation.
- ii. As regards capacity expansion by domestic industry, the Designated Authority may kindly examine whether withdrawal of antidumping duty is likely to cause injury to the domestic industry both in respect of capacities which are already installed and operational capacities that have not been installed so far but shall become operational in near future.
- iii. The dumping margin determined in previous investigations and present investigation is significant. Significant positive dumping margins itself warrants continuation of antidumping duty.
- iv. Parameters laid down for examining threat of material injury in fact shows that there is likelihood of injury to the domestic industry in the event of premature withdrawal of ADD.
- v. The injury margin was found negative in the review investigation period for the cases on Polypropylene from Singapore, Coumarin from China PR, Zinc Oxide from China PR, ‘Front Axle Beam’ and ‘Steering Knuckles’ from China PR, Chloroquine phosphate from China PR, Diclofenac Sodium from China PR, Acetone from European Union, South Africa, Singapore and USA. However, duties were extended in these cases.
- vi. Reference is invited to Acetone and Phenol review cases wherein Negative IM in POI for India and Positive IM for third countries in Period of Investigation were determined and thus duties were extended
- vii. Reference has been made to Polypropylene review case wherein Negative IM in POI for India & third countries, Negative IM in post-POI for India and Positive IM in third countries in post Period of Investigation, were determined and thus duties were extended
- viii. Reference has been made to Ductile iron pipes, Caustic Soda from Taiwan, Potassium carbonate from Korea review cases wherein Negative IM in POI for India & third countries, Negative IM in post-POI for India and third countries were determined and the volume of injurious exports to India or third countries were found to be significant and thus duties were extended
- ix. Reference has been made to Persulphates, Vitamin E, Sodium Formaldehyde Sulphoxlate, PVC Flex Film, Phenol review cases wherein Positive IM in POI for India, Positive IM in Post POI for Third Countries were determined and thus duties were extended

- x. Reference has been made to White Cement, Zinc Oxide from China wherein Negative IM in POI for India & third countries, Negative IM in post-POI for India Negative IM in third countries in post POI were determined and thus duties were revoked
- xi. Whenever the Designated Authority has found negative injury margin in these midterm reviews, the Designated Authority has examined as a matter of mandatory obligation under Rule 23(1)(a) whether the injury to the domestic industry is likely to recur or not in case the said antidumping duty is withdrawn.
- xii. CESTAT has held in the matter of Kothari Sugars & Chemicals Limited Versus Designated Authority that in a situation where weighted average injury margin is negative, the authority is required to consider the volume of exports which were below NIP. This decision is in the fresh investigation and has been applied in number of cases in sunset reviews. While this decision is in the context of injury margin, the same is required to be applied to price undercutting also
- xiii. The domestic industry submits that price underselling is entirely irrelevant for determining price attractiveness. There is no way exporters would consider the NIP of the domestic industry and determine whether the Indian market is attractive to them.
- xiv. Significant exports from each of the subject countries to a number of countries in the world are at such low prices that the resultant price undercutting is positive. There are significant unutilized capacities in subject countries. This clearly establishes likelihood of injury.
- xv. Price attractiveness of Indian market shows that the exporters would divert their third countries exports and/or utilize their surplus capacities to export significant volumes to Indian market at lower prices
- xvi. Significant volume of exports from subject countries to other countries in the world are having positive dumping margin and price undercutting, diversion of these exports from third countries to India is imminent in view of price attractiveness of Indian market.
- xvii. Authority is required to undertake following tests for examining recurrence of injury, namely, whether price undercutting in respect of exports to India during POI is positive, whether price undercutting in respect of exports to India during post-POI is positive, whether price undercutting in respect of exports to various third countries during the POI is positive, whether price undercutting in respect of exports to various third countries during the post POI is positive and the volume of exports to third countries during POI which was at a price below (i) selling price of the domestic industry and (ii) export price to India and whether such volume of exports is significant having regard to Indian demand
- xviii. Exporters have not filed SSR questionnaire part II which requires information such as expansions including planned dates and capacity/production quantities involved, and the reasons for such change, the markets (countries) to which such additional capacity or production would be directed with evidences; Identification of export markets (other than India) developed as a result of the antidumping duty, significance of the existing ADD in terms of its effect on production capacity, production, home market shipments, exports to India and other markets, and inventories, changes expected with withdrawal of ADD. Further information is sought for production, exporter and other exporter sales in domestic market, demand, exports by the exporter and other exporter to third countries, for three years period and potential information for two years.

#### **Examination by the Authority**

87. The Authority examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Rules keeping in view the directions of the Hon'ble High Court of Gujarat in SCA 16426 to 16429 of 2016. The Hon'ble High Court, *inter alia*, has observed as under:

*Thus, though most of the factors which are required to be taken into consideration for the purpose of determination of injury, namely, increase in volume, increase in dumping, increase in margin of dumping and price undercutting are all positive and only price suppression and price depression are absent, the designated authority, instead of relying upon the said factors for the purpose of basing his decision as to whether or not to continue with the determinative measures, has placed reliance upon an irrelevant factor, viz., injury margin, which is not required to be taken into consideration while considering the likelihood aspect under clause (vii) of Annexure II to the rules. Clause (vii) of Annexure II to the rules provides for four factors which are required to be taken into consideration, viz.: (a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation; (b) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial*

*increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports; (c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and (d) inventories of the article being investigated.*

*Out of the above four factors, the designated authority has taken into consideration the factors prescribed under sub-clauses (a) and (c). However, insofar as sub-clause (c) is concerned, the designated authority has placed reliance upon incorrect facts, namely, though the price undercutting is positive, it has considered the same to be negative and drawn its conclusions accordingly.*

*Insofar as the factors prescribed under sub-clauses (b) and (d) of clause (vii) of Annexure II to the rules are concerned, it, however, has been contended on behalf of the respondents*

*that the designated authority has also considered those factors. In this regard, a perusal of the disclosure statement shows that while the designated authority has taken into consideration the above two factors, it is manifest that while doing so, it has taken into consideration incorrect facts, inasmuch as, instead of considering the capacity of production*

*of the exporters indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, as contemplated under sub-clause (b), it has taken into consideration the capacity of production of the domestic industry; and instead of taking into consideration the existence of inventories of the dumped imports that could meet any increase or future demand for the imports, has taken into consideration the inventories of the domestic industry. Evidently therefore, the designated authority has failed to follow the procedure laid down under clause (vii) of Annexure-II to the rules for the purpose of determination of threat of material injury in the manner prescribed thereunder.*

88. The Hon'ble Court further observed that

*Thus, the designated authority has based its findings on essential facts based upon the "injury margin" and "price underselling" as well as the fact that price undercutting is negative. As noted hereinabove, insofar as the injury margin and price underselling are concerned, the same are not relevant factors at the stage of examination of likelihood of injury in a disclosure statement. The designated authority was, therefore, not justified in placing reliance upon factors like "injury margin" and the "price underselling" while considering the question of likelihood of injury to the domestic industry in case of revocation of duties.*

89. In view of the above, while considering the likelihood aspect under clause (vii) of Annexure II to the Rules the Authority considered, inter alia, following factors as:

**Whether there is significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.**

90. The Authority notes that though there is overall increase in imports during the POI as compared to the base year of the injury period, out of three major producer subject countries (China, USA and EU) two countries namely, China and EU are showing declining trend in imports in the post-POI. Even on overall basis, (ie. all subject countries taken together) the increase in imports during the annualized post POI is only miniscule 3%. To have a more objective prospective analysis the import data for the years 2015-16 & 2016-17 was also obtained from DGCI&S by the Authority. The import from China, Kenya and Ukraine has registered constant decline during two years post-POI. In the post POI period the imports from EU & USA have first declined in 2015-16 and then increased again in 2016-17. So the requirement of significant increase in dumped imports into India is not really met with.

**Whether there is sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter**

91. This parameter for ascertaining the threat of material injury requires evaluation of existing surplus capacities and capacity addition, if any, to explore the possibility of diversion of disposable quantity to Indian market. Domestic industry has claimed that the producers in subject countries are already faced with significant surplus capacities. The domestic industry has furnished copies of I H S Chemical journal which provides information regarding Soda Ash manufacturing in the subject countries viz. existing capacity,



existing production , unutilized capacity and capacity expansion etc. The table below indicates that against Indian demand of approx. 3 million MT, the unutilized capacity in the subject countries is approx. 9.26 million MT capacity expansion ( undertaken already as well as upcoming ) is to the extent of 4.55 million MT. This data however is based on the premise that all Soda Ash manufacturing companies are to operate at 100% capacity utilization which may not actually be the case in reality. Some of the interested parties have even contended that the optimum capacity utilization of soda ash plants is approximately 80% only. The rule for determining likelihood analysis clearly prescribes that the analysis should be based on hard facts and not mere on conjectures or remote possibility. Moreover, the highest capacity addition (40 lac tonnes) i.e. nearly 88% of capacity addition is undertaken by China which has very low export orientation (8%) for this product. The Authority therefore notes that there does not appear to be threat of injury on account of imminent or substantial increase in the capacity of the exporters.

Particulars	UOM	Subject Countries					
		China	USA	EU	Pakistan	Iran	Total
Existing Capacity*	MT	319,61,000	125,48,000	91,22,750	4,90,000	7,25,000	548,46,750
Existing Production*	MT	252,76,000	116,57,000	76,49,750	4,01,250	5,93,750	455,77,750
Unutilized Capacity	MT	66,85,000	8,91,000	14,73,000	88,750	1,31,250	92,69,000
Capacity Expansion**	MT	40,00,000			2,50,000	3,00,000	45,50,000
Total Exports	MT	19,42,574	65,63,293	16,49,095			101,54,962
Export Orientation	MT	8%	56%	22%			22%
Export to India***	MT	1,29,466	87,833	67,823			2,85,122
FOB Export Price to India***	USD/MT	211.92	171.22	231.60			
Export to Third Countries-Volume							
Total***	MT	18,13,108	64,75,460	15,81,272			98,69,840
Price Lower than India***	MT	1,23,173	6,04,303	15,03,361			22,30,837
Price Higher than India***	MT	16,89,934	58,71,157	77,911			76,39,003
Export to Third Countries-Price							
Total***	USD/MT	217.51	198.39	194.31			
Price Lower than India***	USD/MT	210.51	152.05	187.77			
Price Higher than India***	USD/MT	218.02	203.16	320.50			

Source:

\*IHS Chemical Supplement September 2015

\*\* IHS Chemical Global

\*\*\* World Trade Atlas

92. **Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices**

On analysis of the data it is noted that selling price has increased consistently year on year and accordingly the price depression is clearly absent. There is also no clear trend in so far as price suppression effect on account of dumped import is concerned. While the increase in sales price in 2012-13 has not been in proportion to the rise in landed value of imports it has registered higher comparative growth in the subsequent year.

93. **Level of inventories**

The level of inventories available with the producers in subject countries could not be ascertained in view of lack of sufficient cooperation. Accordingly, this parameter for ascertaining threat of injury/likelihood of injury could not be examined by the Authority.

94. **Export Orientation**

Export orientation of all subject countries as a whole comes to 22%. While for USA the export orientation is as high as 56% it is as low as 8% in case of China

95. **Price attractiveness of Indian market**

The Authority notes that the landed value of imports from the subject countries as a whole is lower than selling price of the domestic industry thus showing positive price undercutting during POI as well as post POI. Further, WTA (World Trade Atlas) data establishes that exports from subject countries to a number of other countries have been found at a price lower than the export price from these countries to India. The volume of such exports is 2.23 Million MT amounting to 72.42% of existing demand in India. However, to conclude that on revocation of anti-dumping duty the volume of such low-priced exports would get diverted to the Indian market would be too far-fetched. Such analysis can throw misleading results if the low volume export transaction has been made to India at a relatively higher price. Then the price is related to the grade of the product as well. Moreover, it is not so easy to switch the market just on the possibility of a hike in export price by few notches on account of withdrawal of anti-dumping duty. So, this analysis on this criterion is full of conjectures and subjectivity.

**S. POST DISCLOSURE COMMENTS**

96. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. Additional submissions have been analysed as under:

**Submissions made by the Applicant and Other Interested Parties**

97. The submissions made by the applicant and other interested parties domestic industry have been summarized as below:
- i. Gujarat HC remanded the matter on limited points; no new facts should be entertained at this belated stage. Rule 16 proof of AD Rules does not envisage submission of any new information or evidence. Thus proceeding is not in accordance with observations of Gujarat HC.
  - ii. The oral hearing on 24/4/17 can't be said to be effective because interested parties were not provided with relevant data/information relied upon by the DA for arriving at the basic facts under consideration. The World Trade Atlas/IHS data which has been relied upon has not been provided. Not providing the data is in contravention of basic requirement of law and principle of natural justice.
  - iii. Documents on record do not support the observation of the DA regarding new capacities of DI. DA should provide documents relating to Capacity enhancement, when the information relating to capacity enhancement was brought to DA's Notice.
  - iv. If data was available before first disclosure the authority ought to inform interested parties earlier, but if same has been submitted at a later stage, it amounts to new information hence it can't be injected in the present statement
  - v. There is no injury to DI from the dumped imports as they themselves admitted
  - vi. Price underselling may not be the decisive factor for likelihood but it is still essential ingredient to decide injury and must be analysed
  - vii. Authority has backtracked from its previous stance in the earlier disclosure comments. Mere export orientation of the producers is not sufficient to prove that there will be dumped imports in the domestic market; it is dependent on other factors as well

- viii. The Authority has incorrectly shifted the onus on the exporters to prove that there has been no change in production capacity, instead of asking the applicants to prove that there has been an increase in production capacity.
- ix. The Authority has deviated from previous disclosure statement where it said that the Landed Value of Imports was above NIP in the Indian market. However they have changed their stance, without any justification, to state that landed value as a whole from subject countries is lower than domestic selling price.
- x. China and USA are doing most of the exports at prices above Indian export prices. Thus the prices are not at all attractive for the producers in subject countries
- xi. Prices from subject countries to third countries are more or less in same band.
- xii. Combined analysis of subject countries with other countries attracting ADD is without authority of law. Causal link to be done for subject countries only. Combined analysis gives perverse results
- xiii. Authority failed to note the decrease in quantum of imports from subject countries, rather relying on combined imports from all ADD attracting countries
- xiv. Authority has changed its stance from previous investigations where status as DI was denied on the ground of relation with importer/exporter. Here applicant is importer hence should be denied status as DI
- xv. With regard to correctness of the information, failure of the domestic producers to provide correct information cannot be brushed aside on ground that verification had subsequently taken place.
- xvi. Correct information ought to be provided to interested parties. Exporter response has been rejected on grounds of clerical mistake, improper address etc. in previous instances, why is a different approach being taken in the present case
- xvii. The data relied upon by the Hon'ble Designated Authority is outdated since it is for the post-POI period which is two years ago.
- xviii. There has been a sizeable decrease in imports from USA, China and Ukraine in the most recent period as per IHS data  
Lack of disposable capacity in various subject countries clearly indicates that there is no likelihood of increasing imports from these countries.
- xix. In fact as per IHS, the local demand constitutes a dominant proportion of the local production in China and EU (two of the biggest producers of Soda Ash), whereby there is no likelihood of increased imports.
- xx. The capacity utilization as per the data provided in the disclosure statement indicates that capacity utilization in subject countries is around 80-85%. However, though there are unutilized capacities in the subject countries, these can't be classified as 'freely disposable capacities'.
- xxi. Historical data sourced from IHS clearly shows that Soda Ash plants operate at optimal levels with capacities of 80-85%;
- xxii. Capacity utilization in the subject countries is already at optimal or near-optimal levels i.e. around 80-85% as per HIS;
- xxiii. Even the domestic industry (which has admitted it is not injured) is operating at a capacity utilization of about 83-84% in the POI and post-POI period
- xxiv. As per IHS there is substantial demand for the product under consideration in the subject countries as well as other export destinations (other than India) whereby these markets can readily absorb the increased exports;
- xxv. Particularly in two of the largest producing countries i.e. China and EU – the local demand is already a very major proportion of the local production (well over 90% in both countries) and the trend is expected to continue for the next 2-3 years
- xxvi. Upon examining the historical expansions in capacity since 1990 to 2015, it is seen that the average rate of increase for capacities has been 3.43% per annum. The capacity expansion identified in the disclosure statement (4.5 million MT) is expected to be rolled out over the next 3-4 years i.e. at an average growth rate of 2-3%, which is very much in line with historical trends in demand and capacity.
- xxvii. Indian prices being higher than third country prices implies there is no likelihood of dumping
- xxviii. Although the exports to countries at price lower than India have taken place, the price of these exports is USD 210.51 – which is only 1.41 USD/MT less than the price to India i.e. the difference between prices is less than 1%.
- xxix. It seems highly unlikely that Chinese exporters will change their channel of sales and divert all these quantities to India for a mere 0.5% increase in price.
- xxx. As per the IHS Global Soda Ash Supplement (February 2017 issue), the Indian market presently accounts for barely 2% of China's exports.

- xxxi. Further even those exports are declining, with a 17% decrease in Chinese exports to all sources over 2016. This is largely due to the fact that the domestic demand in China is currently over 90% of the domestic production, and the scenario is projected to remain the same over the next 2-3 years. Therefore, there is no likelihood of imports to India from China. In fact, China has even had to import some soda ash from USA to fulfill its growing domestic demand.
- xxxii. As per recent updates to the same data (IHS Supplementary report), it seems as though India now accounts for only about 1% of US exporters.
- xxxiii. Upon comparing the sales to India and exports to countries with prices higher than India the ratio is approximately 98:2 in terms of quantity.
- xxxiv. Even if the sales to countries with prices below India are to be redirected to more price-attractive markets, they would be divided in the same ratio, which would imply that only about 12,000 MT are likely to be directed to India – which is clearly too insignificant to be considered a threat.
- xxxv. As per IHS the main focus of US based producers in recent periods has been its domestic market and certain select export markets such as Mexico, China, Thailand and Vietnam.
- xxxvi. Expected capacity expansion in US is only about 90,000 MT, which is miniscule compared to both – the Indian demand as well as USA's overall capacity.
- xxxvii. The capacity in USA presently is about 13,000,000 MT, which is already outstripped by local demand as per IHS. This implies that the 90,000 MT capacity expansion would be a less-than 1% increase.
- xxxviii. Prices from EU to India (as per the disclosure statement) are USD 231.60/MT whereas the price to countries with prices lower than India is USD 187.77/MT. Even adding the AD Duty rate of 9.17 USD/MT to the price of 187.77, the resultant figure would be about 196.84 USD/MT. In other words, even with the present anti-dumping duty in force, India should have been a very price-attractive market for EU based producers since they could easily have absorbed the AD duty in their prices and still sold at a higher price than USD 187.77/MT. However, despite being such a price attractive market (with present AD duties), India constitutes only 4% of the export markets for EU. IHS Global Soda Ash Supplement reports that local demand in the EU already constitutes well over 90% of local production, and this pattern is expected to remain unchanged for the next 2-3 years. Therefore, there is no likelihood of imports to India from EU.
- xxxix. There appears to be no data or analysis in the disclosure statement for exports from Kenya, Ukraine, Iran and Pakistan.
- xl. However, seeing the lack of likelihood for other countries (examined above), it may be sustainably speculated that likelihood of injury from these countries would also be insignificant.
- xli. In fact, for Kenya, it is well established fact that there is now only one active plant in the country, whereby their exports are likely to be highly curtailed.
- xlii. The Petitioner revised its data with respect to the non-injurious price, therefore the Authority may have considered the Cost Accounting Record to calculate the cost of production since the PUC falls under the Cost Accounting Record.
- xlili. Initiation of SSR investigation raises serious questions on the fairness in which the present MTR is now being conducted by the Authority.
- xliv. The said initiation is loosely subjected to the outcome of this MTR. However, it appears that the Authority has made up its mind to reverse its own earlier finding of no likelihood of injury else it would not have reached to any prima facie view on the SSR application filed by the domestic industry.
- xlvi. The Authority did not do the needful to complete the investigation in 60 days as directed by the High Court and now acted in a haste to initiate the SSR by citing certain technicalities which is highly tilted towards the interest of the domestic industry and have no judicious logic behind it.
- xlvi. There has not been any injury caused to the domestic industry on account of exports by Olympia neither in the POI nor in the post POI period. Also, there is no likelihood of injury with the price at which exports are made as it is achieving very moderate prices for the subject goods in Pakistan and there is a robust demand situation for the subject goods in Pakistan. The high domestic realisations may be showing positive dumping margins in Olympia's case but such dumping margin did not have any effect on the Indian industry.
- xlvi. The level of increase in profits and overall performance of the domestic industry during the entire injury period and POI and also post POI period conclusively shows that there is not even an iota of chance that the injury is likely to continue or recur if the current duties are withdrawn.
- xlvi. The anti- dumping duties on soda ash are being misused by the Soda Ash producers in India to resort to excessive profiteering.

- xlix. The positive dumping margin found has no bearing on the performance of the domestic industry and such positive dumping margin does not vitiate the absence of likelihood of injury.
  - 1. Performance of the domestic industry has been extremely strong on all injury parameters in the entire injury period and also in the POI of present MTR and a similar trend followed in the post POI period as well. Even in original case the domestic industry was being able to sell at price higher than the NIP.
  - li. The mandate of the remand back do not permit perusal of a fresh set of data and a decision has to be taken on what is there in the file of the Authority already particularly when such data is being relied upon without even disclosing such reports in its entirety.
  - lii. Some selected and sporadic pages from “IHS Chemical-Global Soda Ash cannot be relied upon to conclude on a crucial parameter like ‘likelihood’. Interested parties cannot provide their rebuttals until the complete report is provided
  - liii. In fact the domestic industry had relied upon some pages from the same report in their written submissions and it was pointed out by us in our rejoinder submission that the very report contradicts the claims of domestic industry in certain other pages of the report.
  - liv. The 9 pages document placed in the public file have the source of the report provided in the header of the document and month of the publication on the footer except page number 7 and 8 [information about Turkey etc]. It appears like the page is manufactured. The report appears to be of a time after completion of the investigation.
  - lv. WTA data relied upon by the Authority is also not provided to us.
  - lvi. Likelihood examination in case of Pakistan should be based on cooperating producers’ data and not based on some baseless reports
  - lvii. There is no such excess volume or surplus capacities which will be diverted to India in the event of revocation of duty. The demand supply situation of the product in Pakistan and also in the world is well balanced and no country is under any such pressure to sell the Soda Ash under a lower price than what it is getting now
  - lviii. When the rule does not state that the likelihood should be examined as per the principles of Annexure II para (vii), the Authority adopting such principles directly is not understood.
  - lix. Marginally positive price undercutting do not suggest any likelihood of injury with the given state of extremely high levels of profit. The positive price undercutting is the result of extremely high price increases carried out by the domestic industry by misusing the AD duties on Soda Ash
  - lx. Certain exporters have participated in the present investigation and wherever there has been participation, the likelihood examination should be based on the data collected from such cooperation exporters and the Authority should not adopt facts available merely.
  - lxi. Scope restricted to the decision in judgment of the Gujarat High Court. Matter remanded back to complete investigation and issue final finding in 60 days. Considering 7 days for receipt of order from high court still the time frame has lapsed.
  - lxii. Most of the observations on procedural part. Even if 4 factors for threat to material injury is taken into account the industry still not suffering injury
  - lxiii. Price undercutting analysis is irrelevant in cases where there is no price suppression and depression of the domestic industry. Prices has not been impacted by the exports from the subject countries imports from the subject countries are not causing a negative effect on the prices of the DI.
  - lxiv. The normal value for the European Union, Iran and Untied States has been determined on the basis of average prices during the POI as published in IHS Chemical. The Authority has failed to provide the figures of the IHS Chemical prices that have been used.
  - lxv. Although the volume of imports from the subject countries has increased, the same is purely for the reason that the domestic industry is incapable of meeting the rising demand
  - lxvi. The United States has no plans for capacity expansion in the future and further nearly all its exports have been at prices above those to India. The data is an indication therefore that there is no reason to consider that there is a likelihood of increase in imports from the United States
  - lxvii. The exporters from the European Union have no plans for capacity expansion. Further, exports from the European Union have been at prices as high as USD 320.50 per MT and further in the post-POI period the prices from European Union have not been undercutting the prices of the domestic industry

- lxviii. China's export orientation is merely 8% and further that nearly all its exports to third countries have been at prices above those exported to India
- lxix. Merely the presence of an export orientation is not an indication of the fact that imports will increase to India if anti-dumping duties are withdrawn.
- lxx. If the duty is removed on imports of the subject goods, the exporters will only increase their prices further. As there is a demand supply gap present in the Indian market, there is no reason for the exporters to not capitalize on the rising demand as their customer base is already prepared to pay these higher prices.

#### **Submission made by the Domestic Industry**

98. The submissions made by the domestic industry have been summarized as below:

- i. The Designated Authority is requested to first decide the preliminary objection raised as to jurisdiction to carry midterm review without evidence of likelihood of injury
- ii. The onus to prove absence of continued injury and no likelihood of recurrence of injury to the domestic industry is onto the applicant before the Designated Authority. The said onus is not onto the domestic industry
- iii. The selling price of the domestic industry should be compared with the landed price of imports only after adding the transportation costs as transportation cost forms a very substantial portion of the cost of production.
- iv. The principles of fair comparison demand that the domestic price is compared with import price at the same level of trade. While such level of trade may normally be ex-port vs. ex-factory level, there is no reason to believe that the level of trade is required to be invariably kept at ex-factory level as far as domestic industry is concerned.
- v. India's position before the WTO, which clearly supports the contentions of the domestic industry that the comparison of the imported product price be made with the domestic industry price as close as possible to the point of consumption.
- vi. There is significant increase in dumped imports during POI and post POI.
- vii. If ADD are withdrawn, the imports shall have significant suppressing or depressing effect on the prices of the domestic industry in the market.
- viii. There are significant exports from the subject countries to a number of countries globally where the prices are materially below the Indian prices. Further, the combined volume of these exports is much higher than the Indian demand for the PUC. The exporters are holding significant surplus and unutilized capacities and are therefore likely to enhance their exports significantly in the event of cessation of present anti-dumping duties
- ix. In a situation, where the duties have had a desired effect, there is sufficient evidence of likelihood of recurrence of injury and thus the Authority needs to extend the duties as imposed. It is a settled position of the Directorate that when there is no injury past duties, as imposed, are extended. Reference is made to investigation on Polypropylene, Zinc Oxide, Potassium carbonate from Korea, Caustic Soda from Taiwan, and Ductile Iron Pipes from China etc.
- x. Authority has initiated SSR investigation which shows that the Authority found prima facie evidence of likelihood of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty after considering the application for a period subsequent to the POI considered in the present mid-term review investigation. This fact itself shows that there is likelihood of recurrence of injury in the event of premature withdrawal of anti-dumping duty.

#### **Examination by the Authority**

99. Submissions made by the interested parties have been examined as under:

- i. As regards the submission that WTA and IHS data has not been provided and no new facts can be brought in, it is noted that no new facts have been entertained by the authority at this stage. The domestic industry has merely repeated their earlier submissions/information in their present post hearing written submissions. Information on exports from the exporting countries to various countries as per customs data of the exporting countries were provided by the domestic industry during the course of original review investigations. The Authority has merely used World Trade Atlas data to cross verify correctness of the claims made by the domestic industry. As regards disclosure of this WTA data to interested parties, it is clarified that WTA data is not a public domain information and is accessible to Govt. of India under an agreement signed with an

international data compiling agency. This agreement with the agency prohibits Govt. of India from circulating this information to any interested party and public at large. The Authority has used this information only for cross verification of the claims of the domestic industry from its own sources. The domestic industry has adopted customs data of the exporting countries in order to establish their claim of likelihood. The authority has co-related these customs data adopted by the domestic industry with world trade atlas and has found that the data corroborates. Thus, WTA data in the form of third countries' exports has in a way already been made available by the domestic industry in the form of customs data of the exporting countries. Merely because sources are different it does not mean that the information has not been disclosed to the interested parties.

- ii. As regards the argument that documents on record do not support the observation of the Designated Authority regarding new capacities of domestic industry, the Authority notes that the claims of capacity enhancement and related documents were provided by the domestic industry from the beginning of the investigation. Further, the capacities added by the domestic industry or the expenditure made towards it have not been considered in the present Findings.
- iii. As regards the contention that prices from subject countries to third countries are more or less in same band, the Authority notes that the investigation however has shown difference in prices from exporting countries to various countries. Table at para 91 above demonstrates that.
- iv. As regards the argument that price underselling should have been examined, the Authority notes that having determined no injury to the domestic industry as also admitted by the domestic industry itself, the Authority has, in view of the order issued by the Hon'ble Gujarat High Court, not determined price underselling.
- v. As regards the argument that the Authority has backtracked from the previous findings, the Authority notes that the previous findings have been quashed by the High Court of Gujarat and is non-existent now. Thus any reference to the previous findings holds no ground. Moreover, no conclusion has been reached at the disclosure stage and therefore it was premature on the part of interested parties to make any observation in this regard.
- vi. As regards the argument that causal link analysis should be done for subject countries only, the Authority notes that the causal link has been done for the subject countries only.
- vii. As regards the argument that selected and sporadic pages from "IHS Chemical-Global Soda Ash cannot be relied upon and that the pages submitted by the domestic industry on likelihood appears to be manufactured, the Authority notes these documents were placed in the public file and opposing parties had ample opportunity to question the authenticity of these documents with evidence.
- viii. As regards the argument that the rule does not state that the likelihood should be examined as per the principles of Annexure II para (vii), the Authority notes that there is no set principles for determining likelihood of dumping and injury. However, the Authority has been applying these provisions for determination of likelihood of injury in review cases. The decision of the Gujarat High Court clearly states that the threat parameters laid down under the law are to be applied for likelihood examination. Further, the Authority has not restricted its analysis only on the basis of these parameters but has also examined other injury parameters brought out by the interested parties for examination of likelihood of injury to the domestic industry.
- ix. As regards the argument that initiation of sunset review investigation raises doubts on the fairness of the Authority, it is noted that the sunset review investigation has been initiated in view of the order of the Supreme Court in the matter of Union of India vs Kumho Petrochemicals holding that any one-year extension of antidumping duty after the expiry of existing antidumping duty is illegal. Since there was still time for issuance of final findings of the present mid-term review investigation and the existing anti-dumping duty was about to lapse, it was considered appropriate to initiate the sunset review investigation subject to the outcome of the present investigation.
- x. As regards the argument that the likelihood examination should be based on the data collected from cooperative exporters, it is noted that no information have been provided by such cooperating exporters on likelihood of injury and therefore the Authority has considered the best information available with the Authority.
- xiii. As regards the argument that there is no likelihood of injury with respect to cooperating exporters, the Authority notes that the likelihood analysis is not based on individual exporters. Rather, the same is country specific.
- xi. As regards the argument that the profits made by the domestic industry itself shows no likelihood of injury, the Authority notes that as already evidenced above, there is no likelihood of recurrence of injury.

- xii. As regards absence of disposable capacities in various subject countries, The authority notes that the domestic consumption in China and European is indeed quite significant. The Authority further notes that the highest capacity addition (40 lac MT i.e. nearly 88% of capacity addition) is undertaken by China which has very low export orientation (8%) for this product. The Authority therefore notes that there does not appear to be threat of injury on account of imminent or substantial increase in the capacity of the exporters.

### **CONCLUSIONS**

100. The Authority notes that the present investigation being a midterm review investigation, there should be evidence of likelihood of injury to the domestic industry in order to warrant continuation of duties. The relevant rule for determination of threat of injury/likelihood of injury in Annexure II (vii) of the Indian Anti-Dumping Rules states that “A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent”
101. The Authority on detailed scrutiny of facts has come to the conclusion that (i) No definite or conclusive trend is noticeable in respect of rate of increase of dumped imports. (ii) There is no depressing or suppressing effect on domestic prices caused by the import, leave alone significant depressing or suppressing effect. (iii) No examination of the inventories of the product under consideration with the exporters was possible on account of unavailability of this information due to lack of cooperation from the exporters (iv) There seems apparent availability of disposable capacity with the exporting countries but this estimate that capacity addition in China ( a country which alone accounts for approx. 88% of capacity addition and has very low export orientation for this product ) will increase likelihood of dumped exports to India and that all the Soda Ash plants will operate at approx. 100% capacity utilisation is a bit too far fetched and based on unrealistic possibility rather than on verifiable concrete evidence available in the public domain.
102. In view of above the Authority concludes that there is no likelihood of recurrence of injury on revocation of duty and therefore the continuation of anti-dumping duty is no longer warranted.

### **RECOMMENDATIONS**

103. The Authority notes that the review investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link and likelihood of injury in terms of the AD Rules, the Authority does not recommend to continue the anti-dumping duty imposed earlier on imports of subject goods from the subject countries as recommended vide Notification No.14/17/2010-DGAD dated 17th February, 2012 and imposed by the Central Government vide Notification No. 34/2012- Customs (ADD) dated 3rd July, 2012.
104. Accordingly, the sunset-review initiated on 16<sup>th</sup> June, 2017 subject to the outcome of this Mid- Term Review will be rescinded and formal orders for the same will be issued separately. As in the present case, 5 years duty period expired on 3.7.2017, the discontinuation of anti-dumping duty under the present Mid-Term Review investigation is recommended with effect from 3.7.2017.
105. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority